हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 1978

खंड , अंक 11

अधिकृत विवरण

विषय सूचि

सोमवार, 13 मार्च, 1978

पृष्ठसंख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (11)
1

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे
गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (11)
43

विशेषाधिकार प्रश्न (11)
73

अनुदानों के लिए सरकारी मांगों पर चर्चा
तथा मतदान
(11)74—130

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सइन हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 14. 30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Ambala Hissar Road

***216. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the (State Highway) Ambala Hissar Road was completely damaged between Narwana and Kalayat, during recent floods ;

(b) whether the road as referred to in part (a) above has not been repaired so far, if so, the time by which it is likely to be repaired ;

(c) whether Government proposes to construct link roads linking Gurudwara Sahib at Damtan (Jind) with Punjab Territory, linking village Khardwal (Jind) with village Samain (Hissar), Dhabi Tek Singh with Rasidan and Mohal-Khera with Narwana in the Distt. of Jind ; and

(d) the District-wise number of link roads taken in hand from July to December, 1977 in the State ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : (a) No. However the damage was extensive.

(h) The road is under repairs and is likely to be made traffic worthy by June, 1978.

(c) Yes.

(d) A statement is placed on the Table of the House.

ANNEXURE—A

Statement showing number of roads taken in hand after the formation of Janata Government.

Sr. No.	Name of District	No. of roads which were al- ready in progress on 30-6-77 and on which the work continued after that date	No. of roads san- ctianed between 1-7-77 & 31-12-77	Total of columns 3 & 4
1.	Ambala	62	6	68
2.	Bhiwani	25	9	34
3.	Gurgaon	47	—	47
4.	Karnal	47	4	51

5.	Jind	16	4	20
6.	Mohindergarh	36	—	36
7.	Hissar	32	33	65
8.	Rohtak	9	1	10
9.	Sonepat	15	1	16
10.	Kurukshetra	77	5	82
11.	Sirsa	19	18	37
		385	81	466

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह बात उनके इल्म में है कि नरवाना और क्लायत के बीच पिछले 15 दिनों से रोड टैरफिक के लिए बन्द है, अगर है तो क्या सरकार लोगों की तकलीफ को देखते हुए ज्यादा लेबर लगाकर रोड को ठीक करवस्केकी कृपा करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जमीन की इरोजन की वजह से मिट्टी ज्यादा बह गई है । इस को रेज कर रहे हैं । यह ठीक है कि ट्रैफिक बन्द है, लेकिन इसको जून, 1978 से पहले ट्रैफिक–वर्दी कर दिया जाएगा ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने पार्ट (डी) का जवाब नही दिया है ।

Shri Verendar Singh : I have already said that the statement is laid on the table of the House.

Share of Electricity in Bhakra Nangal

***234. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the share of Haryana State in the supply of electricity from Bhakra Nangal respectively togetherwith the share in the Bhakra Management Board thereof and whether the share of electricity so received is being utilised properly, if not, the time by which the same is likely to be utilised properly; and

(b) whether Haryana will also get its share in Electricity from 'Mein Dam, if so, the percentage thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हरियाणा राज्य का भाखडा नंगल से पैदा होने वाली बिजली में जैसे एक तदर्थ प्रबन्ध है, कोमन पूल उपभोक्ताओं की मांग तथा राजस्थान राज्य का हिस्सा निकालने के बाद, 39.5 प्रतिशत हिस्सा है । भाखडा प्रबन्धक बोर्ड की परिसम्पत्ति तथा देयता को, राजस्थान के हिस्से को निकालने के बाद, पंजाब तथा हरियाणा में 60 : 40 क्रमशः के अनुपात में बांटा जाता है । हरियाणा को इस प्रकार जो बिजली मिलती है, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया है ।

स्वामी आदित्य वेश : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि मैनेज– मैट बोर्ड में जो हरियाणा

का शेयर है, उसको हरियाणा पूरी तरह से उपयोग नही कर पा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह गलत बात है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, सवाल के जवाब पार्ट (बी) में कहा है कि थीन डैम से बिजली के शेयर के बारे में गवर्नमैंट आफ इण्डिया से बातचीत चल रही है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इसके बारे में मीटिंग कब हुई और क्या उस मीटिंग में यह निर्णय लिया है कि हरियाणा का इतना शेयर निर्धारित है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पिछली मीटिंग तब हुई थी जब थीन डैम प्रोजैक्ट को एक्सीक्यूट करने की क्लीयरैस प्रधान मन्त्री जी ने दी थी और उस समय किसी भी स्टेट का कोई शेयर फिक्स नहीं किया गया था । न एड–हॉक बेसिज पर और न डिटर्मिनेशन के बेसिज पर । जब शेयर डिटर्मिन होगा तो हमारा केस रखा जाएगा और इससे पहले भी हमने कहा है कि इतना शेयर बनता है ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या मन्त्री महोदय बतांएगे कि हमारी गवर्नमैंट का क्या स्टैण्ड है, कितना शेयर मिलना चाहिए और कितना क्लेम किया है?

श्री शमशेर सिंह : शेयर की बात यू नही आई कि थीन डैम पिछले कई सालों से रुका हुआ था और इसके कारण कोस्ट कई गुणा बढ़ गई थी । इसलिए फिलहाल यत्र! सोचा गया कि

पिछली सरकार ने जो कौस्ट बढ । दी थी उसको क्लीयर किया जाए । जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट में एड–हाक बेसिज पर शेयर पर डिस्ट्रिव्यूटिड है, उसी के हिसाब से डिस्ट्रिब्यूशन कर ली जाएगी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मिनिस्टर साहब से मालूम करना चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब के ब्यान के मुताबिक क्या यह समझा जाए कि थीन डैम में सरकार अपना कोई हिस्सा नही डालना चाहती? अगर हरियाणा गवर्नमैंट शेयर करना चाहती है तौ वहू कितना शेयर मांगेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैने पहले अर्ज किया है कि शेयर का डिटर्मिनेशन इसमें नहीं है । जहां तक हरियाणा के क्लेम का ताल्लुक डेए! वह वही है जिसका री–आगेंनाइजेशन एक्ट में प्रोवीज्न है । उसी के हिसाब से हम अपना शेयर मागेंगे और वही हमारा स्टैण्ड है ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया है कि शेयर का कोई डिटर्मिनेशन नही किया –है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सैन्ट्रल गवर्नमैंट से क्लीयरैस हो गई, काम को एक्सीक्यूट करने के लिए, तो हरियाणा गवर्नमैंट ने क्यों ऐक्सैप्टैस दी है? क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि पार्टनर स्टेट्स ने कितने पानी की एक्सैप्टैस दी है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जब क्लयिरैस हुई थी, उस वक्त सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने पार्टनर स्टेट्स से शेयर के मामले मे कुछ नहीं मांगा था । जिस वक्त मांगेंगी, जैसे मैने अर्ज किया, स्टेट री–आर्गेनाईजेशन एक्ट के मुताबिक जो एसैट्स एंड लायबिलिटिज होंगी, हमारे शेयर के मुताबिक जो प्रोवीजन है, उसके मुताबिक शेयर करे we shall move according to that

स्वामी आदित्य वेश : कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में यह खबर छ पी थी कि थीं डैम ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू तुंड काश्मीर, राजस्थान और पंजाब का हिस्सा है लेकिन हरियाणा का कोई हिस्सा नही है । क्या यह बात सत्य है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : For correction of the hon'ble member

मैं उन्हें बताना चाहता हू कि राजस्थान का हिस्सा नही मांगा गया था । आपने गलत पढ़ा है । ऐसी कोई खबर नहीं आई, जिसमे यह कहा गया हो कि हरियाणा का थीन डैम में कोई शेयर नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि उन्होंने क्या मन बनाया है कि कितना हिस्सा क्लेम करना चाहिए?

श्री वीरेन्द्र सिंह : शेयर डिटर्मिन गवर्नमैंट आ फ इण्डिया ने इकट्ठे बैठ कर तय करना है और जो शेयर हमारा बनता है वह लिया जाएगा ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि थीन डैम का एक्सीक्यूशन वर्क कौन– सी गवर्नमैंट करेगी? क्या सब मिलकर करेंगे या कोई एक सरकार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : एक्सीक्यूट पंजाब स्टेट करेगी और उसका ज्वांयट कन्ट्रोल बोर्ड होगा । Chief Ministers or all the respective States and Irrigation and Power Ministers of all the States will be the members of that Board.

कंवर राम पाल सिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि री–आर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक 'जितना हिस्सा हिसाब से आता है, वह 'मिलेगा । क्या यह जरूरी है कि थीन डैम पर भी यह री–आगेंनाइजेटान एकट ही लागू होगा? री–आर्गेनाइजेशन एक्ट तो डिवीजन के लिए था, न कि आगे जो स्कीमें चलनी हैं, उन पर लागू होगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तक्सीम के लिए ही नहीं, इसमें एसैट्म एंड लायबिलिटीज की डिवीजन का हिसाब–किताब भी आता है, यहा भी यह लागू होता है ।

Incomplete Drains in the State

***291. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the time by which the incomplete drains are likely to be completed in the State ; and

(b) the time by which the digging work at the

Nigdhu drain in Nilokheri area is likely to be completed ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) The Incomplete drains in the state are likely to be completed by 30-6-78 except Pundri and Asan Drains which are expected to be completed by 30-6-79. This is the reply submitted by the department. But I have got certain reservations with regard to Bhambheva drain also.

(b) There is no drain named as Nigdhu drain. However, there is a depression named as such and the drain named as Pundri starting from that place is likely to be completed by 30-6-79.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, नीलोखेडीं ब्लाक में झंजाडी लिंक ड्रेन है । कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में प्रश्न पूछा था और जवाब दिया गया था कि वह ड़ेन पूरी कर दी गई है । परन्तु दो तारीख को बारिश हुई और कल परसों भी बारिश हुई जिसके कारण झंजाडी गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन पानी ये खड़ी हो गई और सारी फसल मर रही है । दूसरे गांव वालों ने जमीन यकसां कर ली और परिणाम स्वरुप इस गांव का सारा पानी रोक रखा है । क्या मन्त्री महोदय दोबारा इस ड्रेन को ठीक करने के लिए गौर करेंगे, ताकि फसल खराब होने से बच सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक नही है । मैं माननीय सदस्य कें नोटिस में लाoंगा कि उसकी इनक्वायरी करवाई जाएगी ।

चौधरी संत कंवर : मन्त्री महोदय ने सवाल के पार्ट (क) के उत्तर में कहा है कि पुंडरी और आसन ड्रेनों को छोड़कर सब अधूरी ड्रेने 30– 6– 1 978 तक पूरी कर ली जाएगी । क्वैश्चन आवर में चार दिन पहले मन्त्रीँ जी ने इसी हाउस में ब्यान दिया था कि कुलताना ड्रेन इस साल नही, अगले साल पूरी होगी यानी. 1 979 में पूरी होगी लेकिन इसका जिक्र इस सवाल में क्यो नही आया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरे लायक दोस्त ने सवाल पढ़ नही है, सवाल किया था जो ड्रेन्ज इन–कम्प्लीट है! उनके बारे में बताए । पहले को चालू थी but still remain in complete. Kultana drain may be one of the drains which is yet to be started.

कंवर राम पाल' सिंह : स्पीकर साहब । (क) भाग के उत्तर में मन्त्री. जी ने दो तीन डेरज के नाम बताए हैं जो इस साल पूरी होगी । मैने भी एक्य सवाल किया था जो पुट नही हो सका लेकिन उसका जिक्र मैंने बजट स्पी च में किया था । इसी तरहे पुक्य ' पइं ?' ड्रेन करनाल में भी है । उसके बारे में डिपार्टमैंट ने जवाब दिया है कि वह कम्पलीट है लेकिन वास्तव में वह कम्पलीट नहीं है । क्या मन्त्री. महोदय को उसके बारे में जानकारी हद कि जब वह कम्पलीट नही है तो डिपार्टमैंट ने उसका जवाब ऐ सा क्यों दिया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . स्पीकर साहब उसकी इनक्वायरी करवाई जाएगी ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आसन ड्रेन को क्यों छोड़ दिया गया जबकि वह सब–से इम्पाटैंट और दूखदाई ड़ेन है और कई गांवों को तबाह करती है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : छोड़ा नही गया । वह 3 0– 6– 1 978 तक कम्पलीट नहीं हो पाएगी ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब सारे हरियाणा की ड्रेनज के बारे में कहां कहा जाता है तो जगाधरी तहसील की पंजौरा ड्रेन के बारे में क्यों नहीं कहा जाता? उसके कारण अम्बाला जगाधरी रोड पर डिप्रैशन है । वहां काज–वे भी बना हु आ है । आज से दो साल पहले बरसात के अन्दर वहां टैर फिक भी बन्द हो जाती थी । वहां एक नौजवान की मृत्यु भी हो गई थी । उसका मोटर साईकिल वहां पै दल चलते हुए उलट गया था । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वह ड्रेन भी कभी कम्पलीट होगी और जो काज–वे हैं, उस पर कभी पुल बनेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इसके लिए अलग नोटिस की आवश्यकता है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि पुण्ड्री ड्रेन अगले साल बनेगी । क्या वे बताएंगे कि उसे इस साल न बनाने में क्या रुकावट है ?

Shri Verendar Singh : Sir, Pundri drain has already been completed from RD 0.35 i.e. from outfall and to village Jamba on left side of Karnal-Kaithal pucca Road. The work in the reach RD 35-55 (Village Dussain) is in progress and is likely to be completed during this year subject to availability of funds etc. स्पीकर साहब, इसके इस साल कम्पलीट न होने के बारे में अर्ज यह है कि यह ड्रेन बड़ी लम्बी है, इस पर दो करोड़ रुपए की लागत आएगी और इतना पैसा फिलहाल अवेलेबल नही है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कही ऐसा तो नही है कि सारे हरियाणा की ड्रेनज मुकम्मल होकर बादली में इकट्ठी हो जाए और जमुना मे पानी ले जाने का प्रबन्ध न हो, जिससे वहां के लोग बरबाद हो जाएं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे हरियाणा की ड्रेनज बादली में इकट्ठी नहीं की जाएगी ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, अभी यहां बताया गया कि चूंकि कुल्ताना ट्रेन का काम शुरू नही हुआ हे इसलिए

उसका जिक्र यहां नहीं आया । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आसन ड्रेन, जिम पर अभी काम शुरू नही हुआ है, का नाम यहां आ सकता है तो कुल– ताना डेंरन का नाम क्यों नहीं आया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उसका कुछ पोर्शन बन गया होगा ।

चौधरी संत कंवर : बिल्कुल नही बना ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : जरूर बना होगा ।

चौधरी गंगा राम : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आसन ड्रेन को रिठाल तक ऐक्सटैंड किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन ड्रेन पर कुल कितने गांव आते हैं, यह ज्यो– ग्राफिया मुझे याद नहीं । इसके लिए मुझे सैप्रेट नोटिस चाहिए ।

श्री भले राम : क्या मन्त्री जी अलग अलग ड्रेन के बारे में न बताकर यह बताएंगे कि ये सारी ड्रेनज कब तक पूरी होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 38 करोड़ रुपया सारे फ्लड को कन्ट्रोल करने के लिए चाहिए । यह पैसा जब होगा तब कम्पलीट हो जाएंगी ।

श्री रघुनाथ गोयल : स्पीकर साहब, हमारे यहां मानस तीर्थ से एक लिंक ड्रेन चलकर बाबा लदाना से होते हुए पाडला

वाली सड़क से कुतेपुर कैथल ड्रेन में गिरती है । इस पर दो पुल भी बने हुए हैं । यह ड्रेन केवल पांच किलोमीटर लम्बी है । यह कुछ खुदी हुई है, कुछ ऐमरजैसी में लोगों ने बन्द कर दी हे । मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जितना एरिया हरियाणा का है उस में अधिक से अधिक जितने एरिया को फ्लड से बचा सकेंगे, बचाएंगे ।

श्री मूल चन्द मंगला : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि श्रमदान से जोड्रेनज बनाई जा रही हैं, क्या वे इस रेनी सीजन से पहले पूरी हो जाएगी? दूसरी बात यह कि पलवल क्षेत्र में जो 11 ड्रेनज यू. पी. गवर्नमैंट की हैं, जो इस समय मिड़ी से इग्री होने की वजह से काम नहीं कर रही हैं और इलाके को बड़ी तकलीफ दे रही है, उनके बारे में यूपी. गवर्नमैंट पर प्रैशर डाला जाएगा कि वह उनकी खुदाई करे? यदि उनकी खुदाई यू. पी. गवर्नमैंट न करे तो क्या हमारी सरकार करेगी ताकि लोगों का नुक्सान न हो ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो ड्रेनज श्रमदान से बनाई गई है या बन रही है, वे छोटी' छोटी. लिंक ड्रेनज हैं और उनका 3 0— 6— 1978 तक जरूर पूरा कर लिया जाएगा ।

अगले सवाल का जवाब यह है किं जिन उत्तर प्रदेश की ड्रेनज का जिक्र मंगला साहब ने किया ीऐ उनको मै एग्जामिन करवा लेता हू । अगर उनकी जिम्मेदारी हमारी हुई और उनसे हमें ज्यादा नुक्सान होता होगा नौ हम जरूर साफ करवाएंगे ।

कैप्टन मांगे राम : स्पीकर साहब, तहसील झज्जर के हल्के में रत्नथल गांव ऐसा है जिसके तीनों तरफ दो–दो किलोमीटर पानी है । वही हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के 70 घर गाय से बाहर झोपड़ियों में पड़े है । इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मौनसून से पहले वहां के पानी को ड्रेन आउट किया जाएगा और इन लोगों की रीहैव्लीटेशन का कोई प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हरियाणा के अलग अलग गांवों के बारे में बताना बड़ा मुश्किल लेकिन इस हाउस के माननीय सदस्यो को मै यह विश्वास दिलाना चाहता हु कि हम हरियाणा को अगली बार फ्लड से बचाने की इन्तहा कोशिश करेंगे ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, मन्त्री' जी ने अभी कहा सारे हरियाणा में नहरों को खोदने का प्रोग्राम है । क्या मन्त्री जी' बताएने हइए मेरे हलका रतिया मे रंगोई नाला को कब तक पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि वहां कोई पन्द्रह सोलह गांवों को नुक्सान होता है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : रंगोई नाला के बारे मैं मुख्य मन्त्री जी ने– स्पैसिफिक आदेश दिया था जब. ये टूर पर गए थे । वह एग्जामिन किया जा रहा है ।

चौधरी संत संवर : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगले साल हरियाणा को फ्लड से बचाने की कोशिश की जाएगी । पहले भी मन्त्री जी कई बार कह चुके हैं कि वैस्ट जुआ ड्रेन, कइनाली ड़ेन और बलियाना लिंक ड़ेन इस साल पूरी कर ली जाएगी । स्पीकर साहब, इन ड्रेनज के पूरा होने के बाद पानी नकफगढु नाला में जाएगा । जब तक नफजगढ नाले की एक्सटैंशन तीस हजार क्यूसिक्स तक नहीं होती, तब तक बाढ़ का इन्तजाम ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा । तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस नाले की एक्सटैंशन का काम इस साल हो जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, दिल्ली सरकार से इस बारे में बातचीत चल रही है ।

श्री गुलजार सिंह : स्पीकर साहब, कुछेक ड्रेनज ऐसी हैं जो पन्द्रह बीस साल पहले खुदाई गई थीं और वे चल रही थीं लेकिन लोगों ने ऐमरजैसी के दौरान उनको रद्द करके खेती. बाड़ी करनी शुरू कर दी । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि ऐसी कुछ ड्रेनज के बारे में, जिनसे लोगों को नुक्सान हो रहा है, कोई कार्यवाही की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या माननीय सदस्य सेम के नालों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हु? (विध्न)

श्री गुलजार सिंह : जी नहीं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर फ्लड की ड्रेनज ऐसी हैं तो नोटिस में लाएं, उस पर कार्यवाही की जाएगी ।

स्वामी अग्नि वेश : पुण्ड्री ड्रेन लगभग तीन चौथाई बन चुकी है और एक चौथाई बकाया रहती है, अगर समय पर उसको बना दिया जाये, तो कुरुक्षेत्र जिले में फ्लड से जो तबाही और नुक्सान होगा, उससे वह बच जायेगा और ज्यादा लाभदायक रहेगा । तो मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि थोड़ा–बहुत पैसा लगा कर अगर उसको पूरा कर दें तो राज्य को क्या दिक्कत है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : 3 0– 6– 1978 से पहले पु डरी ड्रेन के बनाए जाने की कुमीटमैंट नही की जा सकती ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब मेरा सवाल है, मुझे तो दो सप्लीमैंट्री करने दें ।

श्री अध्यक्ष : आपको दो सप्लीमैंट्री की इजाजत दे दी गई है ।

Complaint against an Ex-Managing Director, Central Co-operative Bank Ltd. Sonepat.

***352. Chaudhri Sant Kanwar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether the Govt. has received any complaint against an Ex-Managing Director, Central Co-operative Bank Sonepat for making illegal appointment of his relation and for making appointment of some peon and one driver in the Bank ; and

(b) whether any departmental enquiry was coducted in the matter and, if so, the action taken thereon ?

Minister for Irrigation and Power (Shri Verendar Singh) :

(a) Yes.

(b) Yes, A departmental enquiry was keld in the matter and the question of taking action against the officer concerned is under the consideration of Government.

चौधरी संत कंवर : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब वह अधिकारी दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, डिले क्यों की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह जांच मेरे तक नहीं पहुंची है । आखिरी हुक्म मैंने करना है ।

Posts of Assistants Filled in the Excise and Taxation Commissioner's Office

***306. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to State —

(a) the total number of posts of Assistants vacant in Excise and Taxation Commissioner's Office during the calendar years 1975 and 1976 ;

(b) the total number of posts of Assistants out of those referred to inpart (a) above were filled up through direct recruitment/transfer from other departments/offices/ex-cadres during the said years separately;

(c) the procedure followed in filling up the said posts and the total number of applications received through proper channel togetherwith the number of applicants considered and selected separately ;

(d) whether the compliance of Notification Nos. 523-3GS-70/2068, dated 28-1-1970 and No. GS.R.88/Const.-Art.309/73, dated 29-6-73, in respect of prior approval of the Subordinate Services Selection Board were made ; if so, the manner thereof ;

(e) the number of applications of the Development Department Office's employees were received and on what dates for which posts alongwith the names, educational and other qualifications period of service and designation of those applicants the procedure followed for each applicant to consider and appoint him against that post ;

(f) the reasons for ignoring the departmental clerks for promotion to the posts of Assistants ; and

(g) the number of representations against the

appointments on such posts were received from the effected clerks of the department and the action taken on them by the department ?

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

(a) Vacant posts of Assistants :—

1975	11
1976	8

1975	1976

(b) Posts filled --

(i) Through Direct Recruitment

(ii) Transfer from other Departments 2

1

(iii) Transfer from other offices i.e. District 5
Offices of the Excise and Taxation

Department

(iv) From Ex-cadre

(c) Statement (No.1) giving the requisite information is laid on the table of the House.

(d) No.

(c) Statement (No. II) giving the required information is laid on the table of the House.

(1) Statement (No.111) giving reasons for ignoring

departmental clerks is laid on the table of the house.

(g) 39 representations were received which were considered and rejected by the competent authority.

STATEMENT I

According to rule 7(b) of the Punjab Excise and Taxation Commissioner's Office (State Services Class III) Rules, 1954, the posts of the Assistsnts are to be filled in the following manner :-

7(b) In the case of Assistant (including Reader) and Stenographers :

(i) By promotion from among senior clerks (including Nazir) or Stenographer in the Services; or

(ii) By selection from among officials already in Government Service ; or

(iii) By direct appointment.

Provided that 25 % of vacancies in the case of Assistants shall be filled by direct appointment.

2. 120 applications as per details given below received in the office of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana for the posts of Assistants :—

Applications received through proper channel		Number of applications considered		Number of candidates selected
Other	Distt.	Other	Distt.	Other District

Deptts.	offices of E&T Deptt.	deptt s.	offices of E&T Deptt.	Deptt s.	Offices of E&T D eptt.
82	38	82	38	3	9

STATEMENT II

Only three applications of the Development Department were received in this office. The details of these applications are given below :—

Name of the applicant	Date of receipt of applica tion	Name of post applied for	Educat ional qualifi ca ttons	Period of Service	Designa- tion of the post held
She. Onkar Singh	2841-73	Any suit- able	Inter- mediat e	10 years	Accounts Clerk
2. She, Prem Sarup	15-5.74	Asstt.	B.A.	10 years	Stenotypist
3. Sh. Ajmer Singh	15-7-74	Do.	Matric	10 years	Assistant

It was decided to appoint the officials of the other departments by transfer under rule 7(b)(ii) of the Punjab Excise and Taxation Commissioner's Office (State Service Class III) Rules, 1954, as already mentioned in Statement I.

STATEMENT III

The Clerks who were at that time due for promotion on the basis of seniority were not experienced as they had even less than three years service at their credit. So it was felt that if any more clerks were promoted from the Head Office strength, the office will have to consider officials who had not completed even three years of service at their credit. On the other hand, the officials of the District Offices and other Departments appeared to be more seasoned since they had longer service at their credit. However, the departmental clerks who were working in the District Offices were considered and promoted to the posts of Assistants in the Head Office.

श्री देवेन्द्र शर्मा : जनाब इसमें मेरे दो तीन सप्लीमैंट्री बनेंगे । पहला तो यह है कि 'बी' पार्ट में बताया गया है कि दूसरे डिपार्टमैंट से तीन और डिस्ट्रिक्ट आफिसिज से 9 आदमी लिए गए हैं यानी कुल 12 आदमी लिए हैं तो मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

कि क्या इनमें कोई शिडयूल कास्ट्स या एक्स–सर्विसमैन के लिए कोटा रिजर्व है, अगर है, तो क्या उनमें से कोई लिया गया हे?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : जहां तक रिजर्व कोटे का ताल्लुक है । स्पीकर साहब वहां पर एक्साईज ऐंड टैक्सेशन डिपार्टमैट के रूल्ज के मुताबिक कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री जी के नौलेज में यह बात है कि वहां पर उनकी दरखास्तें थी और उनको न लिया गया हो?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : मैंने जवाब में बताया है कि टोटल एप्लीकैन्ट्स 120 थे । उनमें से मैरिट के मुताबिक सिलैक्शन कर लिया गया ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : इन 120 एप्लीकैन्ट्स के अलावा क्या और एम्पलाइज भी थे, जिनकी हैड–आफिस से दरखास्तें आई थीं और जिनके बारे में कहा गया है कि इसके अलावा और आई ही नहीं?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : मैंने सवाल के जवाब में कहा है कि ट्रांसफर कॉम अदर आफिसिज यानी जितनी दरखास्तें हैड आफिस में आई हैं उनमें से पांच सिलैक्ट हुए हैं, यह तो नहीं कि उनमें से सिलैक्ट ही नहीं हुए ।

श्री मूल चन्द जैन : मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि हरिजनों के लिए इस विभाग में कोई कोटा मुकरर्र नहीं है, तो क्या मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि हरिजंनों की दरखास्तें ही नहीं थी या कोई रूल ही ऐसा बन गया है जिसमें कोई कोटा मुकर्रर नहीं है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : जहां तक दरखास्तों का ताल्लुक है, यह तो सैप्रेट कुवेश्चन है कि किस–किस की दरखास्तें आई हैं । आप नोटिस दें मैं बता दूंगा । एक्साईज डिपार्टमैंट के

जो रूल्ज हैं, उनमें उनका रूल 7 पढ़कर सुनादेता हूं—वैसे रूल सात के अन्दर ऑफिशियल के लिए परमोशन है डायरैक्ट कोटा नही है । रूल सात इस तरह से है –

According to rule 7(b) of the Punjab Excise and Taxation Commissioner's Office (State Services Class III) Rules, 1954, the posts of the Assistants are to be filled in the following manner-

(i) By promotion from among senior clerks (including Nazir) or Stenographer in the services; or

(ii) By selection from among officials already in Government Services or;

(iii) By direct appointment.

इसके अलावा 20 परसैन्ट वैकेन्सीज डायरैक्ट अप्वांयटमैंट के लिए रिजर्व हैं । यहां पर इस रूल में कोई स्पष्ट नहीं है कि हरिजनों का या दूसरे आदमियों का कोटा मुकर्रर है ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरिजनों के लिए जो रिजर्वेशन बनती है जैसे चार पर एक बनती है तो क्या कारण है कि चौथी पोस्ट ही नहीं निकालते? हर दफ्तर में तीन ही पोस्ट निकालते हैं, इसका क्या कारण है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : इस बारे में कोई शिकायत मेरे नोटिस में नहीं आई है । अगर कोई शिकायत

नोटिस में लाएंगे, तो जांच करा ली जाएगी । आप लिख कर दें, इनक्वायरी करवा लेंगे ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा सरकार ने कानून बना रखा है कि हरिजनों के लिए रिजर्वेशन है, बैकवर्ड और एक्स–सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन है तो क्या यह रूल इसको ओवर राइट करता है?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह जो रूल्ज बनाए हुए हैं, ये पुरानी सरकार के बनाए हुए है । अब हम इनको कन्सिडर कर सकते हैं, लेकिन इनको अधिकार नहीं है । हम कन्सिडर करेंगे ।

चौधरी गया लाल : मन्त्री महोदय ने अभी यहां बताया है कि मैरिट से पांच आदमी लिए हैं परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि हरिजनों के लिए भी. कोई रिजर्व सीट है या नहीं, उनमें से कोई भी क्यों नही लिया गया, क्या कारण है? क्या उनकी रिजर्वेशन खत्म हो गई?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : मैंने बताया है कि पुराने रूल्ज के मुताबिक कोटा रिजर्व नहीं था । अभी हाउस के सामने मैंने रूल सात पढ़ कर भी सुनाया है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एस.एस.एस. बोर्ड की अप्रूवल क्यों नहीं ली गई, जब कि डिपार्टमेंट

के रूल 12 में यह कहा गया है कि उसकी परमिशन लेनी जरूरी है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ है वह सारा हाउस जानता हे कि पुरानी सरकार के अन्दर रूल्ज वगैरह की कोई खास मान्यता नही थी कहां पर इन्होंने यानी पिछली सरकार ने गलती कर रखी है । अब सरकार ने अश्योरैस दी है कि सरकार कानूनी कार्यवाही करेगी ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो आपका कोटा पूरा नहीं हो रहा, वह सन् 197 8–79 में पूरा करेंगे क्योंकि आपने वैकेन्सीज भी निकाली हें?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि कोटे वाली कोई बात ही नहीं है, उस रूल के मुताबिक कोटा फिक्स ही नही है इसलिए कोटा पूरा करने वाली कोई बात हीं नही है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बताया हे कि पिछली सरकार गलती करती रही है तो मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या यह भी सरकार तरफदारी को छोड्कर एस.एस.एस. बोर्ड से पोस्ट्स को फिलअप करेंगे?

चौधरी सतवीर सिह मलिक : अध्यक्ष महोदय पिछली सरकार की गलती को हम दोहराते नहीं । हरियाणा में जनता

पार्टी की सरकार के टाईम पर जो भी काम होगा, वह कानून के मुताबिक होगा ।

श्री शेर सिंह : मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि रूल 7 के तहत कोई रिजर्वेशन नहीं है । तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह रूल सात इसी डिपार्टमैंट में लागू होता है या सभी डिपार्टमैंट्स में यह लागू होता है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : मैंने यहां एक्साइज ऐंड टैक्सेशन विभाग का रूल बढा है, दूसरे विभागों का जिक्र नहीं किया हुऐ ।

चौधरी लाल सिंह : मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पहले जो लोग हरिजनों के नाम से नौकरी ले लेते थे, क्या उनके खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगीं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री फतेह चन्द विज : जैसा कि पिछली सरकार ने वायदे किए थे कि हरिजनों के लिए कोटे निर्धारित हैं लेकिन उन्होंने रूल्ज में प्रोविजन नही रखा तो क्या सरकार इस बात की इनक्वायरी कराएगी कि मिनिस्टरों ने वायदे करके भी रूल्ज में अमैंडमैंट क्यों नहीं की?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा था कि पहले जब ये रूल्ज बने, तो उस वक्त भी हरिजन ही

इस विभाग का मिनिस्टर था, लेकिन किसी की गलती से रह गया । सरकार इस रूल में अमैंडमैंट करने के लिए कन्सिडर करेगी ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि इसकी इनक्वायरी कराई जाएगी । तो मैं वजीर साहब से हाउस में यह अश्योरैस चाहूंगा कि इनक्वायरी कराए जाने के बाद जो लोग सफर हुए हैं इफैक्टिड/डग्नोर्ड हुए हैं, उन लोगों को दोबारा बहाल और मदद करने पर विचार करेंगे?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : मेरे दोस्त ने नाम नहीं बताया कि यह जुल्म किस–किस के साथ हुआ है ।

Superannuation Age

***357. Chaudhri Partap Singh Thakran :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government intends to reduce the superannuation age of Government Servants from 58 to 55 yeats ; and

(b) Whether this reduction in superannuation age will solve the Unemployment problem to some extent ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार के विचार में इस प्रकार का प्रस्ताव बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी इलाज नहीं है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चीफ मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि जब सरकार यह मानती आयी है कि रिटायरमैंट की उम्र 55 साल होनी चाहिये, क्योंकि रिटायरमैंट से तीन साल पहले जो हम उनको एक्सटैंशन देते हैं, उनसे हमारे नौजवान लड़कों का नम्बर ही नहीं आता, क्या चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पर विचार करेंगे कि यहं तीन साल की एक्सटैशन न दी जाया करे?

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, 28 मार्च, 1963 के बाद 58 सालकी रिटायरमैंट की उम्र हुई है । अब सरकार का इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि इसे कम किया जाये क्योंकि सरकार यह समझती है कि इस तरीके से करने से एक की बेरोजगारी. दूर होगी. तो जो वहां से निकाला जायेगा, वह बेरोजगार हो जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृ पा करेंगे, जैसे कि उन्होंने यह बताया कि इससे बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी, अगर 58 की बजाय 55 साल की रिटायरमैंट की उम्र कर दी जाये तो 1 5, 000 से ज्यादा आदमी एक ही साल में रिटायर होते हैं और इससे 1 5, 000 और लोगों को रोजगार मिल सकता है, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आयु 58 से 55 करने पर विचार करेंगे?

चौधरी देवी लाल :इन आंकड़ों के मुताबक उतने ही बेकार भी तो हो जायेंगे ।

Protective Schemes for Floods

***372 Shri Mool Chand Jab :** Will the Minister for Revenue be pleased to state -

(a) whether any flood protection schemes for this year have been approved by the flood control board ; if so, the details of such schemes be laid on the Table of the House ; and

(b) whether it is a fact that in the absence of Jamuna river protective works on the side of Haryana, the said river has gradually pushed to Haryana side posing imminent danger to village Mirzapur, Tamsa, Jalalpur, Pathergarh and Bilaspur in Tehsil Panipat ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) Yes. The details of these schemes are placed on the Table of the House,

(b) No. However on account of construction of flood protection works on left bank by U.P., the river has a tendency to deflect the current towards Haryana Side. River protection works are undertaken on Haryana side to provide safety to village abadies and agricultural lands. The scales of these protection works has, however, to be limited to the availability of funds. There is no imminent danger to villages Thamcabad Jalalpur, Pathergarh and Bilaspur. However protection works will be undertaken to provide safety to village Mirzapur for averting imminent danger.

Details of Flood Protection and Drainage Schemes Approved by the Haryana State Flood Control Board on 30-1-1978 at Jhajjar.

(Rupees in lakhs)

1		2
(a)	Ambala District	
(i)	Protection to village Murad Nagar	2.97
(ii)	Protection to villages in Naraingarh Tehsil	11.35
(iii)	Protection to village Pyarewala	2.44
(iv)	Protection to village Dari-Ujjal	1.03
(v)	Protection to Miyanpur-Chichi Majra by constructing stone studs	1.80
(vi)	Protection to village Nizampur Galvari	1.41
(vii)	Protection to village Islam Nagar	1.22
(viii)	Protection to village Bhagwali	1.15
(ix)	Protection to village Kurali by constructing 3 No stone stud and revetment	1.86
(x)	Protecting Old Babyal Bund	2.70
(xi)	Protection to village Kot Kachhwa	0.79
(xii)	Protection to village Tharwa Majri in reach R D	0.70

17600-19000 RMB Tangri D/S G.T. Road	
(xiii) Protection to village Bichpuri-Laliani in reach RD32-35 RMB Tangri	1.84
(xiv) Constructing RMB Tangri D/S Narwana Branch RD 8 to 37000	18.52
(xv) Protection to village Bhog Pur	1.71
(xvi) Constructing Ring Bund around village Godhaula	0.46
(xvii) Construction of Chutang Nallah from RD 0 to 5000	2.33
(xviii) Protection to village Mahaiuddinpur	0.37
(xix) Protection to village Jaitpur	0.48
(xx) Protection to village Bangera	0.60
(xxi) Protection to village Musfatkurd	1.34
(xxii) Protection to village Muqaibpur	0.85
(xxiii) Protection to village Hafizpur & Bakarwala	0.93
(xxiv) Protection to village Raipur Dhamouli	1.62
(xxv) Protection to village Kamalpur Tepu	5.23
(xxvi) Linking depressions on drain along right bank of M.I.L. from R.D. 90000 to 112000	4.20

(xxvii) Protection to village Ratour.	2.34
(b) Kurukshetra District	
Protection to R.M.B. Markanda near village Ram Nagar	3.65
(ii) Raising and Strengthening guide bund from RD. o 8720 along River Markanda U/S G.T. Road	1.57
Protecting Kalsana Bund	2.90
(iv) Constructing bull headed stud opposite R.D. 9500 L.M.B. Markanda U/S Jalbehra	0.33
(v) Protecting LMB Markanda U/S Jalbehra Head Opposite RD 14000-15000	2.15
(vi) Raising and Strengthening of LMB Markanda D/S Jalbehra Head from RD 32000 to 55000	3.81
(vii) Pitching LMB Markanda D/S Jalbehra Head opposite RD 12900-43170	0.91
(viii) Protection to LMB Markanda opposite RD 53600-54300 D/S Jalbehra Head by providing pitching	2.05
(ix) Constructing Thana Link drain RD 0-45000 outfalling into Kaithal Drain at RD 1,52,000/Right	12.33
(x) Constructing Khurana Link drain from RD o-2000 outfalling into Kaithal Drain at RD 1,20,000/Right	4.52
(xi) Constructing Magho Majri Link drain from RD0 to	7.47

25000 outfalling into Kaithal Drain at RD 111900/Right

(xii) Constructing Baba-Ladana Link drain from RD 0-52000 outfalling into Kaithal Drain at RD 48000/Right — 15.25

(xiii) Constructing Pundri Drain RD 0-1,80,000 outfalling into Sirsa Branch at RD 278538/Left — 243.84

(xiv) Constructing Habri Drain RD 0-58,000 outfalling into Pundri Drain at RD 99000/Right — 15.26

(xv) Constructing Kasan Drain from RD 0-82000 outfalling into Pundri Drain at RD 59000/Right — 29.32

(xvi) Constructing Ring Bund around 13 marooned villages of District Kurukshetra — 12.52

(xvii) Constructing Alhar Link Drain from RD 0-63500 out-falling in Dhanaura Escape — Deferred

viii) Protection to village Gumthala — 11.17

(c) Sirsa District

Extending Left Marginal Bund U/S Ottu Weir

(ii) Constructing Syphon cum inlets in Ghaggar bund D/S Ottu Weir — 7.00

(d) Hissar District

(i)	Dhanipal Link drain	1.95
(ii)	Retrogressing of Sirhind Choe	1.85
(iii)	Constructing Ring bund around 7 villages of District Hissar	6.74
(e) Jind District		
(i)	Constructing Ring bund around 26 No. marooned villages of District Jind	25.84
	Constructing Pump House at Amritsar	1.47
)	Constructing Pump House at village Ujjana	2.52
(iv)	Constructing Bhana Brahmana Link drain from RD 0-32000 outfalling into Sirsa Branch at RD 300 Left	24.09
(v)	Constructing Kalayat Kapil Muni Link drain from RD 0-11000 outfalling into Sirsa Branch at RD 283/ Left	4.71
(vi)	Constructing Dumerkha Link drain from RD 0-51000 with Pump House at RD 7900/Left of Barwala Branch	With drawn
(vii)	Constructing Ratauli Link drain from RD 0-15000 with Pump House of 25 Cs. outfalling in Hansi Branch at RD 124800/Right	8.09
ii)	Constructing Dhatrath Link drain from RD 0 to 14000 outfalling into Hansi Branch at RD 151800/ Right	6.41

(ix)	Constructing Rajana Link drain outfalling into Hansi Branch at RD 121650/Left	3.48
(x)	Constructing Lochap Link drain outfalling into Hansi Branch at RD 165000/Left	5.14
(xi)	Constructing Sharfabad Link drain from RD 0-25000 e outfalling at RD 84000/L of Bhambewa Drain	7.01
(f)	Karnal District	
(i)	Protection to village Chowgawan	9.58
(ii)	Protection to village Chandraen Ka Gaon	9.11
(iii)	Protection to village Zapti Chhapra	2.81
(iv)	Protection to village Nagli	5.42
(v)	Protection to village Jaroli	3.49
(vi)	Protection to villages Nabipur and Khirajpur	4.66
(vii)	Protection to villages Manglora and Dalora	8.13
(viii)	Protection to village Pir-Baroli	15.05
(ix)	Protection to village Balhera	9.44
(x)	Protection to villages Tamsabad, Nawada and Sanauli	5.81
(xi)	Protection to village Nanhera	10.44
(xii)	Protection to villages Admi, Jalmana and Mirzapur	7.60
(xiii)	Protection to village Goela Khurd	7.75
(xiv)	Bringing Drain No.2 to its designed section in reach	With

	RD 163000 to 204000	drawn
(xv)	Protection to village Hathwala Rakshera	10.26
(xvi)	Constructing Marginal Embankment from village Hathwala Rakshera to village Simbalgarh	3.37
(xvii)	Renovating Indri Drain from RD -0-138000 With	drawn
(xviii)	Constructing Ring Bund and peripherial drain around village Assandh	46.95
(xix)	Remodelling Tributary Drain No. I from RD 0-78000 outfalling into Nai Nallah drain at RD 71700/L	24.26
(g)	Sonepat District	
(i)	Constructing Nizampur Link drain from RD 0-4000 with a Pump House at RD 32500/R of Sunder Sub Branch	1.25
(ii)	Constructing a Pumping station near village Dhanana at RD 21925 /R Kahnaur Distributary	4.12
(iii)	Pitching of Chhapra drain RD 29000-34000	5.52
(iv)	Protection to village Kathura	1.37
(v)	Remodelling of Tributary Drain No. 3 from RD 0-161000	16.32
(vi)	Raising and strengthening of Right bank of Tributary	0.52

Drain No. 4 from RD 0 to 10400	
(vii) Remodelling of Dobetta drain from RD 0-68500 outfalling in Drain No. 8 at RD 18700 including provision of pitching in Head reach	10.43
(viii) Constructing Kahni Link drainfrom RD 0-28000 outfalling at RD 42500/L Jassina drain	10.91
(ix) Pitching of Rithal Pump House L-drain from RD 0-4200	1.74
(x) Pitching of Rithal Link drain from RD 0-12400	16.50
(xi) Remodelling of East Jua drain from RD 0-89500 outfalling into Drain No. 6 at RD 11000/Right	20.48
(xii) Remodelling Khanda drain from RD 23000-59000 outfalling at RD 110000 of Diversion Drain No. 8	8.76
(xiii) Protection to village Jajjal Complex	2.34
(xiv) Protection to village Jhundpur and Tanda	5.81
(xv) Protection to Village Jagdishpur	5.75
(xvi) Constructing Pumping Stations combined with Link drains in 5 No. low lying villages in Sonepat District	2.23
(xvii) Constructing Ring bunds around 17 No. marooned	16.90

villages of District Sonepat

(h) Rohtak District

(i) Pitching of Jasia Drain from RD 23000 to 26000	2.56
(ii) Constructing Khadwali Link drain from RD 0-22300 outfalling at RD 78500/R of Drain No. 8	4.25
(iii) Constructing Samar Gopalpur Drain from RD 0-285001 outfalling into Drain No. 8 at RD 106000	2.31
(iv) Constructing Bakheta, drain from RD 0-42000 out-falling into Diversion Drain No. 8 at RD 136000/Right	18.16
(v) Increasing capacity of Bohar Drain from RD 0-12500 with additional pumping at RD 14800-R of Bhalaut sub Branch	6.63
(vi) Pitching of Kanheli drain from RD 4000/6000	**5.16**
(vii) Remodelling of Pakasma from RD- 0-77500 outfalling into West Jua Drain at RD 38400/Left	31.47
(viii) Remodelling of Gandhra Drain from RD 0-51500 out-falling into Pakasma Drain at RD 35400-Right	12.66
(ix) Remodelling of West Jua Drain RD 0 -70500 out-falling into Mangeshpur Drain at RD 43600/Left	84.71
(x) Remodelling Sankhoul Link Drain from RD 0-1850 outfalling into West Jua Drain at RD 12300/Right	2.97
(xi) Constructing Kultana Hhudani Bhupania Drain	265.55

from RD 40-176000 with its Link drains	
(xii) Constructing Gurnothi Link Drain from RD 0-36000 outfalling into Drain No. 8	10.56
iii) Constructing Ring Bund for Jhajjar Town	**87.17**
(xiv) Constructing Bund along the boundary of village Kunjla-Karnoud from RD 0-3200	2.08
(xv) Raising and strengthening banks of Bhindawas Link Drain from RD 0-19500	68.12
(xvi) Utilisation of stored flood water in Bhindawas Lake during Rabi Season	296.50
(xvii) Raising and strengthening of Left bank of outfall drain No. 8 from RD 0-130730	137.57
(xviii) Constructing Pump Houses combined with link drains in No. 20 villages in Rohtak District	11.25
(xix) Construction of Ring bunds in 43 No. marooned villages of District Rohtak	42.99
(xx) Constructing ring bund around 22 No. marooned villages of Tehsil Jhajjar and Rohtak of District Rohtak	22.34
(j) Mohindergarh District	
Protection to village Pali	1.89
(ii) Constructing Ring bunds and protection bund for 18 No. villages in Mohindergarh District	32.67

(k) Gurgaon District

(i)	Protection to village Basantpur	0.98
(ii)	Constructing Marginal embankment on the right side of river Yamuna Village Basantpur to Dadsia	11.78
(iii)	Protection to village Dadsia and Kadawali	7.26
(iv)	Raising plinth level of village Dadsia and constructing ring bund around village Kadawali	2.58
(v)	Providing protection to village Mohabatpur	1.37
(vi)	Protection to villages Manjhwali and Akbarpur	7.21
	Protection to village Gharasan	6.48
)	Protection to village Chandpur	0.88
	Protection to village Shahupura	0.35
	Protcction to village Duelepur	3.68
(xi)	Protection to villages Kushak, Tappa, Bilochpuri and Atwa	7.13
(xii)	Protection to villages Chhainsa and Lattipur	12.75
(xiii)	Protection to village Mohna	5.73
(xiv)	Protection to village Maksoodpur	0.91
(xv)	Protection to village Rajpur and Dostpur	5.29

(xvi) Protection to village Balai and Thantri	3.98
(xvii) Protection to village Prehladpur	3.62
(xviii) Protection to village Gurwari	3.44
(xix) Protection to village Phant Nagar	1.65
(xx) Protection to village Murtazabad	1.16
(xxi) Protection to villages Satika Nagla and Mohauli	3.15
(xxii) Constructing Ring bunds around 8 villages in Tehsil Gurgaon	15.64
(xxiii) Constructing Ring bund around village Harphala in Ballabgarh Tehsil	0.81
(xiv) Remodelling Nuh Drain from RD 0 to 104145	13.28
(xxv) Remodelling Chandeni Drain from RD 0 to 43650	8.08
(xxvi) Constructing Aluka Link Drain from RD 0 to 18000 outfalling into approach Channel of Gurgaon Canal at RD 95000 tail.	5.21
(xxvii) Constructing Ring bunds around 15 villages in Nuh Tehsil	25.17
(xxviii) Constructing Ring bunds around villages Khaika Rosar and Manpur in Tehsil Nuh	3.26

(xxix) Pitching Kot Bahin Link Drain from R.D 10,000-13500	6.33
(xxx) Constructing Ring bunds around villages in Tehsil Palwal	4.36
(xxxi) Constructing V.R. Bridge on Banchari Link Drain at RD-2200	0.87
(xxxii) Providing Pumping stations at the outfalls of Siha Link Drain and Gudhrana Link Drains	4.12
(xxxiii) Constructing V.R. Bridge at RD 44000 and 61900 of Gaonchi Main Drain	9.25
(xxxiv) Constructing Ring bunds around villages Punhana, Marika Bichhore,Nai Aminabad and Bikti in Tehsil Ferozepur Jhirka	7.74
(xxxv) Constructing Ring bunds around 9 villages of Feroze-pur Jhirka Tehsil	20.81
(xxxvi) Constructing Ring bunds around 11 villages of Pataudi Sub-tehsil	26.17
(xxxvii) Raising and strengthening of Ring bunds around 5 No. villages of Patandi Sub-tehsil of Gurgaon District	3.85
(xxxviii) Protection to village Khalilpur	3.87
1. Constructing Pinana Farmana Link Drain from RD o-43500 outfalling into Diversion Drain No. 8 at RD 152500/Left	9.63

2. Constructing Talao Link Drain from RD o-21000, outfalling into outfall Drain No. 8 at RD 35000/L.	9.21
Deepening Gaunchi Main Drain from RD o-229500	185.94
Constructing Masani Barrage on Sahibi Nadi	1653.67
5. Scheme regarding flooding of area between Surethi and Beri Khas on either side of Drain No. 8	—
6. Restoration of land acquired for Lissara Nallah to the original Land Owners	—
Protection to village Bhuni	2.05
8. Remodelling of Manageshpur Drain from RD 345000 to 525000	20.38
9. Constructing small storage tanks created in depressions	19.50
10. Deepening of village tanks for flood moderation/ irrigation	Referred
II. Raising pond level of Ottu lake on Ghaggar River	529.27
Kotla Storage Project for irrigation	Withdrawn
Raising and Strengthening banks of Drain No. 8	10.00
Providing 8 No. embankments (Bunds) on Drain No. 8	5.00
Deepening of Diversion Drain No. 8 from RD 60,000 to 2,30,165	260.00

Constructing supplementary Bahadurgarh Drain	15.00
Pitching of Gaunchi Main Drain in Sloughy reaches	Referred
Storages along. Lift Canals	Referred
The scheme of Ujjina Diversion Drain already stands approved for Rs. 6.0 crores and in the minutes of the meeting it was approved for Rs. 12.0 crores.	
This item was also discussed in the 15th meeting of N.S.F.G. Board as a special item for Rs. 19.20 crores.	19.30

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि हमारा यू0 पी0 गवर्नमैंट के साथ एक मुआहिदा है कि हम जमुना के इधर कोई चीज बनायेगे तो हम उनसे इजाजत लेंगे और अगर वे जमुना के उधर कोई चीज बनायेंगे ते वे हम से इजाजत लेंगे, मैं मिनिस्टर साहब– से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यू 0 पी0 की सरकार ने जो यह बांध बनाया है, इसकी कोई इजाजत हरियाणा सरकार से ली थी या नही ली थी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : जब यह सरकार आयी तो, तो बांध मुक्म्कल था ।

श्री मूल चन्द जैन : मिनिस्टर साहब ने जो लिस्ट जवाब मैं दे रखी है, उसमें करनाल जिले में उन्होंने कई स्कीमो का

जिक्र 'किया है, क्या मैं उनसे यह जान सकता हं कि यह जो प्रोटैक्शन टू फलाना–फलाना विलेज लिखा हुआ है, इस में किस क्स्मि का प्रोटैक्शन वर्क किया जायेगा ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : बाबू जी, जो जमुना के साथ गांव है, वहां पर तो स्पर्ण ही बनते हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृ पा करेगे कि आपके डिपार्टमैंट वाले इंजीनियर्ज गांव वालों से भी सलाह लेंगे कि वहां पर स्पर्ज बनाने से काम चलेगा या बैक्स को स्ट्रैंथन करने से काम चलेगा? अगर स्पर वाली स्कीम से जो कि पिछले कई सालों से बेकार साबित हो रही है, गांव वाले न सहमत हों तो क्या आपका महकमा उसको तबदील करने को तैयार होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमने यह महकमे को इंस्ट्रक्शन्ज दी हुई हैं that they must associate with them, बाद में अब फिर यह इंस्टूक्शन्ज जारी कर देंगे that the villagers must be associated.

श्री लछमन सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि उन्होंने फ्लड कन्ट्रोल करने के लिये क्या–क्या उपाय किये हैं जिससे कि कहा–जहा पर अब की बार फ्लड आये हैं, उनको आगे को इस मुसीबत का सामना न करना पड़े?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमने फ्लड कन्ट्रोल करने के लिए एक मास्टर प्लान 138 करोड़ रुपये का तैयार किया है । यह

फेजड प्रोग्राम में हैं । यह 138 करोड़ रुपये की रकम एकदम से तो प्रोवाइड नहीं की जा सकती लेकिन जो ज्यादा फ्लड अफैक्टिड एरियाज हैं, हम वहां पर यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्कीम पर काम करके वहां पर लोगों को फलड से बचाया जाय ।

राव राम नारायण : मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़गांव जिला जोकि खादर का एरिया है, में जमुना के उस पार यू 0 पी0 की सरकार ने जो एक बांध बना लिया है, उस की वजह से हमारे इ लाके के बहुत से गांवों को डेन्जर हो गया है, यही नहीं इस वजह से पिछली बार उन–कों बहुत तकलीफ हुई और वहां से उठ कर उनको वहां से भागना पड़ा, क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि उस बांध के पानी को इधर गांवों में आने से रोकने के लिके कोई इन्तजाम करने जा रहे हैं, अगर हां, तो कब तक वह काम हो जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमने जो स्टेटमैंट आन दी टेबल आफ दी हा उस ले कर रखी है, उस के अन्दर इसका जिक्र किया हुआ है ।

श्री लछमन सिंह : मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि 1 38 करोड़ रुपये की स्कीम है और इनकी बात से यह जाहिर होता है कि शायद पैसे की कमी है । क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर इमीनैन्ट डेंजर तो नहीं है लेकिन अगर वहां पर वर्क शुरू न किया गया तो बहुत ज्यादा

डेंजर हो सकता है, जहां पर आगे तो फ्लड नही आया है लेकिय अब भी भी फ्लड आ सकता है तो क्या उन गांव के लिये भी कोई प्रोवीजन रखा गया है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तो बात ठीक है कि जहां पर फ्लड आये हैं वहां पर फिर से फ्लड आने का खतरा हो सकता है लेकिन जहां पर फ्लड आये ही नहीं वहां पर क्या खतरा हो सकता है । अव्वल मैं ऐसी त कोई सम्भावना ही नहीं है लेकिन फिर भी हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि फ्लड आये ही नहीं ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब की लिस्ट के पेज 7 आईटम नं 24 जोकि उजाना डाइवर्शन ड्रेन के बारे में है, उसके बारे में बताया है, मैं इस बारे में उनसे यह पूछना चाहूंगा कि इस ड्रेन की कितनी फाईनल कैपेसिटी होगी और यह स्कीम कब तक मुकम्मल हो जायेंगी? क्या यह इसी साल बरसात से पहले–पहले मुकम्मल हो जायेगी या अगले साल बरसात से पहने–पहले मुकम्मल हो जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उम्मीद है कि अगली बरसात से पहले–पहले 500 की कैपेसिटी की ड्रेन कम्पलीट हो जायेगी ।

कंवर राम पाल सिंह : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि क्या उनकी नौलेज में है कि जितने गांव इस सवाल में दिये गये हैं, उनके अलावा भी बहुत से ऐ से गांव हैं जहां पर फ्लड की वजह से गांव की जमीन का इरोजन हुआ और आबाथी

को भी भारी नुक्सान हुआ हए? क्या ऐसे गांवों के लिए भी मइकमें द्वारा काम शुरू किया जाना है, अगर हां तो कब तक किया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कुछ किया हुआ है और कुछ कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द मंगला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि उजीना ड्रेन कब तक मुकम्मल हो जायेगी? मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि उजीना ड्रेन पर जहां पर कि काम शुरू हए वहां पर 5 एक्स0 ई 0 एन 0 हैं जोकि फरीदाबाद के अन्दर बैठे हुए हैं । जहां पर काम हो रहा है, वह वहां से काफी दूर हैं. मैं समझता हूं कि एक होडल, एक नूह और एक पलवल इत्यादि इनका सैन्टर बनना चाहिए जिससे कि वैस्टेज न हो पाये । आप खुद ही देखिये 5 एक्स0 ई0 एन0 का खर्चा कितना रोज का है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सुझाव बहुत अच्छा है । इस पर गौर किया जायेगा ।

सरदार सुखदेव सिंह : स्पीकर साहब में आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि दीवाली वाले रोज. रोडी हल्के में चीफ मिनिस्टर साहब यह ए. लान करके आये थे कि यहां पर जो नहर है, उसको पक्की करने का इन्तजाम किया जायेगा, उनके उस आश्वासन को कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरे आनरेबल दोस्त नहर पक्की करने का सवाल पूछ रहे हैं जब कि मेन सवाल तो ड्रेन के बारे में है ।

श्री मूल' चन्द जैन : मंत्री महोदय ने मेरे एक सवाल के जवाब में यह बताया है कि इन प्रोटैक्शन वर्क्स में गांव के लोगों की सलाह अवश्य ली जायेगी । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड ने मान लीजिये स्पर्ज लगाने की स्कीम मन्जूर कर दी और गांव वाले यह कहें कि बैक्स को मजबूत करो और यहां पर स्वर नहीं लगने चाहियें, तो क्या आपका महकमा या आपके इंजीनियर्ज उनकी इस बात को मान लेंगे या वह गाव वालों की सलाह को इग्नोर करके काम शुरू रखेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : बाबू जी, यह तो हिपोथैटीकल क्वैश्चन है । अगर वह गांव वालों की सलाह नहीं ले रहे हैं तो बताइये । अगर किसी को कोई ग्रीवैन्स है तो वह हमारे नोटिस में लायें, हम उस पर जरूर गौर करेंगे ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब., हमारा जो. क्रोड़ों रुपयों का बजट चल रहा है, इसमें जो ड्रेनज और नहरे बन रही है, इसमें पिछली सरकार के अन्दर यह होता था कि ठेकेदार लोग सीमेन्ट बेच देते थे, अनख भी वही हो रहा है । सीमेंट बिक रहा है । क्या मन्त्री महोदय इस बात का इन्तजाम करेंगे कि ठेकेदार लोग सीमेन्ट चोरी से बेच न पायें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अभी तो मिट्टी का काम हो रहा है । जब कोई पुल बनेगा तब ही तो सीमेन्ट की जरूरत पड़ेगी ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मंत्री महोदय बताने की कूपा करेंगे कि तहसील पानीपत के मिर्जापुर, तमसा जलालपुर और पत्थरगढ़ तथा बिलासपुर गावों को बाढ़ आने से पहले स्पर वगैरह बनाकर बचाने की कोई स्कीम विचाराधीन है या नही?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पहला गांव है बिलासपुर इस पर 4. 12 लाख रुपया खर्चहो चुका है । दूसरा गांव है मिर्जापुर इस 'पर 2. 14 लाख रुपया खर्च हो गया है, 10. 77 लाख और खर्च मारना है । अगला गांव है पत्थरगढ इस पर 0. 08 लाख रुपया खर्च' हो गया है, 5. 68 लाख खर्च करना है । अगला गांव है तमसाबाद, इस सर 4. 95 लाख खर्च' हो चुका है, 9. 14 लाख रुपया और खर्च करना है ।

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया कि कुछ जगहों पर काम शुरु हो चुका है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंने कि किन–किन जगहों पर जमुना पर काम शुरू हो चुका है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह कठिन काम है ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, ड्रेन नम्बर 8 और ड्रेन नम्बर 6 सब से बड़ी ड्रेने हैं और ये दोनों ड्रेने' गोहाना सब–डिविजन से पैदा हुई है और उसमें से गुजरती हैं । क्या

मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इनकी पानी लेने की कैपेसिटी दुगनी की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इस सदन के पटल पर यह जो स्टेटमैंट रखा गया है इसका फायदा ही क्या हुआ अगर फिर भी सवाल पूछे जाते हैं जबकि सारी इंफरमेशन उसमें प्रोवाइड की गई है । आगे से में जवाब पढ़ दिया करूंगा । जब में जवाब देता हूं तो कहते हैं कि सारा घन्टा ही लग जाएगा ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने सवाल के 'बी' भाग के उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश द्वारा बाईं तरफ बाढ़ सुरक्षा कार्य करने के कारण दरिया के बहाव का रुख हरियाणा की ओर हो जाने केकारण हरियाणा के गांवों को खतरा पैदा हो गया..

श्री वीरेन्द्र सिंह : – मेने तो ऐसा नहीं कहा है.....

चौधरी संत कंवर : आपने 'बी' के उत्तर में कहा है उत्तर प्रदेश द्वारा बांई तरफ बाढ़ सुरक्षा कार्य करने के कारण दरिया के बहाव का रुख हरियाणा की ओर हो गया । गांवों की आबादी तथा कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा हेतु हरियाणा की तरफ दरिया से सुरक्षा के कार्य किये गए हैं । इन सुरक्षा कार्यो को धन की उपलब्धि अनुसार सीमित किया गया है । स्पीकर साहब, इस साल जमुना के बहाव के काट की वजह से जो जमीन जमुना में बहकर चली गई और जो फसल खराब हुई उनसे काफी नुक्सान

हुआ है । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्पर बनाने का खर्चा जमीन बहने तथा फसल के नुक्सान होने से कम नही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : नुक्सान जरूर ज्यादा होगा लेकिन जितना धन उपलब्ध है उसी के हिसाब से काम चलाया जाएगा ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या मन्त्री महोदय बताने कभई कृपा करेंगे बिय यू 0 पी 0 गवर्नमैंट ने बांध पर जो स्पर बनाए है, वे कब बने थे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर बनते ही वहां गया था, वह वहां पर खड़ा था । It was already there.

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, लास्ट पेज. पर आइटम नम्बर 24 पर उजीना ड्रेन का जिक्र है । इसके बारे में एन 0 एस0 एफ 0 जी 0 बोर्ड की पद्रहवीं मीटिंग में डिस्कशन हुई थी और 19. 30 लाख रुपए क्रूा प्लान भी तैयार हो चुका है । क्या मन्त्री महोदय बताने की खग करेंगे कि इस ड्रेन की अल्टीमेट कैपेसिटी क्या होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, डस ड्रेन की टोटल कैपेसिटी 3,400 क्यूसिक की होगी ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या नारायण गढ़ तहसील का सरकर द्वारा कोई सर्वे हु आ था और क्या इस साल वहां कोई स्पर लगाया जाएगा?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री लहरी सिंह मेराह : स्पीकर साहब, जमु ना पर जो स्पर बनाएं जाते हैं उसके लिए जो काम अब शुरू होना चाहिए वह बरसात के दिनों में जब बाढ़ आई होती है तब शुरू होता है जिससे वह सामान पानी में बह जाता है और काफी नुक्सान होता है । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे वह काम बाढ के आने से पहले शुरू करने का सरकार का विचार है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : बरसात के समय तो पिछली सरकार शुरू किया करती थी हमने तो बरसात से पहले ही शुरू कर दिया और श्रमदान भी शुरु केर दिया है ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृ पा करेंगे कि जो नई लिंक ड्रेन बनाने की योजना है उसके लिए जमीन एक्वायर क्ओं नहीं कर ली जाती ताकि बारिश होने से पहले ही किसान खुद खोद लें?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां जमीनें एक्वायर करनी है वह एक्वायर कर रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने सकीमें बनाने के बारे में बताया हस लेकिन कुछ इलाकों में ऐसे हालात पैदा हो गए थे जैसे कुरुक्षेत्र और नीलोखेडी के इलाके में 300 किल्ले गेहू की फसल में पानी भर गया और वहां पर काफी नुक्सान हुआ और अफररूरों ने हमारी काफी मदद की । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कीम बनने के बाद अगर कहीं नए हालात पैदा हो गए है तो क्या कहा के बारे में दुबारा विचार किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्कीम बनने के बाद अगर नए हालात पैदा हो गए हैं तो जरूर विचार किया जायेगा ।

Quantum of Water

***438. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the quantum of water released in Loharu Canal in the months of October and November during the Rabi Crop of 1976 and October and November, 1977, separately ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Quantum of water released in Loharu Canal in October and November, 1976 is 12331 cusecs days and 3559 cusecs days respectively. Quantum of water released in October and November 1977 is 7052 cusecs days and 1153 cusecs days respectively, The supply in drain No. 8, which is feeder for Loharu Canal, was kept low to permit removal of flood water from low lying areas. However, 9936 cusecs was supplied during December, 1977 and 4374 cusecs during

January, 1978, as against Nil supply during December, 1976 and January, 1977.

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है अक्तुबर, 1976 में 1233 1 क्गूइसक डेज पानी दिया गया और अक्तूबर, 1977 में 7052 क्यूसिक डेज पानी लोहारू कैनाल को दिया गया । इस हिसाब से 5279 क्यूसिक डेज पानी अक्तूबर, 1977 में कम दिया गया । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या पानी कम देना भिवानी के साथ दुर्भावनाक नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, दुर्भावना तो कोई नहीं है । ड्रेन नम्बर आठ जिससे लोहारू नहर को पानी मिलता है, इस साल बाढ़ बहुत ज्यादा आने के कारण निचले केल से बाढ़' के पानी को निकालने के लिये ड्रेन जरूर आठ में जल की सप्लाई कम रखी गई । दिसम्बर 1 976 तथा जनवरी, 1 977 में लोहारू कैनाल को कोई पानी नही दिया गया इस कमी को दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 में पूरा किया गया ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, दरअसल बात यह है कि 14 दिसम्बर को मुख्य मन्त्री महोदय जब दादरी गए थे तो उस वक्त कहां पर लोगों ने मांग की थी कि आई0 यी0 एम0 साहब के हुक्म से पानी बन्द किया गया है और यहां के लोगों को पानी. मिलना चाहिए । इसके बाद मुख्य मन्त्री के आदेश पर

लोहारू कैनाल में पानी ठीक मिलना शुरू हुआ । क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह दुर्भावना नही हे?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) : मेरे रूबरू कोई ऐसी बात नही की गई कि आई0 पी0 एम0 साहब की वजह से पानी बन्द किया गया है । मेरे से पानी की मांग की गई थी और मैंने पानी रिलीज किया शा ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने 1977 में अक्तूबर, नवम्बर में पानी की कमी. की वजह यह बताई है कि फ्लड वाटर को लेने के लिये ड्रेन नम्बर 8 का फलो कम रखा गया तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि– अगर ड्रेन नं 0 8 का लेवल कम था तो फ्लड का पानी ड्रेन में आया लेकिन लोहारू कैनाल में पानी कम क्यों पहंचा जबकि फ्लड वाटर भी– ड्रेन भै था?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . स्पीकर साहब, यह तो हिसाब किताब का मामला है, आनरेबल मैम्बर जवाब को ध्यान से देखें तो उन्हें पता लग जाएगा । The reply is self explanatory.

श्री अध्यक्ष : आप जवाब को समझिये, जवाब बिल्कुल सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है, व ठीक कह रहे हैं ।

Chaudhri Birinder Singh : This is not at all satisfactory.

Mr. Speaker : The level had to be kept low to throw out the water.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, गै पूछना चाहता हूं कि फ्लड वाटर वहां तो आ गया लेकिन जो लोहारू कैनाल फीड करती है, वहां पानी क्यों नहीं पहुंचा?

(इस प्रश्न का उत्तर नही दिया गया)

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि **चौधरी**. बंसी लाल जी ने हमारे रोहतक और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के साथ बड़ा डिसक्रिमीनेशन किया था और 40 परसेन्ट कट लगाकर भिवानी की तरपय पानी दे दिया गया था और यह सब कुछ दुर्भावना की भावना से किया गया था, क्या हमारे मिनिस्टर साहब, इस कट को समाप्त करने का विचार करेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . यदि कोई इस प्रकार की कट है, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री रण सिंह मान : स्पीकर साहब, नहर का पानी रोहतक में पैदा नहीं हुआ । फिर भी तीन सौ साल से नहरें बह रही हैलेकिन नेचूरल रिसोर्सिज जो भी हैं, उन पर सब का समान अधिकार है, तीन सौ साल हो गये लेकिन लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमैंटरी पूछिए ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो लोहारू या दूसरी नहरों के पर सरकार का जो खर्चा आया और जमींदारों से जो उगराही की जा रही है, जब ये खर्चा पूरा हो जायेगा तो जमीदारों से वसूली भी बन्द कर दी जाएगी? ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेनटीनैन्स के लिये तो खर्चा हमेशा ही सरकार लेती रहेगी ।

चौधरी उदय सिंह दलाल :' रू स्पीकर साहब, जैसा कि परसों मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बतलाया था कि इस लोहारू कैनाल या दूसरे नदी नालों से 5 करोड रुपये की आमदनी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए जब मुरम्मत वगैरह का खर्चा पूरा हो जायेगा उसके बाद सरकार इस उगराही को बन्द करने का विचार रखती है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैंने परसों जो जवाब दिया था वह यह था कि इन नहरों के लिये जो बिजली की कंजम्पशन हुई' है, इसके मुकाबले में इन नहरों के पानी से जो प्रोडक्शन हमने की है, वह 5 करोड़ रुपये अधिक बैठती है ।

चौधरी राजिन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि गुड़गांव करनाल को फीड करने केलिये बल्लबगढ में 100 के करीब गर्वनमैंट नैं ट्यूबवैल्ज लगाये हुये हैं. ...

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग सवाल है ।

चौधरी गंगा राम : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि साल में एक एकड़ जमीन को पानी देने के लिये आप वाटर चार्जिक कब लेने का अधिकार रखते हैं, कितनी दफा पानी देकर वाटर चार्जिज ले सकते हैं, यानी एक दफा, दो दफा, चार दफा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह सैपरेट क्वैश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : अगर एक दफा पानी आ जाए तो आपको भाव लगेगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या उन्होंने अक्तूबर में लोहारू कैनाल में पानी बन्द करने के लिये चीफ इंजीनियर को कोई आदेश दिये थे? यह भी बतायें कि पिछले 300 सालों से रोहतक, अम्बाला और सोनीपत वगैरह में पानी मिलता रहा है और जिन इलाको में पानी की कमी रही है क्या उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

Share of Water from the Rajasthan Feeder

***461. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Haryana State has any share in the water of the Rajasthan Feeder Canal which flows through

Haryana ; and

(b) if not, whether the Haryana Government is making any scheme to get its share ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) No.

(b) Yes.

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, जवाब के पार्ट 'बी' में मन्त्री जी ने 'यस' कहा है । यह हरियाणा का हिस्सा कब तक लेने की संभावना है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह हरियाणा का हिस्सा है तो नहीं लेकिन हम कुछ लेना चाहते हैं ।

Recruitment made in the Printing and Stationery Department

***475. Chaudhri Des Raj : Will** the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) the number of new officials/officers recruited in the Printing and Stationery Department, Haryana since 1-1-76 to-date ;

(b) the names of the officials/officers recruited as referred to in part (a) above togetherwith the post on which recruited ;

(c) the names of the States of which these

officials/officers alongwith their domiciles ; and

(d) the number of the previously employed as regular, temporary and stipendiary officials who have been removed from service during the period referred to in part (a) above ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 139

(ख और ग) विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है! (घ) 11

सूची

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हरियाणा में 1– 1–76 से अब तक की गयी भर्ती सम्बन्धी सूचना ।

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद का नाम जिस पर नियुक्ति की गयी	अधिकारी/कर्मचारी जिस राज्य से सम्बन्ध रखता है	होम डिस्ट्रिकट
1	श्री किशन चन्द राज पूत	नियंत्रक	हिमाचल प्रदेश	दिनांक 5–2–1976 से हिमाचल सरका से प्रतिनियुक्ति

				पर
2	श्री हरीश चन्द्र	लिपिक	यू पी 0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
3	श्री राजेश बजाज	″	हरियाणा	अम्बाला
4	कुमारी नीलम	″	यू0 पी0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
5	कुमारी सुशीलता	″	हरियाणा	अम्बाला
6	कुमारी रेनू	″	हरियाणा	″
7	श्री रिशी केश	″	हरियाणा	करनाल
8	श्री प्रभु दयाल	″	हरियाणा	″
9	श्री पुरखा राम	″	″	हिसार
10	कुमारी जोगेन्द्र कौर	″	″	अम्बाला
11	श्री अतर सिंह	″	″	जीन्द
12	श्री मोहन लाल	″	″	अम्बाला
13	श्री राम सिंह	″	″	भिवानी
14	कुमारी मंजु गुप्ता	″	यू टी चण्डीगढ़	चण्डीगढ
15	श्री वीरेन्द्र कुमार छाबड़ा	″	हरियाणा	सोनीपत

16	श्री राम मुमाया हल	″	″	रोहतक
17	श्री कुलदीप राय	लिपिक	हरियाणा	अम्बाला
18	श्री प्रेम प्रकाश	″	″	करनाल
19	श्री कंवरदेव राज सरोहीवाल	″	″	कुरुक्षेत्र
20	श्रीमती अरुण शर्मा	अप्रेन्टिस लिपिक	यू 0टी0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
21	श्रीमती उर्मिला देवी	″	हरियाणा	अम्बाला
22	श्री सुभाष चन्द	स्टैनोटाईपिस्ट	″	करनाल
23	कुमारी पुष्पा रानी	लिपिक	″	अम्बाला
24	श्री कंवल नैन	″	″	गुडगावां
25	श्री अनिल कुमार	″	″	अम्बाला
26	श्री जय राम	″	″	अम्बाला
27	श्री दलबीर सिंह	″	″	हांसी
28	कुमारी विजय	″	यू 0टी 0 चण्डीढ	चण्डीगढ
29	कुमारी सन्तोष	″	″	″

30	श्री गनेश सिंह	"	यू 0पी 0	पोडी गढवाल
31	श्री रोहतास	"	हरियाणा	रोहतक
32	श्री बलराम शर्मा	टाईपराईटर मैकेनिक		अम्बाला
33	श्री आशा राम	"	यू 0 पी	पोडी गढवाल
34	श्री राजेन्द्र लाल	सेवादार	हरियाणा	अम्बाला
35	श्रीमती चरण जीत कौर	"	यू 0टी 0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
36	श्री बाबू लाल	चौकीदार	हरियाणा	मोहिन्द्रगढ
37	श्री कालू राम	"	"	अम्बाला
38	**श्री जगन नाथ :**	चौकीदार	हरियाणा	कुरुक्षेत्र
39	श्री चेत राम	"	"	अम्बाला
40	श्री उमेद सिंह	मजदूर	"	सोनीपत
41	श्री आटा राम	स्वीपर	"	कुरुक्षेत्र
42	श्री फकड राम	"	"	
43	श्री राम चन्द्र	"	"	सोनीपत
44	श्री जय किशन	कम्पोजिटर	"	अम्बाला

45	श्री किशन लाल	"	"	"
46	श्री सुन्दर सिंह	"	"	"
47	श्री वीर अर्जुन	"	"	"
48	श्री गुलशन कुमार	इं कर	"	करनाल
49	श्री शशी पाल	जूनियर मशीन मैन	"	कुरुक्षेत्र
50	श्री बलदेव सिंह	जी 0पी 0मैन	यू 0टीं 0 चण्डीगढ	यू 0टी 0 चण्डीगढ.
51	श्री विजय कुमार	टेरडल मैन	हरियाणा	अम्बाला
52	श्री ज्ञान चन्द	प्रैस मैनेजर	हिमाचल प्रदेश	ओन डैपूटेशन फरौम यू 0 टी 0 प्रैस चण्डीगढ विद इफैक्ट फरौम 2—11—77 फार वन इयर
53	श्री सुशील कुमार नागपाल	सै क्शन होल्डर प्रोसेस	नई दिल्ली	दिल्ली

54	श्री दया नन्द	सैक्शन होल्डर प्रिटिंग	हरियाणा	सोनीपत
55	श्री डी एस बेरवाल	सहायक सैक्शन होल्डर		हिंसार
56	श्री ईश्वर सिंह	”	उत्तर प्रदश	यू 0पी
57	श्री नरेश कुमार	कम्पोजिटर	एच0पी0	कांगड़ा
58	श्री बलबीर सिंह	कापी होल्डर	हरियाणा	रोहतक
59	श्री गोपाल चटर्जी	मोनो आप्रेटर	बंगाल	बंगाल
60	श्री प्रेम सिंह	गैली प्रूफ प्रैस मैन	पंजाव	पटियाला
61	श्री राम मेहर	गैली प्रूफ प्रैस मैन	हरियाणा	सोनीपत
62	श्री अमर चन्द	गैली प्रूफ प्रैस मैन	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
63	श्री भुपिन्द्र सिंह	मोनो मिनिस्टर	यू 0 टी 0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
64	श्री राम प्रकाश	मोनो कास्टर	हिमाचल प्रदेश	0ना
65	श्री बाबू राम	बाईडर	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश

66	श्री महेन्द्र सिंह जोशी	बाईंडर	हरियाणा	रोहतक
67	श्री राम दास	बाईंडर	हरियाणा	भिवानी
68	श्री मनोहरी लाल	बाईंडर	यू 0 टी 0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
69	श्री मनोहर लाल	बाइंडर	यू 0 टी 0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
70	श्री रमेश चन्द्र	बाइडर	यू 0 टी 0 चण्डीगढ	चण्डीगढ
71	श्री शशी पाल	लरनर बाईन्डर	यू 0पी 0	अलीगढ़
72	श्री महावीर सिंह	″	हरियाणा	गुडगावां
73	श्री सीता राम	″	″	अम्बाला
74	श्री राजेन्द्र सिंह	″	″	हिसार
75	श्री सतीश चन्द्र	″	हिमाचल प्रदेश	0ना
76	श्री सत्य पाल	″	हरियाणा	हिसार
77	श्री अशवनी कुमार	लरनर बाइंडर	हरियाणा	हिसार
78	श्री निरजन सिंह	″	यू 0पी 0	अलीगढ़

79	श्री अमी चन्द	"	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
80	श्री भूपाल सिंह	"	हरियाणा	करनाल
81	श्री रोनकी राम	"	"	कुरुक्षेत्र
82	श्री जिले सिंह	"	"	करनाल
83	श्री रूप चन्द	"	यू 0 पी 0	सहारनपुर
84	श्री हरी राम	"	हरियाणा	रोहतक
85	श्री मोती सिंह	"	यू 0 पी0	पोडी गढ़वा ल
86	श्री सुभाष चन्द	"	हरियाणा	सोनीपत
87	श्री लाल चन्द	"	"	अम्बाला
88	श्री सत्य नारायण	"	"	जीन्द
89	श्री इन्द्र सिंह	"	"	कुरुक्षेत्र
90	श्री हजारी लाल	"	"	करनाल
91	श्री शक्ति चन्द	"	हिमाचल प्रदेश	उना
92	श्री जगदीश चन्द	"	हरियाणा	हिसार
93	श्री सगवा रा म	"	यू 0 पी0	सहारनपुर
94	श्री ह वा संह	"	हरियाणा	हिसार

95	श्री इरीक विलियम	"	यू 0टी0चण्डीगढ	चण्डीगढ
96	श्री रा म कंवर	"	हरियाणा	भिवानी
97	श्री टिका रा म	"	हरियाणा	करनाल
98	श्री अमर सिंह	लरनर बाइंडर	यू 0 पी 0	पोड़ी गढवा ल
99	श्री बचन सिंह	"	हरियाणा	अम्बा ला
100	श्री बृज लाल प्रेमी	"	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
101	श्री ऋषिदत्त	"	हरिया णा	गुडगावां
102	श्री कश्मीर सिंह	"	हिमाचल प्र देश	हिमाचल प्रदेश
103	श्री नारायण सिंह	"	राजस्थान	राजस्थान
104	श्री मेहर चन्द	"	हरिया णा	अम्बाला
105	श्री राजिन्द्र सिंह	"	"	गु डगा वां
106	श्री छतर सिंह	"	"	गुडगावां
107	श्री बलवान सिंह	"	"	रोहतक
108	श्री जीत सिंह	"	"	अम्बाला
109	श्री हंस राज	"	"	भिवानी
110	श्री साधू राम	"	"	रोहतक

111	श्री बृज मोहन	"	"	करना ल
112	श्री नान्हा सिंह	"	"	रोहतक
113	श्री नवाब सिंह	"	यू 0टी 0चण्डीगढ	चण्डीगढ
114	श्री भंगत सिंह	इंकर	हरियाणा	मोहिन्द्रगढ
115	श्री सुदर्शन कुमार	"	"	करनाल
116	श्री किर्ती सिंह	डिस्ट्रीव्यूटर	यू 0पी 0	टीरी गढवाल
117	श्री केवल राम	"	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
118	श्री मोहन लाल	"	हरियाणा	अम्बाला
119	श्री बलजीत सिंह	डिस्ट्रीब्यूटर	हरियाणा	कुरुक्षेत्र
120	श्री राम किशन शर्मा	इलैक्ट्रीशियन	"	अम्बाला
121	श्री भोला	मजदूर	"	अम्बाला
122	श्री बस्ता राम	"	"	अम्बाला
123	श्री रौमी राम	"	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
124	श्री बकखरख सिंह	"	पंजाब	होशियारपुर
125	श्री महावीर सिंह	"	हरियाणा	महेन्द्रगढ़
126	श्री महेन्द्र सिंह	"	हरियाणा	सोनीपत

127	श्री बाबू राम	"	"	अम्बाला
128	श्री इन्द्र सिंह	"	"	सोनीपत
129	श्री पन्ना लाल	कारपैन्टर	"	रोहतक
130	श्री ज्ञान चन्द	आफसैट इंकर	हिमा चल प्रदेश	कांगड़ा
131	श्री शिव प्रसाद	"	यू 0 पी 0	यू 0 पी 0
132	श्री नेक राम	"	हमा चल प्रदेश	कांगड़ा
133	श्री महेन्द्र सिंह	"	हरियाणा	अम्बाला
134	श्री जोहन पी 0ए0	"	केरला	त्रिवेन्द्रम
135	श्री बलदेव सिंह	"	पंजाब	होशियारपुर
136	श्री नैयर प्रसाद	टूक्लर वैव आफसैट मशीन आप्रेटर	यू 0 पी 0	यू 0 पी 0
137	श्री धर्म पाल सिँह	"		मेरठ
138	श्री नैयर प्रभाकरण	डोमीनेट आफसैट मशीन आप्रेटर	केरला	
139	श्री ओम प्रकाश	"	देहली	देहली

Voices : We have not got the copy of the statement. It has not been supplied to us.

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : It has been supplied to the Member concerned.

Shri Lachhman Singh : Unless a copy of the statement is supplied to the Members, how can supplementaries be asked ?

Dr. Mangal Sein : It is supplied to the Member concerned.

आवाजें : स्पीकर साहब हमें यह स्टेटमैंट नहीं मिंत्री है ।

श्री अध्यक्ष : क्या आपको यह स्टेटमैंट नहीं मिंत्री है? इसका दस्तूर यह है कि कन्सर्नड मैंबर को वह स्टेटमैंट मिलेगी, बाकी के लिए टेबल आफ दि हाउस पर ले होती है ।

चौधरी देसराज : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री साहिबा बताएंगी कि जो पार्ट 'बी' का जवाब है, उसमें रैगुलर और टैम्पो'रेरी कितने थे जो कि टर्मीनेट किए हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय., टर्मीनेशन की संख्या मैंने 1 1 बताई है । इनमें से तीनरैगुलर, तीन प्रोबेशन पर थे और 5 एडहाक बेसिक पर थे ।

चौधरी देसराज : क्या मिनिस्टर साहिबा उनकी टर्मीनेशन के कारण बताएंगी जिनके कारण उन्हें टर्मीनेट किया गया?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, 11 के टर्मीनेशन का मैं अलग–अलग करके बता देती हूं । वैसे अध्यक्ष महोदय यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है कि जो व्यक्तिगत केसिज हैं, वे लेजिस्लेचर के अन्दर या वे हाउस में डिस्कस किए जाए, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है अगर आपकी अनुमति है तो मैं उनके नाम तथा रीजन बता सकती हूं ।

श्री अध्यक्ष : चाहते हैं आप?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप चाहते हैं तों मैं 1 1 के रीजन बता देती हू ।

श्री अध्यक्ष : उन मैंबर साहिबान से पूछें जिन मैंबर साहिबान ने सवाल किया है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति पर निर्भर करता है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया बताने का कष्ट करेगी' कि यह जो रिपोर्ट सदन में रखी गई है उसमें हरियाणा के इम्पलाईज की संख्या 60 परसैन्ट दिखाई गई है लेकिन असलीयत यह है और मैंचौलेज करेत। हूं कि इस लिस्ट

में हिमाचल और हरिया णा दोनों स्टेटों के एम्पलाईज की संख्या इकट्ठी है और हरियाणा के सिर्फ 30 परसैन्ट एम्पलाईज हैं, इसलिए यह क्रो रिपोर्ट दी गई है यह बिल्कुल झूठी है और जिन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है, क्या मन्त्री महोदया उन अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने का विचार रखती हें?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, 1— 1— 1976 से रिक्रूटमैंट की फिर्ग्ज मांगी गई थी और यह सदन के पटल पर रखी गई हैं, सूचना बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात बिल्कुल गल्त है अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदइएइय इस को चेलेन्ज करें । अगर वे स्टेटमेंट को चौलेन्ज करते हैं तो वह चीज मेरे सामने लाकर रख दे ओर मैं यह बतादूगी कि यह स्टेटमैंट बिल्कुल सत्य है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मैं इस स्टेटमैंट को चौलेंज करता हूं कि यह स्टेटमैंट गलत है ।

Mr. Speaker : Now the Question Hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Colonies Constructed in District Hissar

***462. Lala Balwant Rai Tayal** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) the number of colonies constructed so far in the development blocks of district Hissar under the Rural Housing Scheme ;

(b) the names of development blocks out of those referred to in part (a) above where these colonies have not been constructed so far togetherwith the reasons therefor ; and

(c) the amount of the expenditure incurred by the Government so far thereon ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) इस स्कीम के अधीन हिसार जिले के पांच खण्डों में 7 कालोनीज निर्मित की गई हैं ।

(ख) जिला के हिसार–।, हिसार–।।, हांसी–।, हांसी–।।, तथा नारनौंद खण्डों में कोई कालोनी निर्मित नही की गई क्योंकि चुने हुए गांवों के लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने हिस्से का 20 प्रतिशत भाग श्रम के रुप में देने को इच्छुक नहीं हैं ।

(ग) सीधे तौर से राज्य सरकार द्वारा कोई खर्च नही किया गया, क्योंकि यह स्कीम वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि से चलाई जाती है ।

Reservation of Plots for Government Quota at Panchkula

***470. Chaudhri Bhag Mall :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there was any provision for reservation of plots by Government in the initial terms and conditions for allotment of plots in sector 6 & 7 of the Urban Estate at Panchkula ;

(b) if the reply is in the negative then the reasons of making reservation by the Estate Officer in the said sectors in contravention of the terms and conditions ;

(c) the total number of applications of March, 1972 pending for allotment of 10 marla and 14 marla plots ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to resume the unbuilt big plots in Sector 6 and to convert them into small plots for allotment to old applicants of March, 1972 by directing the Town and Country Planning Department to curve out small plots from the vacant land in the said sectors, if not the reasons therefor ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(क) जी नहीं ।

(ख) पंजाब शहरी सम्पदा (प्लाटों की बिक्री) नियमावली के नियम 3 के अनुसार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया शा कि सरकार द्वारा अलाट किए जाने वाले प्लाटों का दस प्रतिशत आरक्षित रखा जाए ।

(ग) मार्च 1972 में दिए गए कुल आवेदन पत्र, जो अभी 2 8— 2— 78 को 10 मरले तथा 14 मरले के प्लाटों की अलाटमैंट के लिए लम्बित पड़े थे, निम्नानुसार हैं :—

10 मरला— 4851. 14 मरला— 690

(घ) जी नहीं । 1 3— 1— 1977 से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 के अधीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है । प्लाटों को पुनर्ग्रहण करने की शक्ति प्राधिकरण में निहित है और सरकार प्लाटों का पुनर्ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है ।

Capacity of Dhamtan Disty.

***217. Sh. Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the capacity statement as per Bhakra water allowance of Dhamtan Disty. of Narwana Irrigation Divn. from its head to tail alongwith its off takes ;

(b) whether there are any schemes for providing full supply of water at the tails of Narwana, Mohalgarh, Dhamtan, Dharodi Laon, Kalwan and Sancha Khera Minors of Narwana Divn. of Ambala Bhakra Canal Circle, if so, the time by which the aforesaid schemes, are likely to be completed ; and

(c) the total amount recovered as `Taware from Irrigators of Narwana Canal Sub Division for the years 1975-

76,1976-77 and 1977-78, todate.

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) कैपेसिटी स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है ।

(ख) नहीं, यह सभी नहरें पहले ही अपनी टेलो पर पूरी क्षमता से पानी प्रदान कर रही हैं ।

(ग) तवान लगाकर निम्नलिखित राशि वसूल की गई है ।

	रुपए
1975— 76	64,988
1976— 77	54,081
1977— 78	अब तक 20,846

Rising Prices

***276. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by the Government to check the rising prices in the State together with the extent to which the Government has achieved the success in this behalf ?

खाद्य व पूर्ति मंत्री (श्रीमती डा 0 कमला वर्मा) :

(1) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धी उचित भावों पर उपभोगताओं को कराने हेतु सरकार ने भिन्न–भिन्न आदेश जारी किए हुए हैं । यह आदेश मुख्यतः

प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं की बेच तथा भण्डार पर नियन्त्रण रखते है । प्रतिदिन इस्तेमाल में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को व्यापारियों द्वारा दर्शाना आवश्यक है ।

(2) लाईसेंस चक्की वालोंको इस बात की छूट दे दी गई है कि बहु केन्द्रीय भण्डार से गेहूं की सप्लाई प्राप्त करें सकते हैं । इसके फलस्वरुप चक्की वालों को अधिक मा ला में नेह अलाट की गई है ताकि वह इसका आटा उपभोगताओं का बेच सके ।

(3) पर्याप्त माता में गेहूं उचित मूल्य की दुकानो की मारफत उपभेगताओं में वितरण के लिए जारी की जा रही है ।

(4) उचित मूल्य की दुकाने और भी खोली जा चुकी हैं और गत वर्ष में शहरी क्षेत्रों में 24 व देहाती क्षेत्रों में 366 और नई खोली गई हैं ।

(5) विदेशों से आयात किया हुआ रेप–सीड आयल को कोप्रेटिव कन्जयूमर स्टोर्ज की मारफत सस्ते दामों परे बेचा जा रहा है ।

इन पगों के उठाए जाने के फलस्वरूप प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुएं जैसा कि चीनी, चावल बेगमी, उड़द, खुली चाय, वनस्पति घी तथा सरसों के तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई है । जहां तक दालों का प्रश्न है हमारा राज्य अन्य राज्यों से आयात पर निर्भर है और जब तक कि उनकी कीमतें उतादन करने वाले राज्यों में नियन्त्रण में नही की जाती, राज्य सरकार इनकी कीमतों को नीचे लाने में कुछ आधिक नहीं कर सकती ।

Co-operative Sugar Mills Karnal and Sonepat

***292. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Government has received any complaints in regards to the irregularities committed during the construction of co-operative Sugar Mills set up at Karnal and Sonepat and also making appointment in the aforesaid mills ;

(b) if so, whether the Government propose to conduct an equiry in this regard ;

(c) If no, will the Government collect the information now ; and

(d) whether the quality of the sugar manufactured in the said mills was got tested and if so, the result thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar. Singh) :

(a) Complaints have been received only in regard to appointments.

(b) Management of Sugar Mills conducted enquiry and terminated services of some of the employees. Further more, a Screening Committee has been constituted by Sugar Mills which will go into the matter in detail. The Committee would put up suitable proposal for weeding out inefficient staff.

(c) Question does not arise.

(d) Yes. Statement is placed on the table of the House. **STATEMENT**

Mill-wise position of the Quality of sugar manufactured, tested and results thereof is given as under :—

Quality of Sugar		Sonepat (Qtls.)	Karna l (Qtls.)
(1)	E-30	1478	7492
(2)	E-29	2833	1812
(3)	D-30	596	33398
(4)	D-29	886	4831
(5)	C-30	21	9073
(6)	C-29	—	3865
(7)	B-29		701

(8) Below Indian Sugar Standard (BISS)	13342	1265
(9) Brown Sugar	1297	-
Grand Total :	20453	62437

Local Purchase in Buildings and Roads Material

***307. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district-wise total expenditure incurred on local purchase of the material in respect of Buildings & Roads during the years 1974-75, 1975-76 & 1976-77 togetherwith the details of the main items purchased under the Head "Local Purchase";

(b) the total number of registered suppliers in the State as at present ; and

(c) 'whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase all the material direct from the manufacturers ?

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(बी) 330

(सी) नही ।

विवरण

क्रमांक	जिला	1974—75	1975—76	1976— 77
1	अम्बाला	2,63,172	2,63,647	2,90,060
2	करनाल	2,56,491	3,23,027	3,14,366
3	कुरुक्षेत्र	1,11,111	2,01,575	2,54,097
4	सोनीपत	42,284	36,877	1,70,604
5	रोहतक	1,26, 454	1,27,586	2,08,685
6	गुड़गांव	6,69,641	6,64,960	7,35.794
7	भिवानी	1,10,980	2,90,702	2,87,685
8	जींद	88,886	1,11,290	1,72,632
9	हिसार	1,65,208	3,36,099	2,48,879
10	सिरसा	42,149	52,389	1,28,491
11	महेन्द्रगढ	20,767	80,229	1,33,633
	जोड	18,97,143	24,88,381	29,44,886

(ए) (ii) मुख्य वस्तुओं का विवरण जो कि शीर्ष ' 'स्थानीय खरीद'' के अधीन की गई पेन्टस तया डिसटैम्पर, ब्रुसिज, टेरिग आउटफिट्स, पलैक्सीबल पाईप, टूथ वासकींट्स,

डबल एक्सन हिंगज, डोर फिटिंग्ज, पयूलवुड, एल 0डीप्स, कोर्पालंग, सैट, ग्लास पैनस, रोप, डोरी, टेरिंग बुकेट/मैटीरियल. व्हाईट लाईम, एम0 एस0प्लेट, मिस रोड आईटमज, दियोदार वुड स्टील विभिन्न प्रकार का स्वीचेज कन्डैसर चोक, 5, 1 0, 1 5, एम्प प्लगक, पी 0डबयू 0 बेटन राउण्ड ब्लाक, पलैक्सीबल वायरटैप, किटकैट्स, एयर कन्डीशनर/कूलिग एपलीऐसिंज स्पेयर, हीटरज स्पेयर, फर्नीचर, टयूब स्टारटर्ज इत्यादि ।

Tax Structure Review Committee

***404. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the Government appointed a Tax Structure Review Committee, if so, the names of the members ;

(b) whether the Committee has submitted its report or it is still functioning ; and

(c) whether the Government has received any memorandum of the grievances of the Haryana traders from Haryana Beopar Mandal ; if so, a copy thereof be laid on the table of the House and whether any action was taken thereon ?

वित्त मंत्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) :

(ए) जी हां । सदस्यों के नामों का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(बी) कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं ।

(सी) हां । हरियाणा प्रदेश व्यापार मण्डल से प्राप्त ज्ञापन की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है । ज्ञापन पर कमेटी द्वारा विचार जारी है ।

टैक्स स्ट्रकचर रिव्यू कमेटीके सदस्यों के नामों का विवरण

(1) डा0 मंगल सैन,

उद्योग मन्त्री, हरियाणा ।

अध्यक्ष

(2) श्री वीरेन्द्र सिंह

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री, हरियाणा

सदस्य

(3) श्री सतबीर सिंह मलिक,

वित्त मन्त्री, हरियाणा ।

सदस्य

(4) श्री राम लाल वधवा,

उप–अध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड ।

सदस्य

(5) श्री पी0 पी 0 कैप्रीहन,

वित्तायुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी व कराधान विभाग ।

सदस्य

(6) श्री बी0 एस 0 ओझा,

वितायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,

वित्त विभाग । सदस्य

(7) श्री एम0 कुट्टपन,

उपुक्त सचिव, आवकारी व कराधान विभाग ।

सदस्य सचिव

ज्ञापन

HARYANA PRADESH BEOPAR MANDAL Central Office :

Chaura Bazar, Karnal

November 15, 1977.

Proposals put up by the Representatives of Haryana Pradesh Beopar Mandal—Members of the Tax-Structure Review Committee for consideration and approval in -the meeting of Tax Structure Review Committee held on 15-11-1977 at Chandigarh.

(i) It is proposed that in addition to review the Tax structure, this Committee will also consider all the Trade Problems relating to various Government Departments ;

(ii) **Enhancement of Surcharge on Sales Tax from 2 to 15%**

There is adverse effect on the Trade in the State as well as on the Revenue of Government from Sales Tax as after enhancement of surcharge, the sales of Scooter, Motor Cycles, Auto Cycles, Tractors, Motor Cars, Trucks, Tyres and Tubes, Refrigerators Geysores, Coolers, Electric Fans, Televisions, Radios, Radio-Grams, Loud Speakers, Cameras, Projectors, Type-writers, Duplicators, Furniture, Electric Motors and their appliances, Mono block Pumping Sets, Sanitary Goods, Leather Goods, Building Material, Medicines, etc. etc. has considerably fallen and the purchaser meet their requirements from the adjoining StateDelhi—Chandigarh, Punjab, Rajasthan and U.P., Where there is no surcharge and lessor rates of Sales Tax in those States. Therefore, in this way, the Government will lose its sales-tax instead of getting surcharge on it. The Trade with this measure will shift to adjoining States thus giving a jolt to the State economy.

It is proposed that enhancement of Surcharge be withdrawn with immediate effect.

(iii) **Enhancement of Market Fees from 2% to 3**

The enhancement of Market fee has- ruined the trade of the State. The business of border Mandis are almost transferred to the adjoining States as the rate of Market Fee in Punjab is l I %, Rajasthan 1 %, U.P. 1 % and Delhi Nil. The Farmers will take its produce to the Mandis in other States and, therefore, the agricultural production figures for Haryana will come down and the Market Committee will lose their fee in total.

For example in these days, the market arrivals of Paddy alone in Narela Mandis is forty thousand bags a day. The major portion of this produce is from Haryana villages. Similarly, other Mandis of Haryana i.e., Dabwali, Kalanwali, Ellanabad, Sirsa, Ratia, Tohana, Jakhal, Sewani, Narnaul, Mohindergarh, Sonepat, Smalkha, Bahadurgarh, Ambala, Kalka, Pehowa, Cheeka, Kaithal, Ladwa, Radaur, Yamuna Nagar, Jagadhri, etc. etc. are on the brink of ruines,

To save Haryana and its trade, it is proposed that this enhancement of Market Fee be withdrawn with immediate effect.

(iv) Reduction in Arhitiya Commission (Dami) from 2 to 1½ %

Dami does not effect the State Revenue or the interest of the Growers. The rate of Arhitiya Commission in Delhi is Rs. 2.06%, Rajasthan 2 to 2 %, Gujarat 2 to 3 %, Madras 3 % and Kerala 3 %. It is charged from dealer to dealer. As there is no restraint on the margin of profit of the Retailers, it does not effect the consumers also.

Rates of 2% Commission which includes heavy rates of interests, salaries of employees increasing rents of shops, heavy investments and other incidental expenses is very very reasonable, whereas the Government agencies charge much more rate of Commission for such kind of services.

It is proposed that Arhitiya Commission be restored immediately.

(v) Sales **Tax on Cotton Sewing Thread**

In spite of the fact that the Chief Minister had agreed to issue instructions for charging 1 % Sales Tax on the sales of Cotton Sewing Threads, no instructions have yet been issued to the Assessing Authorities by the Excise and Taxation Commissioner.

Instructions to this effect be issued immediately so that no harassment and inconvenience is- caused to this Trade.

There are so many other difficulties and ambiguities regarding Sales Tax Act, Agricultural Produce Market Act, Food and Civil Supplies Department, Health and Labour Department, Municipal Committee, which will be brought to notice and discussed in the next meeting.

S.D. Sarup Gupta, Jai Kishan Aggarwal,

President Convener Action Committee.

Jui Canal

***439. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the Jui Canal was made perennial ;

(b) the date, time and place at which fault if any in electricity occurred in the said canal since then to-date alongwith the reasons therefore ; and

(c) the area of land affected by flood on account of its construction

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) 1-1-1973.

(b) A statement is enclosed.

The reasons are power fluctuations and low voltage.

(c) 65.32 acres.

Jui Canal

Detail of break-down in electricity/timing place of fault alongwith area flooded.

Date	Time	Hours	Place	Area Flooded if any
1	2	3	4	5

	Month 7/73			
19-7-73	10.15 to 10.22	0.07	P.H. No. I	-
	10.25 to 10.30	0.05	Jui Canal	
20-7-73	12.40 to 12.45	0.05		
21-7-73	9.15 to 9.17	0.02		
	12.10 to 12.22	0.12		
22-7-73	12.15 to 12.25	0.10		
	16.35 to 17.10	0.35		
24-7-73	10.34 to 10.56	0.22		
26'7-73	20.25 to 20.40	0.15		
27-7-73	12.10 to 12.20	0.10		
29-7-73	11.35 to 11.40	0.05		
	12.00 to 12.10	0.10		
30-7-73	15.30 to 15.42	0.12		
	Total:	2.30		
	Month 8/73			
19-8-73	19.35 to 19.40	0.05		
20-8-73	18.05 to 18.45	0.40		
24-8-73	21-15 to 23.45	2.30		

	Total :	3.15	
	Month 9/73		
6-9-73	11.55 to 12.00	0.05	
	12.20 to 12.40	0.20	
8-9-73	16.50 to 16.53	0.03	
10-9-73	13.15 to 14.25	1.10	
	18.40 to 19.20	1.20	
15-9-73	10.55 to 10.57	0.02	
	14.13 to 14.15	0.02	
18-9-73	16.05 to 16.45	0.40	
	18.50 to 19.20	0.30	
	19.35 to 20.25	0.50	
19-9-73	7.20 to 7.25	0.05	
20-9-73	8.20 to 8.30	0.10	
	19.02 to 19.40	0.38	
	21.35 to 21.40	0.05	
21-9-73	1.05 to 1.10	0.05	P.H. No. I
	11.48 to 12.30	0.42	Jui Canal
22-9-73	8.50 to 12.15	3.25	

	14.50 to 15.15	0.25
24-9-73	7.05 to 7.07	0.02
	11.45 to 12.15	0.30
	Total :	11.00
	Month 10/73	
1-10-73	3.05 to 3.10	0.05
7-10-73	10.40 to 10.42	0.02
8-10-73	10.55 to 11.22	0.27
10-10-73	22.05 to 22.21	0.16
	Total :	0.50
	Month 11/73	
2-11-73	21.35 to 23.45	2.10
5-11-73	9.13 to 9.15	0.02
10-11-73	8.13 to 8.15	0.02
11-11-73	7.45 to 7.47	0.02
	10.50 to 11.00	0.10
12-11-73	11.55 to 11.57	0.02
22-11-73	8.25 to 8.40	0.15
27-11-73	15.35 to 15.40	0.05

28-11-73	10.30 to 14.45	4.15		
	Total :	6.63		
	Month 12/73			
22-12-73	5.48 to 5.55	0.07		
	6.10 to 6.15	0.05		
22-12-73	11.50 to 12.00	0.10		
	16.05 to 16.10	0.05		
	16.15 to 16.20	0.05		
	16.15 to 16.20	0.05		
	16.20 to 16.35	0.05		
	16.50 to 16.55	0.05		
	20.35 to 20.45	0.10		
23-12-73	8.00 to 14.00	6.41		
	Total :	7.33		
	Month 1/74			
20-1-74	12.15 to 12.20	0.05	P.H.No.I Jui canal near village Lohani	No
22-1-74	9.35 to 9.40	0.05		

	9.45 to 9.50	0.05
	11.50 to 12.05	0.15
	18.45 to 19.05	0.20
23-1-74	6.10 to 6.15	0.05
	7.10 to 7.15	0.05
	9.05 to 9.07	0.02
25-1-74	9.20 to 9.25	0.05
	17.10 to 17.20	0.10
29-1-74	7.55 to 8.01	0.06
	Total :	1.23
	Month 2/74	
24-2-74	17.45 to 18.07	0.22
27-2-74	6.58 to 7.00	0.02
28-2-74	21.30 to 21.33	0.03
	Total :	0.27
	Month 3/74	

1-3-74	7.45 to 7.50	0.05
28-3-74	10.48 to 10.55	0.07
	11.45 to 12.10	0:25
	12.35 to 12.55	0.20
	13.05 to 13.25	0.20
	13.55 to 14.00	0.20
	14.25 to 14.30	0.05
	14.50 to 14.55	0.05
	15.05 to 15.10	0.05
	16.15 to 16.20	0.10
	17.05 to 17.20	0.15
30-3-74	13.45 to 13.55	0.10

	Total :	2.12	
	Month 4/74		
3-4-74	13.25 to 13.40	0.15	
	Total :	0.15	
	Month 5/74		
1-5-74	12.00 to 12.30	0.30	P.H.No. I Jui Canal
3-5-74	10.00 to 10.20	0.20	
13-5-74	8.25 to 8.40	0.15	
	Total :	1.05	
	Month 6, 74		
6-6-74	21.05 to 21.40	0.35	
	22.00 to 22.05	0,05	
7-6-74	17.50 to 17.55	0.05	
8-6-74	5.25 to 5.50	0.25	
9-6-74	9.45 to 9.50	0.05	
28-6-74	6.00 to 6.35	0.35	
	19.15 to	0.10	

	19.25	
29-6-74	15.00 to 15.20	0.20
30-6-74	10.45 to 11.00	0.15
	15.15 to 15.20	0.05
	15.40 to 15.50	0.10
	16.45 to 16.55	0.10
	Total :	3.10
	Month 7/74	
1-7-74	8.40 to 8.50	0.10
	13.10 to 13.15	0.05
	17.40 to 18.05	0.25
	23.00 to 1.00	2.00
2-7-74	1.05 to 1.10	0.05
	1.15 to 1.20	0.05

	1.25 to	1.30	0.05	
	10.05	to 10.07	0.02	
5-7-74	14.50	to 15.00	0.10	
9-7-74	17.35	to 17.40	0.05	
10-7-74	7.55 to	8.20	0.25	
	8.25 to	8.50	0.25	
	8.55 to	9.10	0.15	
	14.45	to 14.50	0.05	
21-7-74	12.05	to 12.28	0.23	
	Total :		4.45	
	Month 8/74			
5-8-74	13.20	to 14.10	0.50	P.H.No.I Jui No Canal Near village Lohani
9-8-74	6.05 to	6,10	0,05	
	8.35 to	8,40	0.05	
	15,25	to 15.35	0.10	

	18.20 to 18,23	0.03
10-8.74	10.23 to 10.25	0.02
	13.05 to 13.10	0.05
12-8-74	14.25 to 14.30	0.05
14-8-74	6.12 to 6.40	0.15
15-8-74	6.32 to 6.37	0.05
	18.25 to 18.35	0.10
27-8-74	11.10 to 11.15	0.05
	13.10 to 13.12	0.02
28-8-74	11.15 to 11,18	0.Q3
29-8-74	7.55 to 7.57	0.02
30:8,74	17,20 to 17.35	0.15
	Total :	2.22

Month 9/74

1-9-74	6.20 to	6.35	0.15
	7.02 to	7.05	0.03
	13.05 to	13.08	0.03
	17.25 to	17.30	0.05
4-9-74	16.55 to	17.00	0.05
6-9.74	19.10 to	19.15	0.05
9-9-74	15,00 to	15.10	0,10
11-9-74	13.15 to	13.20	0.05
	15.10 to	15.20	0.10
	16.50 to	17.00	0.10
	20.15 to	20.25	0.10
12-9-74	1.15 to	1.25	0.10
	11.10 to	11.15	0.05

	11.50	to 12.00	0.10		
13.9.74	13.30	to 13.35	0.05		
	12.05	to 12.10	0.05		
	12.20	to 1200	'0.10		
	13.05	to 13.15	0.10		
	14.05	to 14.10	0.05		
	17.15	to 17.25	0.10		
	Total;		2.41		
	Month 10/74				
19.10.74	9.35 to	9.40	0.05	PH No.1 Jui Canal near village Lohani	No
	16.55	to 17.10	0.15		
23.10.74	22.00	to 22.10	0.10		
24.10.74	5.15 to	5.30	0.15		
	10.15	to 10.30	0.15		
	12.30	to 12.35	0.05		
	15.30	to 15.40	0.10		
	22.30	to 22.40	0.10		
25.10.74	6.00 to	6.20	0.20		

	Total;		1.45		
	Month 11/74				
29.11.74	3.40 to	3.50	0.10		
	4.00 to	4.05	0.05		
	Total:		0.15		
	Month 12/74				
31.12.74	10.20	to 10.40	0.20		
	11.35	to 11.40	0.05		
	Total;		0.25		
	January, 1975				
1.1.75	0.50 to	1.40	0.50	P.H.No.I near Lohani	Nil
1.1.75	8.05 to	8.10	0.05	-do-	-do-
1.1.75	8.15 to	8.20	0.05	-do-	-do-
1.1.75	8.25 to	8.30	0.05	-do-	-do-
1.1.75	12.00	to 12.05	0.05	--do--	-do-
5.1.75	9.50 to	10.30	0.40	-do-	-do-
5.1.75	10.45	to 10.50	0.05	--do--	-do-
7.1.75	9.55 to	12.00	1.05	-do-	-do-

8.1.75	6.20 to 7.55	1.35	-do-	-do-
8.1.75	10.23 to 10.28	0.05	-do-	-do-
31.1.75	10.15 to 11.52	0.37	--do--	-do-
		5.17		
	February, 1975			
1.2.75	7.00 to 7.20	0.20	-do-	-do-
3.2.75	9.15 to 9.35	0.20	-do-	-do-
12.2.75	7.35 to 7.47	0.15	-do-	-do-
		0.55		
	March, 1975			
17.2.75	16.04 to 16.45	0.40	-do-	-do-
9,3.75	8.55 to 8.58	0.03	-do-	--do--
24.3.75	10.45 toe 10.50	0.05	-do-	--do--
17.3.75	13.35 to 14.05	0.30	-do-	-do-
20.3.75	9.15 to 10.42	1.27	--do--	--do--
31.3.75	16.20 to 16.25	0.05	-do-	--do--
		2.50		
	April, 1975			

4.4.75	9.15 to	9.25	0.10	-do-	-do-
4.4.75	13.55	to 14.00	0.05	-do-	-do-
6.4.75	8.32 to	8.37	0.05	-do-	-do-
15.4.75	14.15	to 14.20	0.05	-do-	-do-
17.4.75	16.15	to 16.23	0.08	-do-	-do-
18.4.75	10.10	to 11.02	0.52	-do-	-do-
			1.25		
		May, 1975			
5.5.75	10.10	to 10.20	0.10	P.H.No.I Jui Canal	--
10.5.75	20.00	to 20.05	0.05		-
19.5.75	14.35	to 15.25	0.50		
20.5.75	20.20	to 20.50	0.30		
20.5.75	15.25	to 15-35	0.10		
3.5.75	19.05	to 19.30	0.25		
			2.10		
		June, 1975			
2.6.75	11.05	to 11.20	0.15		
2.6.75	20.05	to 20.15	0.10		

4.6.75	9.00 to	9.20	0.20
4.6.75	15.15	to 16.20	1.05
4.6.75	21.30	to 21.35	0.05
4.6.75	21.45	to 21.50	0.05
5.6.75	8.30 to	8.35	0.05
5.6.75	19.10	to 19.20	0.10
5.6.75	19.30	to 20.00	0.30
6.6.75	4.40 to 4.45		0.05
6.6.75	5.05 to	5.10	0.05
15.6.75	22.40	to 22.00	0.10
15.6.75	23.30	to 23.40	0.10
16.6.75	1.25 to	1.35	0.10
16.6.75	2.30 to	2.50	0.20
20.6.75	8.35 to	8.45	0.10
22.6.75	6.35 to	6.40	0.05
30.6.75	14.00	to 14.15	0.15
			4.20

July, 1975

1.7.75	9.45 to	9.55	0.10

1.7.75	10.50	to 11.00	0.10	
2.7.75	11.10	to 11.20	0.10	
3.7.75	7.20	to 8.00	1.30	
3.7.75	15.05	to 15.10	0.05	
5.7.75	17.25	to 19.30	2.05	
5.7.75	20.55	to 20.56	0.01	
10.7.75	15.00	to 15.05	0.05	
11.7.75	15.20	to 15.40	0.20	
15.7.75	18.05	to 18.20	0.15	
16.7.75	6.20	to 6.27	0.07	
17.7.75	6.50	to 7.05	0.15	
17.7.75	22.00	to 22.07	0.07	
			5.20	

August, 1975

1.8.75	10.35	to 10.37	0.02	P.H.No. 1 Jui Canal -
2.8.75	5.52	to 5.55	0.03	
4.8.75	13.55	to 15.10	1.15	
14.8.75	13.15	to 13.25	0.10	

18.8.75	11.35	to 12.35	1.00
19.8.75	2.35	to 2.45	0.10
19.8.75	4.35	to 4.40	0.05
22.8.75	19.02	to 19.12	0.10
			2.55

September, 19'75

1.9.75	10.40	to 11.00	0.20
3.9.75	11.10	to 11.11	0.01
8.9.75	16.10	to 16.15	0.05
9-9-75	6.35	to 6.37	0.02
9-9-75	18.35	to 18.37	0.02
23-9-75	21.35	to 21.55	0.30
24-9-75	9.35	to 9.40	0.05
25-9-75	8.45	to 8.55	0.10
25.9.75	9.00	to 10.15	1.15
26.9.75	3.50	to 4.15	0.25
28.9.75	7.55	to 8.00	0.05

29.9.75	23.35	to 23.38	0.03		
			3.03		
		October, 1975			
3.10.75	18.15	to 18.20	0.05		
8.10.75	12.15	to 12.45	0.30		
11.10.75	15.35	to 15.37	0.02		
28.10.75	15.15	to 15.20	0.05		
30.10.75	16.15	to 16.20	0.05		
30.10.75	18.05	to 18.07	0.02		
			0.49		
		November, 1975			
15.11.75	18.25	to 19.00	0.35		
		December, 1975			
17.12.75	10.20	to 10.25	0.05		
17.12.75	2.35 to	2.37	0.02		
20.12.75	8.55 to	8.58	0.03		
			0.10		
		January, 1976			
25.1.76	7.40 to	8.05	0.25	P.H.No. I near	Nil

25.1.76	8.45 to	8.50	0.05
26.1.76	14.35	to 14.37	0.02
27.1.76	6.40 to	6.42	0.02
29.1.76	9.10 to	9.15	0.05
31.1.76	9.05 to	9.16	0.11
			0.50

February, 1976

19.2.76	15.35	to 16.30	0.55
28.2.76	8.20 to	8.50	0.30
27.2.76	15.45	to 16.20	0.35
			2.00

March, 1976

1.3.76	11.45	to 11.50	0.05
1.3.76	12.00	to 12.10	0.10
2.3.76	23.02	to 23.08	0.06
3.3.76	3.02 to	3.04	0.02
4.3.76	12.35	to 12.45	0.10

5.3.76	8.25 to 8.35	0.10
		0.45
	April, 1976	
2.4.76	8.35 to 8.39	0.04
	May, 1976	
12.5.76	9.35 to 9.50	0.15
20.5.76	14.45 to 14.50	0.10
21.5.76	13.35 to 3.00	3:25
23.5.76	12.35. to 12.40	0.05
25.5.76	18.18 to 18.28	0.10
		4.05
	June, 1976	
6.6.76	21.05 to 21.10	0.05
7.6.76	9.35 to 10.01	0.20
21.6.76	19.45 to 20.30	0.45
22.6.76	13.20 to 13.36	0.16
		1.32
	July, 1976	

4.7.76	9.40	to 9.45	0.05	PH.No. I Jui Canal	--
4.7.76	11.35	to 11.40	0.05		
6.7.76	17.05	to 17.10	0.05		
7.7.76	8.32	to 8.35	0.03		
8.7.76	7.15	to 7.25	0.10		
8.7.76	19.45	to 20,00	0.15		
9.7.76	12.10	to 12.12	0.02		
10.7.76	19.50	to 19.55	0.05		
11.7.76	16.35	to 16.50	0.15		
21.7.76	19.15	to 20.10	0.55		
			2.02		
	August, 1976				
1.8.76	18.35	to 18.37	0.02		
5.8.76	21.01	to 21.11	0.10		
			0.12		
	September, 1976				
3.9.76	18.00	to 18.16	0.16		
24.9.76	11.20	to	0.10		

	11.30		
24.9.76	11.50	to 12.00	0.10
24.9.76	12.05	to 12.10	0.05
24.9.76	12.12	to 12.15	0.03
24.9.76	12.40	to 12.45	0.05
24.9.76	16.10	to 16.15	0.05
4.9.76	17.15	to 17.18	0.03
			0.57
	October, 1976		
2.10.76	9.15	to 9.18	0.03
3.10.76	3.10	to 3.20	0.10
9.10.76	11.05	to 11.20	0.15
9.10.76	13.40	to 13.50	0.10
18.10.76	19.40	to 19.45	0.05
19.10.76	17.55	to 18.00	0.05
19.10.76	18.04	to 18.05	0.01
22.10.76	16.01	to 16.02	0.01
24.10.76	9.45	to 9.46	0.01

24.10.76	17.33	to 17.38	0.05		
25.10.76	16.20	to 16.45	0.25		
25.10.76	18.35	to 19.00	0.25		
27.10.76	9.20	to 9.21	0.01		
28.10.76	16.50	to 16.51	0.01		
30.10.76	17.55	to 18.05	0.10		
			1.58		
		November, 1976			
3.11.76	8.10	to 8.40	0.30	P.H.No.I Jui Canal	--
5.11.76	11.50	to 11.55	0.05		
5.11.76	15.25	to 15.30	0.05		
5.11.76	16.00	to 16.40	0.40		
11.11.76	13.25	to 18.35	0.10		
			1.30		
		December, 1976			
25.12.76	11.10	to 11.18	0.08		
31.12.76	11.50	to 13.05	1.15		
31.12.76	14.45	to 14.47	0.02		

			1.25	
		February, 1977		
1.2.77	9.50 to	9.53	0.03	P.H. No. I Canal near village
2.2.77	7.35 to	7.40	0.85	Lohani
2.2.77	18.55	to 19.15	0.20	
2.2.77	5.40 to	6.40	1.00	
3.2.77	10.15	to 10.20	0.05	
4.2.77	8.07 to	8.12	0.05	
5.2.77	14.45	to 15.22	0.37	
9.2.77	16.15	to 17.00	0.45	
			3.00	
		March, 1977		
2.3.77	10.15	to 10.20	0.05	
3.3.77	12.00	to 12.02	0.02	
5.3.77	9.05 to	9.20	0.15	
31.3.77	19.53	to 19.58	0.05	
			0.27	
		April, 1977		

	9.40	to	9.50	0.10	
	12.02	to	12.25	0.23	
	18.15	to	18.30	0.15	
	19.10	to	19.15	0.05	
	20.25	to	20.30	0.05	
				0.58	
	May, 1977				
2.5.77	13.45	to	14.05	0.20	
4.5.77	16.30	to	16.33	0.03	
	18.45	to	20.15	1.30	
6.5.77	9.35	to	9.45	0.10	
7.5.77	18.50	to	18.55	0.05	
8.5.77	15.35	to	15.50	0.15	
9.5.77	6.35	to	7.35	1.00	
	7.50	to	8.10	0.20	
	8.20	to	9.45	0.25	
	9.55	to	13.20	3.25	
10.5.77	7.20	to	7.40	0.20	P.H. No. I Jui Canal --

15.5.77	19.25	to 19.29	0.04
	20.05	to 20.07	0.02
16.5.77	6.45 to	9.15	2.30
			10.29

June, 1977

3.6.77	16.40	to 16.41	0.01
5.6.77	9.00 to	9.25	0.25
	14.10	to 15.30	1.20
	20.10	to 20.30	0.20
7.6.77	10.10	to 18.00	7.50
	20.14 to	20.29	0.15
8.6.77	7.10 to	7.45	0.35
	3.45 to	3.50	0.05
26.6.77	29.00 to 0.15		0.15
28.6.77	9.15 to	9.27	0.12
29.6.77	3.35 to 15.15		1.40
	16.10	to 17.55	1.45
			14.43

July, 1977

10.7.77	16.33	to 16.38	0.05	
11.7.77	18.14	to 18.19	0.05	
16.7.77	4.30 to	4.45	0.15	
18.7.77	10.20	to 11.00	0.40	
19.7.77	5.25 to	5.45	0.20	
	14.40	to 15.30	0.50	
20.7.77	16.15	to 16.30	0.15	
21.7.77	7.50 to	7.55	0.05	
22.7.77	10.10	to 10.12	0.02	
	16.40	to 18.00	1.20	
24.7.77	8.40 to	8.55	0.15	
	17.15	to 17.25	0.10	
25.7.77	0.10 to	0.20	0.10	
27.7.77	8.32 to 16.00		7.28	
			10.40	

August, 1977

1.8.77	21.38	to 21.50	0.12	P.14. No.1

22.8.77	15.35	to 15.40	-0.05	JuiCanal	---
28.8.77	7.03	to 7.05	0.02		
30.8.77	21.02	to 21.06	0.04		
			0.23		

September, 1977

2.9.77	10.20	to 10.28	0.08		
4.9.77	18.55	to 19.00	0.05		
8.9.77	19.20	to 19.27	0.07		
12.9.77	11.40	to 11.45	0.05		
18.9.77	7.10	to 7.20	0.10		
21.9.77	14.55	to 15.05	0.10		
24.9.77	16.50	to 17.10	0.20		
25.9.77	11.11	to 11.14	0.03		
			1.08		

October, 1977

4.10.77	8.50	to 12.50	4.00		
4.10.77	16.00	to 20.50	4.50		
5.10.77	10.50	to 13.00	2.50		

5.10.77	18.10	to 20.00	2.00
6.10.77	17.00	to 20.50	3.50
7.10.77	18.50	to 19.50	1.00
8.10.77	11.00	to 13.00	2.00
10.10.77	13.50	to 20.50	7.00
11.10.77	11.50	to 13.50	2.00
12.10.77	10.00	to 18.50	8.50
13.10.77	9.00	to 16.00	7.00
			45.00

November, 1977

8.11.77	9.30	to 11.30	2.00
10.11.77	6.55	to 7.02	7.07
12.11.77	15.30	to 18.30	3.00
13.11.77	15.00	to 19.30	4.30
14.11.77	8.00	to 20.00	
	22.45	to 24.00	13.45
15.11.77	5.55	to 13.30	
	15.00	to 17.30	10.00

16.11.77	6.55 to 21.30	14.35	
17.11.77	8.10 to 21.30	13.20	
19.11.77	7.45 to 23.45	15.15	
20.11.77	10.00 to 3.00	5.00	
24.11.77	17.30 to 19.00	1.30	
28.11.77	5.00 to 7.00	2.00	
29.11.77	12.10 to 15.08	2.58	
		88.00	
	December, 1977		
11.12.77	9.50 to 10.10	0.20	P.H. No. I Jui - Canal
24.12.77	8.10 to 8.20	0.10	
25.12.77	9.50 to 9.55	0.05	
		0.35	
	January, 1978		
8.1.78	8.30 to 10.00	1.30	P.H. No. I Jui - Canal
9.1.78	7.30 to 9.30	2.00	
10.1.78	7.00 to 10.00		

	6.30 to	7.30	4.00
28.1.78	7.00 to	1.30	6.30
31.1.78	8.30 to	6.00	9.30
			23.30

February, 1978

1.2.78	9.00 to	5.30	8.30
3.2.78	9.30 to	10.30	1.00
21.2.78	7.20 to	7.25	0.05
20.2.78	15.30 to	18.55	3.25
			13.00

Printing Press Haryana

***476. Chaudhri Des Raj :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state-

(a) the date on which togetherwith the name of the place where the printing press of this State was started by the Printing and Stationery Department, Haryana ;

(b) the year-wise detail of the quantity of the printing ink purchased for the printing press referred to in part (a) above since 1968 to date ; and

(c) the nature of the packages in which. the printing ink referred to in part (b) above is received ; if it is received in tins, the number of tins auctioned togetherwith the number of tins Tying for auction with the department at present ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(क) (1) राजकीय प्रैस सैक्टर– 1 8, चण्डीगढ अक्तूबर, 1970 में चालू किया गया ।

(2) राजकीय पाठ्य पुस्तक प्रैस, पंचकूला, जिला अम्बाला मार्च, 1974 में चालू किया गया ।

(3) मधुबनप्रैस नवम्बर, 1977 में पट्टे पर ली गई है ।

(ख) विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) (1) डिब्बों तथा ड्रमों में ।

(2) 90 ड्रमों की नीलामी की गई है और 97 खाली ड्रम नीलामी के लिए उपलब्ध हैं ।

(3) कोई डिब्बा नीलाम नहीं किया गया है और 1515 खाली डिब्बे प्रैसों में पड़े हैं ।

सरकारी प्रैस के लिए प्रिन्टिग स्याही की खरीद का विवरण

प्रैस का ना म	1970– 71	1971– 72	1972– 73	1973– 74	1974– 75	1975– 76	1976– 77	1977– 78
	(स्याही किलोग्राम में)							
प्रैस सैक्टर–	675	888¾	963	1089½	344	732½	870½	953

पंचकूला प्रैस	--	--	—	1693	3074	3966	3704
मधुबन प्रैस	----	----	-	---		--	स्याही चण्डीगढ प्रैस से भेजी गई है ।

Expenditure incurred on the arrival of Union Health

Minister

***463. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the expenditure incurred on the function if any, held in the Jail at Hissar when the Union Health Minister visited it on 8-2-1978 toetherwith the name of the Account Head to which it was debited ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(1) 9, 887 37 रुपए कुल खर्च ।

(2) 9, 175. 49 रुपए का खर्चा हैड'' 256 जेलज से'' ।

711. 88 रुपए का खर्चा बन्दियों के कैन्टीन फण्ड से ।

15.00 बजे

विशेषाधिकार प्रश्न

Mr. Speaker : I am making an observation

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । एक बड़ा जरूरी मसला है । एस.एस.एस. बोर्ड में बड़ा घपला हुआ है । हजारों पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । ट्रिब्यून में पहले पेज पर इसकी फोटो आई है ।

Mr. Speaker : Please take your seat. I am making an observation.

Hon. Members, I have received a notice of a question of breach of privilege from Chaudhri Shamsher Singh Surjewala, M.L.A. concerning making deliberately false and misleading statement by Col. Rao Ram Singh, Education Minister, in the House on the 9th March, 1978, to the effect that the former Defence Minister handed over Rs. 2 lakhs to his son, Shri Surrinder Singh, M.L.A., which was presented to him in a public meeting at Bawal for being donated to the local college. According to Shri Surjewala this amount was meant for party fund and not for any college as stated by the Education Minister. I have gone through very carefully the relevant portions of the debate of that date and find that Col. Rao Ram Singh repeated and emphatically reiterated his statement that the money presented to Chaudhri Bansi Lal would be donated to the local college but it was instead

handed over to his son, Shri Surrinder Singh, M.L.A., who immediately thereafter left in a car. The hon. Members will also agree that Col. Rao Ram Singh instantly accepted the challenge of Chaudhri Surrinder Singh, M.L.A., and the Vidhan Sabha records do not show that at any stage Col. Rao Ram Singh made any wrong statement. As such, Chaudhri Shamsher Singh's dubbing of the statement of the Education Minister as false and a deliberate lie has not been substantiated (voices from the Treasury Benches : Shame, shame) as required under direction 115(1) as used by the Speaker, Lok Sabha, requiring a member to point out to the Speaker the particulars of the mistake or inaccuracy in the statement. If it was so, Chaudhri Shamsher Singh Surjewala would have challenged the Minister there and then in the House. According to the 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul and Shakdher, page 252, it has been clearly stated that if any statement is made on the floor of the House by a member or Minister which another member believes to be untrue, incomplete and incorrect, it does not constitute a breach of privilege. **in** view of this, I refuse to give my consent to Chaudhri Shamsher Singh Surjewala to raise the question of breach of privilege,

Now, discussion on Demands for grants,

Rao Birender Singh : I just want a clarification, sir

Mr. Speaker : Clarification on ruling ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : No talk against your ruling, sir

Rao Birender Singh : I want a clarification on the ruling so that in future we might also become wiser. This ruling would mean, in my view, that a Minister or Chief Minister or any member for that matter

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट– आफ आर्डर हैकि क्या अध्यक्ष महोदय की रूलिंग आने के बाद उसके पर कमैंट या चर्चा हो सकती है?

श्री अध्यक्ष : वह तो नहीं हो सकती लेकिन मैंने अभी इनका सवाल नहीं सुना है कि क्या है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इस रूलिंग का जो असर होगा मैं उसके बारे में दरियाफत करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : Kindly talk to me in the Chamber (Interruption). **I** will explain to you the whole thing.

Shri Shamsher Singh : I gave notice of a Call Attention Motion regarding the S.S.S. Board affair today

Mr. Speaker : It is under examination. It has been received today.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, करन एक जरूरी मसला अखबार में आया कि एस. एसएस. बोर्ड के....

श्री अध्यक्ष : यह बात हो चुकी है । अभी मैंने इसी के बारे में बताया है कि मामला अन्डर कन्सीडेरशन है ।

अनुदानों के लिये सरकारी मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : According to the previous practice and in order to save the time of the House all the Demands for Grants appearing on the Order Paper will be deemed to have beenread and moved together. The Hon. Members can raise discussion on the Demands but while speaking they will have to indicate the Demand No. on which they want to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 31,82,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 5,50,52,260 be granted to the Governor . to defray the charges that will come in the course-of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand- No-2—general Administration.

That a sum not exceeding Rs. 14,56,57,480 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect cf the charges under Demand No.3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 3,64,74,080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 2,35,64,580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand, No. 5—Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 4,87,36,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 3,13,75,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 28,91,65,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 46,36,76,355 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 26,58,87,015 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for .the year 1978-79 in

respect of the charges under Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 79,31,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 2,62,77,235 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in

respect of the charges under Demand No. 12—Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 3,57,07,059 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 94,82,78,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 14—Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 1,24,84,21,230 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 4,07,95,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the 'course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 25,13,66,460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 5,74,93,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 55,38,920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in- the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 3,19,13,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 4,93,28,715 be granted to the Governor to deft ay the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in

respect of the charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 9,43,42,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 22—Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 41,75,72,426 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 13,30,310 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 51,72,17,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 25—Loans and Advances.

I have also received notices of cut motions to the various Demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, **I** will put the various cut motions to the vote of the House when the respective Demands are put at the time of guillotine. Such Members may, however, participate in the discussion.

Guillotine will be applied at 6.00 p.m.

DEMAND NO. 2

(MAJOR HEAD : 213—Council of Ministers)

1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 6,000/- on account of B—Sumptuary and other allowances be reduced by Re. **1/-.**

2. **Swami Aditya Vesh :**

That the item of Rs. 1,00,000/- on account of C—Tour Expenses be reduced by Rs. 50,000.

3. **Swami Aditya Vesh :**

That the item of Rs. 5,38,300/- on account of E—Discretionary grant by Ministers be reduced by Rs. 4,00,000/- .

4. **Swami Aditya Vesh :**

That the item of Rs. 5,67,500/- on account of F—Other Expenditure—Maintenance of the Ministers' Residence/Office— Cffice Expenses be reduced by Rs. 3,00,000/,

5. **Swami Aditya Vesh :**

That the item of Rs. 14,00,000/- on account of F,Other Expenditure (ii) Nrintenance and running of vehicles and Ministers' Car Section- Office Expenses be reduced to Rs. 4,00,000/-.

(MAJOR HEAD : 285—Information and Publicity)

6. **Swami Aditya Vesh :**

That the item of Rs. 10,03,280/- on account of H—Songs and Drama Services be reduced by Rs. 7,00,000/-.

7. **Swami Aditya Vesh :**

That the item of Rs. 10,45,070/- on account of I—Films be reduced by Rs. 7,00,000/-. (2—GENERAL **ADMINISTRATION)**

8. **Shri Surrender Singh :** That the demand be reduced by Re. 1/-.

9. **Shri Shamsher Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1/-.

DEMAND NO. 3

(MAJOR HEAD : 256—Jails) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 36,69,730/- on account of B--Jails-5(a) Other Charges and 5(b) Office Expenses be reduced by Rs. 20,00,000/-.

DEMANDS NO. 4 AND 16.

(MAJOR HEAD : 304—Other General Economic Services) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 24,01,200- on account of D—Economic Advice and Statistics be reduced by Rs. 15,00,000/,

DEMAND NO. 5

(MAJOR HEAD : 235—Collection of other Taxes on property and Capital

Transactions)

1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 70,000/- on account of Office Expenses be reduced by Rs. 50,000/-.

(MAJOR HEAD 239—State Excise)

2. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 2,61,600/- on account of Office Expenses be reduced by Rs. 2,00,000/,

(MAJOR HEAD : 240—Sales Tax)

3. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 11,01,030/. on account of B--Collection Charges--Office **Expenses** be reduced by Rs. 10,00,000/-.

DEMAND NO. 6

(MAJOR HEAD : 247—Other Fiscal Services) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 20,00,000/- on account of (iii) Awards to District—Other Charges be reduced by Rs. 15,00,000/-.

DEMAND NO. 7

(MAJOR HEAD : 258—Stationery and Printing)

1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 22,00,000/- on account of E—Cost of Printing by other Sources-(a) Private Presses and (b) Other Government Presses be reduced by Rs. 15,00,000/-.

(MAJOR HEAD : 465—Capital outlay on Stationery and Printing and other Administrative Services)

2. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 6,00,000/- on account of Purchase of Machinery be reduced by Rs. 5,00,000/-.

(MAJOR HEAD : 268—Miscellaneous General Services)

3. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 17,82,410/. on account of D—Other Expenditure be reduced by Rs. 15,00,000/-.

DEMAND NO. 8

(MAJOR HEAD : 259—Public Works)

1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 1,00,000/- on account of E—Furnishings be reduced by Rs. 80,000/-.

(MAJOR HEAD : 283—Housing)

2. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 90,000/- on account of C(vii) Lease Charges—Maintenance of the Ministers Residences Rent, Rates and Taxes be reduced by Re. 1/-.

DEMAND NO. 9

(MAJOR HEAD : 278—Art and Culture) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 22,80,585/• on account of Art and Culture be reduced by Rs. 15,00.000/-.

(9—Education)

2. Shri Surrender Singh :

That the demand be reduced by Re. 1/-.

DEMAND NO 10

(MAJOR HEAD : 281—Family Planning) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 2,19,65,000/- on account of Family Planning be reduced by Rs. I,00,00,000/-.

DEMAND NO. 11

(11—Urban Development)

1. Chaudhri Birinder Singh :

That the demand be reduced by Re. 1/-.

DEMAND NO 16

(16—Industries)

1. Shri Mange Ram Gupta : That the demand be reduced by Re. **1/,**

DEMAND NO. 17

(MAJOR HEAD : 308—Area Development) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 8,17,64,000/- on account of B-Dryland Development and D-Development of Desert Areas be reduced by Rs. 6,00,00,000/-,

DEMAND NO. 22 (22—Co-operation)

1. Chaudhri Birinder Singh :

That the demand be reduced by Re. 1/,.

DEMAND NO. 24

(MAJOR HEAD : 339—Tourism) 1. Swami Aditya Vesh :

That the item of Rs. 9,00,000/- on account of B-Tourist Information znd Publicity be reduced by Rs. 8,50,000/-.

राय दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़) : अध्शक्ष महोदय, आज डिमाड्ज पर डिस्कशन चल रही है

स्वामी आदित्य वेश : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । इस डिस्कशन होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने सदन के सामने 22 कट मोशन रखे थे । अपने नेताओं से बातचीत करने के बाद मुझे तसल्ली हो गई है कि भविष्य में इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा इसलिए मैं इन सारे कट मोशन्ज को वापिस लेता हूं ।

राव दलीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1 0। 1 1, 1 2, 1 5, 1 6, 20 और 22 के बारे में अपने कुछ विचार रखूगा । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, जो डिमांड नं. 4 है यह नैचुरल क्लाईमिटीज के बारे में यानी. रिलीफ देने के बारे में है । उपाध्यक्ष महोदय, हेल स्टॉरम से जिला महेन्द्र– गढ़ मेंकितना नुक्सान हुआ है, यह बात किसी से भूली हुई नहीं है । वहां के

बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वहां पर जो ओला गिरा, वह बहुत वजनी था । जो ओला गिरा वह एवरेज 250 ग्राम का था । इतने वजनी ओले गिरने से वहां पर फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हें । एक ईच भी ऐसी खेती या भूमि नहीं बची जहां नुक्सान न हुआ हो । वहां के गांवों में रात को दिया नहीं जलता और खाना बनाने केलिए चूल्हे में आग नहीं जलाई जा रही है । उस इलाके में इतना नुक्सान हुआ हैजिसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि वह कम सेकम एक हजार रुपया प्रति एकड के हिसाब से उन किसानों को मुआवजा दे जिनके खेत बिल्कुल तबाह हो चुके हैं । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि उनके कर्जे 8 महीने के लिए मुलतवी कर दिए जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि 8 महीने केलिए नहीं बल्कि 2–3 साल केलिए मुलतवी करदिए जाने चाहिएं । इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिला महेन्द्रगढ़ में एक स्पैशल एक्सपर्टस की टीम भेजी जाए जो कि वहां के खेतों, सायल और वाटर को एग्जामिन कर सके और बता सके कि खरीफ की फसल से पहले दूसरी कौन सी फसल की बीजाई की जा सकती है ताकि सरकार उस बीज का भी प्रबन्ध कर सके । इसके साथ–साथ तम्बाकू की जो फसल है, उस पर सैन्ट्रल एक्साइज 3 प्रतिशत पर के.जी. के हिसाब से है जो कि बडी भारी एक्साईज डियूटी है । मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूंकि राजस्थान में 100 किलोग्राम तक जमींदार खुद तम्बाकू इस्तेमाल कर सकता है और खुद इस्तेमाल करने के कारण 1 00

किलोग्राम पर एक्साइज डियूटी माफ कीहुई है । हमारे हरियाणा में रुपए प्रति किलो एक्साईज डियूटी लगती है और 36 किलोग्राम तक एक्साईज डियूटी माफ है । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उस बैकवर्ड इलाके में जहां हेल–स्टौर्म का प्रकोप है, वहां तम्बाकू पर एक्साईज डियूटी खत्म की जाए ताकि किसान फायदा उठा सकें ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो 10 लाख की ग्रान्ट है, सबसिडी है इसको और ज्यादा बढाया जाए, ताकि हर किसान को पूरी तरह से मदद मिल सके, किसानों की बुरी हालत है । डिप्टी स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ में जो फसलडैमेज हुई है, उसके मेरे पास कुछ फोटोग्राफज हैं। मगर आप इजाजत दें तो सैं हाउस की टेबल पर रखना चाहूंगा ।

Mr. Deputy Speaker : It is under examination. If it is *permissible then you can lay them on the Table of the House.

राव दलीप सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सदन के नोटिस में लाना चाहूगा कि स्माल सेविन का जो कम्पेन चल रहा है, इसका जमीदारों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ हेलस्टौर्म से बुरी तरह सेइफैक्टिड है । गवर्नमैंट ने एक करोड़ रुपया इकट्ठा करने का टारगैट रखा है । गवर्नमैंट के अफसरान ने यह सर्कुलर जारी किया है कि तुम्हारा सर्विस रिकार्ड खराब कर दिया जाएगा, अगर तुमने स्माल सेविंग

में पैसा इकट्ठा नहीं किया । (व्यवधान) कितनी बुरी बात है कि सरकारी अफसर सर्कुलर जारी करते हैं कि अगर कुलैक्शन का टारगैट पूरा नहीं किया तो उनकी सर्विस का कान्फिडैशवल रिकार्ड खराद कर दिया जाएगा ।

वित्त मंत्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, यह गलत बात है । यह पुरानी सरकार करती होगी लेकिन जनता पार्टी नेऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया ।

राव दलीप सिंह : अगर आप कहें तो मैं उन अफसरों के नाम बता देता हूं जिन्होंने सर्कूलर जारी किए हैए और जो सर्कुलर जारी किए हैं, वह बता देता हूं । (व्यवधान) आप सुनिए, मैं गलत नही बता0ंगा, यकीन रखें

श्री वीरेन्द्र सिंह : गलत तो हम भी नहीं बताते । (व्यवधान)

राव दलीप सिंह : सर्कुलर जारी हुआ हए और टीचर्ज और हैडमास्टर्ज को कहा गया कि तुम्हारा सर्विस रिकार्ड खराब करदिया जाएगा अगर तुमने रुपया इकट्ठा नही किया । पटवारी केलिए दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह हजार रुपए फिक्स कर दिए । हमारे यहां ओलों से भारी नुक्सान हुआ है, अगर उसके पास रुपया मांगने केलिए जाएंगे तो किसान कहां से अदा करेगा, किसान की कैपेसिटी ही नहीं है । इससे तो भ्रष्टाचार फैलेगा औरकुछ नहीं

हो सकता । इतना हैवी टार्गेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा है, यह बेबुनियाद है, इसको सरकार किसी तरह कम करे । सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं वह साधारण आदमी पर ही लगते हैं । ठीक है, सरकार टैक्स लगाए इसमें गुरेज नहीं, लेकिन सरकार रिलीफ जरूर दे । जैसे गवर्नमैंट इम्पलाईज हें, इनमें भी क्लास फोर हें, जैसे सफाई कर्म चारी हैं इनको कुछ न कुछ रिलीफ मिलना चाहिए । म्युनिसिपल कमेटियों में सफाई कर्मचारी बहुत गन्द उठाते हैं । मैं इस काम को गन्दा नही कहता, सबसे पवित्र काम कहूंगा क्योंकि ये कर्मचारी सारे शहरको पवित्र करते हैं । लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इनको कोई रिलीफ नही देती । इस बजट मे इनको कोई राहत नहीं दी है । गवर्नमैंट एम्पलाईज को जो इन्स्टालमैंट दी है, वह सितम्बर में देनी चाहिए थी लेकिन जनवरी से दी है, यह भी सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा भारी अन्याय है ।

डिप्टी' स्पीकर साहब, सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोगों से बड़े–बड़े वायदे किए थे लेकिन आज हम सप्लीमैंटरी डिमांड्क में देखते हैं कि अन एम्प्लायमैंट को दूर करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए । मैं आपकी मारफत सरकार से कहूगा कि पंजाब सरकार ने अनएम्पलायड लोगों को अनएम्पलायमैंट अला0ंस देना आरम्भ कर दिया है । ऐसे बेरोजगार लोगों को जो हरियाणा में रजिस्टर हैं, उनको भी अनएम्पलायमैंट अला0ंस देना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, मैने

गवर्नमैंट को एक बिल दिया जिसका मकसद था अन एम्पलायमैंट अलाकंस दे ना तथा एक इन्शयोरैंस स्कीम थी । अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको हाउस की टेबल पर लेकर दूगा ।

Mr. Deputy Speaker ; Please send your request and it will be examined If it is permissible, You can lay on the Table of the House.

राव दलीप सिंह : जो बेरोजगार हैं, हैंडीकैप्पड हैं उनको अन एम्पलायमैंट अलाउंस दिया जाना चाहिए....'

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर, माननीय सदस्य न रैलेवट बोल रहें हैं और न ही डिमाण्ड' बता रहे हैं । जिस तरह से गवर्नर एड्रैस और बजट परडिसकशन होती है वैसे बोल रहे है । आपडिमांड तो बताए कि– कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

राव दलीप सिंह : लेबरारेंड अन एम्पलायमैंट की डिमांड नं 1 2 है जिस पर मैं बोल रहा हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बिल दिया था और उस विल में मैंने प्रार्थना की थी कि मैट्रिकुलेट को 50 रुपए, मैट्रिकुलेट के पर वालों को 7 5 रुपए, डिप्लोमा होल्डज' को 1 25 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट को 1 50 रुपए, इजीनियर और डाक्टर को 200 रुपए अन एम्पलायमैंट अला0ंस दिया जाए । मेरी सबमिशन यह है कि जनता सरकार ने लोगों से वायदे किए थे कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे और अच्छे कदम उठाएंगे । उस बारे में सिर्फ एक स्कीम जारी की हैकि हरी–गले में कुछ

इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएंगे और उनमें कर्जा दिया जाएगा । ऐसी स्कीम महेन्द्रगढ़ जिले में भी चलाई गई थी लेकिन वहां के लोकल बैक्स इससे सहमत नहीं हुए और कर्जा दैते ही नहीं । किसी को कर्जा नहीं मित्रता । शायद यह स्कीम पेपर पर ही रहे, प्रैक्टिकली कुछ न हो, इससे रोज–गार मिलने की सम्भावना नही है ।

अब थोड़ा सा नेविगेशन के बारे में कहना चाहता हूं । महेन्द्रगढ़ जिला बहुत बैन–वर्ड है और इसमें वहुत बैकवर्ड क्लासिज हैं । हमारी एस्टीमेट कमेटी भी वहां देखने के लिए गई थी । वहां बहुत गरीब लोग है । जवाहर– लाल नेहरू कैनाल पर पिछले साल 14 करोड रुपया खर्च किया गया था लेकिन इस साल औजेन्ट गवर्नमैंट ने साढ़े 12 करोड़ खर्च करने का इरादा कियाहै । बैकवर्ड –एरिया में बजाय इसके कि ज्यादा पैसा दिया जाता उलटा कम कर दिया। यह बड़ी बेइन्साफी है । मेरी सरकार से दरख्वास्त. है कि इस रुपए को और बढ़ाया जाए ।

जहां तक को–आप्रेटिव डिपार्टमैंट का ताल्लुक है, इस पर, डिप्टी स्पीकर साहब, 500 करोड़ रुपए का वर्किंगकैपिटल लगा हुआ है और हरियाणा में इसका– रिकवरी सारे भारत में सबसे क्रूम है । इस डिपार्टमैंट में जो एम्वैजल मैंटस हैं, उनको दूर करने के लिए सही कदम उठाए जाएं ताकि साधारण आदमी कोफायदा पहुंच सके और सरकार की नीति पर अमल हो सके । इसके अलावा मैं सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहूंगा कि

लै.'ड डिवैल्पमैंट बैक और सैन्ट्रल कोमा प्रेटिव बैक, इन दोनों को मिलाकर एक ही बैक बना दिया जाए ताकि किसान को इन अग्र अ गा बैंकों में न जाना पड़े, इससे किसान को बड़ी सहूलियत हो जाएगी । मार्गेजें बैक जो टैक्स लेते हैं वे बड़े हैवी होते हैं । जब प्रॉपटी रहन रखते हैँ तो उसका मार्गेज डीड होता है, रजिस्टर्ड डीड होता है । इस डीड पर 4 परसैन्ट से ज्यादा इन्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान इससे ज्यादा अदा नहीं करसकता । जो आडिट डिपार्टमैंट है वह सब से ज्यादा कमजोर डिपार्टमैंट है, इसकी स्ट्रैथ कम है, इसको जितना मजबूत किया जाए उतना ही स्टेट को फायदा है । अगर आडिट डिपार्टमैंट मजबूत होगा तो एम्बैजलमैंटस नही होंगीं । यह नहीं होना चाहिए कि एम्बैजलमैट हो जाए औरउसके बाद कार्यवाही हो । जहां तक फोडर के रिलीफ का सवाल है, महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल को आज तक फोडर नहीं मिला जबकि यह तीन चार महीने पहले ही मि न जाना चाहिए था. । मैं सरकार से कहूंगा कि फोडर का जल्दी से जल्दी इन्तजाम क्रिया जाए ।

अब मैं डिमांड न. 20 पर बोलूंगा जो फॉरैस्ट के बारे में है । जहां तक वाईल्ड लाईफ का ताल्लुक है हमारे इलाके में नील गाय ने बड़ी तबाही मचाई हुई है । किसान की सारी फसल तबाह कर दी है । मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि इस तरफ खास कदम उठाए जाएं । या तो उसको मारने की इजाजत दीं जाए या कोई अलग नरसरी खोलकर उसको कन्फाईन कर 'दिया जाए क्योंकि

नील गाय के झुण्ड के झुण्ड निकलते है और सारी फसल तबाह कर देते हैं । इसलिए या तो उनको मारने की इजाजत दो जाहू या कोई और इन्तजाम किया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक रोडज और वाटर सप्लाईज स्कीमज कौ सवाल है, इस के बारे में तो मिनिस्टर साहब ने मान लिया है कि महेन्द्रगढ़ के इलाके में न कोई सड़क और न कोई वाटर सप्लाई की स्कीम इए ने का विचार है । लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि उस बैकवर्ड एरिया के साथ इस तरह का सलूक न कीजिए । इधर तो भाखडा और वैस्टर्न जमुना का पानी खेतों को लगता है लेकिन हमारे यहां ऐसी बात नही है । यहां के पशुओं को तो बरसीम आदि खाने को देते हैं लेकिन वहां तूड़ी भी नही मिलती । इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे साथ स्टैप मदरली ट्रटिमैंट न करें बल्कि बराबर का समझते हुए डिवैलमैंट का हर काम करने का विचार करें ।

जहां तक लेबर का सवाल है, डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि दादरी में मजदूर पाई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे । ऐसा ही झगड़ा हिसार टैक्सटाई.ल मिल में चल प्रा है । सोनीपत में तो एक वर्कर मारा भी गया ।

डिप्टी स्पीकर साहब शराब के ठे के पहले ऑक्शन हुआ करते थे लेकिन उस सिस्टम को अब इन्होंने बन्द करदिया है ।

मैंतो यह कहूंगा कि अगर खुली आक्शनं नही हुई तो भ्रष्टा– चार के सिवाए और कोई बात नहीं होगी । पहले ठेके खुले आम होते थे । अब केवल दस बीस ऐप्लीकेशन्ज लेंगे । ऐप्लीकेशन्ज की फीस पांच सौ रुपए रखीं है और वह रिफन्ड भी नहीं होगी । कितने लोग ऐप्लाई करेंगे? बड़े भारी कुरंप्शन के चांसिज हैं । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करे वरना इससे सरकार को भी हानि होगी और भ्रष्टाचार भी फैलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने फरमाया कि फलैट रेट करेगे । यह बात ठीक है । लेकिन इसमें मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा । महेन्द्रगढ, भिवानी और गुडगांव के इलाके ऐसे हैं जहां पानी बहुत गहरा है और मीटर भी केवल रबी के टाईम में दो तीन महीने के लिए चलते हैं । हिसार और करनाल आदि में जीरी और दूसरी फसलों के लिए भी चलते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है इसलिए मेरी यह–प्रार्थना है कि यह फलैट रेट महेन्द्रगढ़, भिवानी और गुड़गांव के लिए बाकी जगहों की बनिस्वत आधा होना चाहिए । (विध्न)

एजुकेशन के बारे में, डिप्टी स्पीकर साहब, में आपकी मारफत कह कहूंगा कि अहीर स्कूल्ज और अहीर कालेजिज के लिए राजनीतिक बदले की भावना से ग्रांट बन्द कर दी गई है । यहबात उचित नहीं है । यही नहीं, सरकार नेएक और निर्णय भी लिया है कि ये काले– जिंज को अपने कन्ट्रोल में लेंगे । डिप्टी

स्पीकर साहब, मैं आपके सामने यह कहूंगी कि वे संस् थाए बड़ी मेहनत से बनाई गई थी और उन संस्थाओं से बहुत लोगों ने फायदा उठाया है । मैं भी इन संस्थाओं का विद्यार्थी रहा हूं । हमने अच्छी तालीम वहां पाई । हमारे जो उस्ताद होते थे वे बड़े अच्छे तरीके से तालीमदे ते थे । इसलिए मैं यह प्रार्थ ना करना चाहता हूं कि ऐसी राजनीतिक बदले की भावना दिल में रखते हुए अगर यह सरकार एजुकेशनल इंस्टीच्यूट्स में दखल देगी, तो एजुकेशन का मयार नीचे गिरेगा । वहां जाना चाहिंए वाईस चांसलर, लेकिन डीपीआई. आफिस से डिप्टी डायरैक्टर जाते हैं या कोई और जाता है और इंस्टीच्यूट्स में दखल अन्दाजी करते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो टैम्पल आफ एजुकेशन हें और उनकी डिगनिटी कायम रखी जानी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, कुछलैक्चरारज अपनी तालीम बढ़ाने के लिए, डाक्टरैट वरने के लिए, इजाजत मांगते हैं लेकिन वह दी नहीं जाती । मैरी यह प्रार्थना है कि उनको इजाजत दे दी जानी चाहिएं ताकि उनको भीइस बात का फायदा. हों और डिपार्टमैंट को भी लाभ हो । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करतो हूं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा (थानेसर) : डिप्टी स्पीक्र साहब, मैं डिमांड नं 2, 9, 10 और 21 के पर बोलना चाहता हूं । सबसे पहले मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा । इसमें एक बात देखने में आ रही है । लोग परेशान भी है । वह बात यह है कि

जनता सरकार बनने के बाद ट्रांसफर पालिसी के तहत लोगों पर इतने जुलम हो रहे हैं और क्रप्शन दिन प्रतिदिन बढ्ती जा रही है, जिसका कोई हिसाब नही । एक आदमी तो दस–दस साल सेएक जगह बठा हुआ है लेकिन दूसरे आदमी की. एक 'दिन तो एक जगह ट्रांसफर की जाती है लेकिन अगले ही दिन उसे दूसरी जगह फैंक दिया जाता है । अफसरों को गेंद समझा हुआ है । भला आप हीं बताएं कि कर्मचारीगण कैसे काम करेंगे? वे समाज को क्या दे पाएंगे? क्या वे कुछ भला कर पाएंगे? जय प्रकाश नारायण जी ने इस देश में इतना बड़ा आन्दोलन आरम्भ किया और उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि उनका यह मूवमैंट बे सिकली क्रप्शन के विरुद्ध था । मैं भी जे. पी. की ऐन्टी क्रप्शन आन्दोलन की देन हू । इसी. तरह हमारे मु ख्य मन्त्री जी. ने जिस दिन शपथ ली थी तोउन्होंने कहा थाकि 'क्रप्शन बन्द हो, पानी का प्रबन्ध हो' लेकिन क्रपशन कितनी ज्यादा हरियाणा में हो गई है इसका एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूं – (विध्न) ।––

राव बीरेन्द्र सिंह : अब तो यह हो गया है कि 'क्रप्शन का प्रबन्ध, पानी बन्द (हंसी)

श्री देवेन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहे रहा था कि कुछ खास लोगों की प्रमोशन करने के लिए बहुत बडे तबके को इग्नोर किया जाता है । एक आदमी की प्रमोशन क्रने के लिए, किसी खास आदमी की प्रमोशन केलिए बहुत लोगों को इग्नोर

किया जाता है.. (विध्न) पुलिस डिपार्टमैंट में प्रमोशन हुई । मेरे से आप नाम मत पूछे ।

चौधरी संत कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । माननीय सदस्य एडमिनिस्ट्रेशन के पर एक बड़ा इल्जाम लगा रहे है । इनको कम से कम कोई कंकरीट एग्जाम्पल देना चाहिए (विध्न) ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह चुका हूं कि पुलिस डिपार्टमैंट में एक आदमी की प्रमोशन केलिए कई आदमियों को इग्नोर किया गया । मैं स्पैसिफिक डिपार्टमैंट क नाम लै रहा हूं । अगर मेरी इस बात को कोई चौलेंज. करे, तो मैं फैक्ट्स और फिर्ग्ज दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे मालूम हुआ है कि हमारी सरकार डिस्ट्रिक्ट्स री–आर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ विचार कर रही. है । कुछ और नए जिले बनाए जाने की प्रपोजल है । लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सोनीपत, सिरसा और कुरुक्षेत्र जो नए जिले बने हैं, उन जिलों की डिवैल्पमैंट की तरफ ही पूरा ध्यान नही दिया जाता । मेरे जिले में न तो पुलिस लाईन है, जिससे 24 घंटे काम लेने की बात है, न मैडिकल फैसेलिटीज हैं, न आफिसर्ज के रहने का इन्तजाम हैऔर नऔर पूरी सहूलियतें आज तक हम दे पाए हैं ।

भला आप ही बताएं कि अच्छे आफिसर्ज वहां क्यों जाएंगे जब वही उनको पूरी सहूलियते ही न हों? वे कैसे जिले की तरक्की के बारे में सोचेंगे और कैसे अच्छे काम करेंगे और क्या वे समाज का भला कर पाएंगे?

अगली बात, डिप्टी स्पीकर साहब., मैं एजुकेशन की करूंगा । यह डिमांड नं. 9 है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बहुत पहले एजुकेशन के मसले को लेकर अपनी सरकार से यह सवाल उठाया था कि हरियाणा में हरिजन कल्याण निगम है, सोशल वैल्फेयर बॉडी है, और तरह–तरह की वैलफेयर बॉडीज हैलेकिन स्टेट लेवल भर कोई स्टूडैन्ट वैलफेयर बॉडी नही है । मेरी–इस रिक्वैस्ट केबाद एक सब कमेटी बनाई गई लेकिन मैं समझता हूं मिय वह कमेटी स्टू– डैन्ट वैलफेयर से कोई वास्ता नहीं रखती । डिप्टी स्पीकर साहब, जिन लोगों ने पहली सरकार से लड़ाई लड़ी और उस राज को उखा डू फैका –फिर हमें इस काबिल बनाया कि हम जनता पर राज करें, उनको अगर आज भी' इग्नोर किया जाता है तो यह अच्छी बात नही । यह बात ज्यादा दिन तक नही चलनी चाहिए वरना स्टूडैन्ट्स कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राव साहब ने एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन्ज का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि वे अहीर कालेज के स्टूडैन्ट रहे है । मैं भी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का यहां जिक्र करना चाहता हूं जिसका मैं स्टूडैन्ट रहा हूं और आज भी

स्टूडैन्ट हूं । उस यूनिवर्सिटी कों इस कदर इग्नोर किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं । वाईस चांसलर के बारे में मैं कई बार अखबारों में दे चुका हू, चीफ मिनिस्टर साहब से पर्सनली मिल चुका हूं, गवर्नर साहब को लैटर लिख चुका हू लेकिन अभी तक उस यूनिवर्सिटी का बाईस चांसलर नही लगाया गया । मैंने काल अटैन्शन मोशन भी दिया था लेंकिन वह भी ऐडमिट नहीं हुआ । इतना गदर आज यूनिवर्सिटी में हो रहा है जिसका कोई हिसाब नही । वहां न तो एकेडैमिक एटमांसफियर है, न ठीक से पढाई चल रही है और न ही कोई सही तरीके से काम हो रहा है । इसके अलावा प्रो–वाईस–चांसजर, रजिस्ट्रार, अकाउट्स आ फिसर और दूसरे जे'।. औफिसर्ज हैं, वे एड–हॉक एप्वायंटमैंट पर हैं, वे सब पूरा काम नहीं कर सकते । यही बात नही, उपाधयक्ष महोदय, हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आ फ– तक वाईस चांसलर्ज एक खास तरीके से अप्वांयट किए जाते रहे हैं । उभेंको अप्वांयटमैंट का अब कोई अलग तरीका हे (ना चा हिए । वाईस चांसलर एंड रजिस्ट्रार को अप्वायटमैंट के लिए पैनल सैट होता है, फिर उसमें तीन नाम दिए जाते हैं, इनमें से ही लगाया जाता है । (विध्न) इसलिए मेरी अपनी' सरकार से यह गुफारिश है कि वाईस चांसलर की अप्वंत्यंटमैंट जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आज तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाईस– चांसलर शिडयूल्ड का स्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज में से नही लिया गया है इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बा र वाईस चांसलर उनमें से लिए जाए और यह

अप्वांयटमैंट प्योरलो ऐकेडैमिक बेसिज पर होनो चाहिए, कोई राजनैतिक आदमी वहां नही भेजा जाना चाहिए । मैं बड़ अरब से दर– ख्वास्त करता हूं कि अगर वहां कोई 'राजनैतिक आ दबा चला गया तो वहां की पढ़ाई का एटमासफियर खराब हों जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, हम करैक्टर बिल्डिग की बात करते हैं, हम मौरल स्टैण्डर्ड को रेज करने की बात करते है, स्टैण्डर्ड आफ जजमैंट 'की बात करते हैं लेकिन इनमें से कोई भी बात नही हे.।. सकेगी जब तक हम यूनिवर्सिटीज में रिफार्म की बात नहीं करे गे । हमारे यहां एक छोटीसी बॉडी. बनी हुई है– एजुकेशन एडवाईजरी बॉडी, लेकिन इस एजुकेशन एडवाईजरो बॉडी का कोई फायदा नही है क्योंकि इसके सुझावों पर कोई अमल नहीं किया जाता । मैं भी उसका मैंबर हूं । मैंने उसमें कुछ सुजैशन्ज दी थीं । वे मान तो ली गई और सबने उनकी तारीफ की और कहा विय बड़ी मेहनत से लिखा गया है लेकिन कहा गय–। कि उन्हें लागू नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पैसा नहीं है । प्लानिंग इस किस्म की है कि एजुकेशन पर पूरा पैसा नहीं लगाया जा रहा है । इसालिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज प्लानिंग इस किस्म से की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा रिफार्म एजुकेशन में किया जा स.के । मैं तो यह भी दरख्बास्त करूंगा कि एक हाई पावर्ड एजुकेशन बॉडी– यह). बनाई जाए । जिसके सुझावों पर अमल किया जाए । उसके दिए हुए सुझावों पर अमल न किया जाए तों उसका कोई लाभ नही है ।

एजुकेशन के बारे में कुछ नए सुझाव देना चाहता हूं और पहले भी दूसरे सुझाव दिए थे । स्कालरशिप के बारे में कुछ सुझाव हाउस के सम्मुख रखना चाहता हूं । प्राइमरी, सैकिन्डसे और हायर एजुकेशन के लिए खो–पैसा रखा गया है उसमें यह नही बता या गया कि प्राइमरी को कितना पैसा दिया जाएगा, सैकिण्डरी एजुकेशन को कितना दिया जाएगा और हा बर एजुकेशन को कितना दिया जाएगा. । कोई रेशे'। नहीं रखी गई है । निश्चित अनुपात नहीं रखा गया है कि कितना–कितना पैसा कहां पर खर्च होगा, कुछ नही बताया गया ।

इसी प्रकार से जब मैंने पेज 97 से 1 00 तक के'।' पढ़ा तो उसकों पडने से मालूम हुआ कि एडमिनिस्टेरशन और डायरैक्शन पर ज्यादा खर्चा किया जाता है, पढाई का प्रबन्ध करने के लिए पूरा पैसा खर्च नहीं किया जाता है । दूसरी चीज' जे । मैं कहना चाहता था कि स्कालर– शिप मैरिट बेसड नहीं होना चाहिए बल्कि नीड बेसड होना चाहिए । स्कालरशिप उन लोगों के'? दिए जाए जिनको जरूरत है । जरूरतमन्द लोगों को पैसा मिलना चा हिए । मैं राक उदाहरण देना चाहता हू कि आमतौर पर मैरिट में वे लोग आते हैं जिनके माता–पिता की ओर से पूर्ण रूप से सहुंलियते मुहैया की जाती है । देहातों से किसान के बच्चे मैरिट में नहीं आ सकते । उनको न किसी प्रोफैशनल कोर्स में एडमिशन ही मिलता है और न ही किसी. कम्पीटीशन में आ सकते हैं । अगर गरीब बच्चे को स्कालरशिप से इग्नोर किया जाएगा तो

वह आगे पढ़ नहीं सकता । इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि स्कालर–शिप नीड बेसिज पर हो न कि मैरिट बेसिज पर हो ।

अब मै स्पोर्टस के विषय में कुछ अर्ज करना चाहता हूं.. ...

डाक्टर इज मोहन गुप्ता : आन ए प्वांयट आफ अर। र्डर, सर । यह जो उन्होंने कहा किं बेसिज पर स्कालरशिप होना चाहिए, यह ठीक नहीं है । अगर मैरिट बेसिज पर स्कालर– शिप नही दिया जाएगा तों लोग डिस्केज होंगे, मौरट दे सिफ. पर होगा तो इन्क्रेज होंगे । यह कहना कि गरीब आदमियों के बच्चे मैरिट पर नहीं आते हैं, यह गलत बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में न बोले, आपके समय दिया जाएगा तब इस विषय से बोलना ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : डाक्टर साहब गलत समझ गए हैं । वे इस बात को गौर से समझें । मैं स्टूडैन्ट हू, मैं जानता हूं । आप भी स्टूडैन्ट थे लेकिन बहुत दिन हे'।' गए हैं । अब आप उन बा तों को भूल गए हे. । डाक्टर साहब मैं गांव. का रहने वाला हू, मुझे पता है । मेरा शू आउट अच्छा कैरियर रहा है । इसलिए मैं कह रहा था कि सोटैस को इग्नोर किया जा रहा है । उसको ड्यू एम्फेसिज नही दिया जा रहा है । किसी नौकरी में या किसी' प्रोफैशनल कोर्स में कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा हैं । हिसार में स्पोर्ट कालेज चालू किया है । वह किस लैवल से चल रहा है, उस

पर हमारी सरकार गौर नहीं कर पा ई है । हमारे यहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट डिपार्टमैंट अलग से है । वहां पर हैड आफ दी डिपार्टमैंट का क्या हाल है? अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर से बा त करते हैं तो वे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे अधिकार में नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किसके अधिकार में है? वहां पर किस के अधिकार लागू होगे । यदि वहां पर बाईस चांसलर लगाना हो तो गवर्नमैंट की मर्जी के बिना लगता ही नहीं है । यूनिवर्सिटी में सुधार करने की बात की जाए तो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है । तो वहां पर किस ने सुधार करना है । सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए ।

इसी प्रकार से जहां तक टैक्नीकल एजुकेशन का सम्बन्ध है उस बारे में जो काम करना चाहिए वह हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं । जब आप औरिएंटिड एजुकेशन की बात करते हैं, उसकी ओर भी कोई ध्यान नही– दिया जाता है । इस पर कोई प्लान नही बनाई गई । हमारे यहां टैक्नीकल रीजनल इंजीनियरिंग कालेज हैं, मैं समझता हू उनकी अभी तक हम पांच परसैन्ट भी समस्या का समा धान नही' कर पा ए हैं । वहां पर प्रोफैसर, स्टूडैन्ट्स, नान–टीचिंग स्टाफ या क्लास फोर्थ एम्पलाईज जो. हैं, वे सब के सब दुखी हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हू कि वे लोग परेश। न हैं । मुझें वहां की एक एक बात वय। पता है, वहां पर बड़ी भारी दिक्कतें हैं, उनकी समस्याओं को पांच परसैन्ट भी हम आज तक हल नहीं कर पाए हैं ।

इसी प्रकार से नीलोखेडी के अन्दर आईटी आई. टी. आई. वहां पर बैटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नही बैटर टीचिंग का इन्तजाम है । मेरी दरख्वास्त है कि बैटर एडमिनिस्ट्रेशन और बैटर टीचिंग के लिए प्रबन्ध किया जाए ।

सबसे बड़ी बात एक और कहने जा रहा हूं । स्टूडैन्ट्स पर बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं कि वे वायलैन्ट हो जाते हैं मगर आज तक किसी ने कारण नही सोचा है कि वे क्यों वायलैन्ट हैं? ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं । ये उल्टा सुल्टा करने के लिए बेबस क्यों होते हैं? वे सब इसलिए करते हैं कि उनको सोशल जस्टिस पूरा नहीं मिलता है । जौब ओरिएंटिड एजु– केशन हम आज तक नहीं दे पा ए है और न ही कोई स्कीम बना पाए है । एजुकेशन इस किस्म की हो जिसका समाज की आवश्यकताओं से ताल्लुक हो, समाज की डे–टू–डे लाइफ से कुनैक्शन हो । एजुकेशन में मोरल एथिक्स पर अधिक जोर दे कर नही चलेगे तो उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा । स्टैण्डर्ड आफ जजमैंट और करैक्टर पर जितना हम ज्यादा जोर देंगे उतनी ही हमारे आगे आने वाली पीढिया आगे बढ़ पाएगी । अभी पिछले दिनों जब केन्द्रीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री पी.सी. चुन्दर ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में ऐलान किया कि 60 परसैन्ट से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडैन्ट्स के एजुकेशन डिर्पाटमैंट 250 रुपए तक स्कालरशिप देगा परन्तु हम। री सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, और न ही कोई विचार किया है उनको लेन। चाहिए । हमारे यहां

पर स्टूडैन्ट्स कों इग्नोर किया जा रहा है । हमारी सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए । पंजाब और बंगाल में अन एम्पलायमैंट की कुछ बात की है चा हे उन्होंने कोई कमीशन बनाया या किसी किस्म की बात सोच रहे है लेकिन हमारे बजट में अन एम्पलायमैंट को खत्म करने की कोई बात नहीं सोची गई है । अन एम्पलायमैंट के बारे में कोई भी एनक्रेजिंग प्लान नहीं है ।

इसी प्रकार से टैन पलस टू के फार्मूला के बारे में बजट में कहा गया है । उसके बारे में हमारी सरकार आगे क्या कदम उठाएगी और वे कही–कहां पर खोले जा रहे हैं इसका कोई जिक्र नहीं है । आगे सरकार क्या करेगी कुछ भी पता नहीं लगता है ।

अब मैं थोड़ा सा हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । हरियाणा और पंजाब देश के अन्दर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सब से आगे हैं । पहले नम्बर पर पंजाब है पौर दूसरे नम्बर पर हरियाणा आता है लेकिन हरियाणा के अन्दर हैल्थ और मैडिकल की बुरी हालत है । हरियाणा में कुल खर्च पिछले साल 1 1 5 परसैन्ट था, परन्तु इस बार इसके। बढ़ा कर 14. 3 परसैन्ट कर दिया मगर मैडिकल पर पिछले साल 27. 6 परसैन्ट खर्च किया और इस साल 1 5 6 परसैन्ट होगा । पहले से मैडिकल और हैल्थ पर खर्चा कम करना शुरू कर दिया है । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर, सब सैन्टर की संख्या दो हजार आदमियों परएक है जब कि मद्रास औंर

महाराष्ट्र हरियाणा से बहुत आगे हैं । इण्डिया की एवरेज बारह हजार है और पंजाब तो इससे भी आगे है । हमारे यहां हरियाणा में एक लाख आदमियों केलिए एक बिस्तर कीव्यवस्था है । यह देश में बहुत नीचे है । बिहार और आसाम प्रान्त को छोड्कर सभी स्टेट्स से नीचे है ।

इसी तरह से सोशल वैलफेयर और कम्युनिटी सर्विसिज की बा त है । पिछले साल 13. 3 परसैन्ट रुपया–सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर खर्च किया गया था परन्तु इस बार घटा कर 9. 6 परसैन्ट किया गया है । डिप्टी स्पीकर साहब जिन को हम यहां पर बार–बार पिछड़ी जातियां कहते हैं, वे हमारी समाज की रीढ की हड्डी हैं । जनता पार्टी भी उनको रीड की हड्डी मान कर चली है मगर उनके। क्यों इग्नोर किधा जा रहा है, उनकी ओर कोई खसरू छगन क्यों नही दिया जा रहा है? उनके'। पर उठाने के लिए कोई खास कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इस दृष्टि से हमारा राज्य काफी पीछे होता जा रहा है । इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, इरीगेशन और इलैक्ट्रिसिटी की बात है । मैं समझता हूं कि इरीगेशन और इलैक्ट्रिसिटी इकौनोमीकल बेसिज पर चलते हैं, कमर्शियल बेसिज पर चलते हैं । अगर उनमें घाटा है, तो मैं समझता हूं कि जो रेट स्ट्रक्चर हैं वह इकौनोमिकल प्रिंसिपल्ज पर आधारित नहीं है ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : पानी तो कमर्शियल बेसिज पर नहीं देते हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : बिजली तो देते होंगे । मान लो अगर एक यूनिट बिजली हम 1 5 पैसे में पैदा कर रहे हैं, तो किसी जगह पर हम इसे 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देने लग रहे हैं तो किसी जगह पर हम 4पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देने लग रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । यह गड़बड़ क्रूब तक चलेगी । यह बात मैं देहात के लिए कह रहा हूं । देहात की बात आज भी की जा रही है । आज इनएफीशिएंट मैनेजमैंट है । उसमें भी आज कई बार गड़बड पैदा हो जाती है । लेबर प्रॉबलम कई बार पैदा हो जाती है । वहाँ पर उस समस्या को सुलझाने की कोई कोशिश नही की जाती', ताकि पहले ही स्थिति को संभाल– लिया जए । जब तक कहीं हडताल नहीं हो जाती तब तक मामला सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती । अप्वांयटमैंट के बारे में तो मैं समझता हूं कि आजकल भी उसी तरह सेही चल रहा है जिस तरह से पहले राज में चल रहा था । इनकम्पीटैन्ट और इनएफीशिएंट आदमी अम्पायट ए जा रहे हैं । पहले भी ऐसे ही आदमियों को अप्वांयट किया जाता रहा है । इसकी वजह से काम में सुधार होने की बजाय, यहांपर बड़े पैमाने पर नुक्सान हो रहा है । यही नहीं, वहां पर एक और दिक्कत है । जो वार्न आउट मशीनरी है, जिसमें तारे' आती हैं और जनरेटर वगैरा आते है, वहां पर रेट स्ट्रक्चर की वजह सेऔर घाटा होने की वजह से यह नहीं बदली जा सकती । जनरेटर हम नए नहीं दे पाते क्योकि पहले ही घाटा हो रहा हे । इससे फैक्ट्रियों में, दफतरों में काम करने वाले लोगों और किसानों को बहुत नुक्सान हो रहा है । मेरा सुझाव है इस

बारे में सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए । बिजली की कई जगह चोरी होती है । मीटरों को कई बार पीछे घुमा ेएते है और नई बार तारे' सीधी डालकर डायरैक्ट कुनैक्शन से बिजली की चोरी करते है । अतः मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस तरफ खास ध्यान दिया जाना चाहिए । इन्ही आईटमज पर मैंने बोलना था । धन्यवाद ।

चौधरी गंगा राम : (गोहाना) माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमाण्ड न. 4 पर बोलना चाहता हूं । डिमाण्ड नं 4 में रेवैन्यू आता है । मोटे तौर पर इसमें तीन चीजे आती हैं । नम्बर एक पटवारी आता है । नम्बर दो हमारी फर्द आती है जिसमे खसरा गिरदावरी और जमाबन्दी की फर्द शामिल है । नम्बर 3 पर इसमें किसान आता है । मैं इस डिमान्ड पर एक दो बातें ही कहना चाहूंगा । आज किसान को सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई मसला कर रहा है तो वह फर्द लेने वाला मसला है । इस मामले में पटवारी आता है । इसलिए मैं सरकार के सामने एक सुझाव रखुगा कि सभी जामें–तें हैं कि किसान जिस समय अपनी फर्द लेने केलिए पटवारी के पास जाता है तो असल में पटवारी किसी को भी मिलता ही नही । दो दो महीने हो जाते हैं । कोई पटवारी गांव के अन्दर रहता ही नही । सभी पटवारी जो हैं, अपने गांव को, अपनी डयूटी के स्थान को छोड्कर इधर–उधर शहरों में फिरते रहते हैं । इसके अलावा किसान बेचारे को यह पता ही नहीं होता कि 5 किल्ले की फर्द लेनी है तो उसके दाम उसने 5 रुपए

देने हैं या 400 रुपए देना है । आजकल सरकार ने किसान को पटवारी की मन मर्जी पर पटवारी के रहम पर छोड़ रखा है । मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा जैसा कि आप जानते है किं अदालत के अन्दर जब एक फैसला होता है तो उस फैसले की नकल लेनी होती है तो किसान उस नकल को लेने के लिए एक फार्म भरता है उस पर टिकट लगता है प्रैसकाइब्ड फीस का टिकट लगाता है और उसको नकल मिल जाती है । इसी तरह से मैं यह चाहूंगा कि चाहे किसी तरीके से हमें करना पड़ूं हमयह कर दें कि किसान को जिस कित्ते को फर्द लेनी हो, जितनी जमीन की फर्द लेनी हो, उसका एक फार्म भर कर तहसीलदार के पास दे आए । तहसीलदार जो है उसी टाइम पर किसान को यह बता दे कि इतने किल्ले पर इस हिसाब से इतने रुपए फीस लगेगी । वहां पर वह किसान तहसीलदार के पास रुपए दे आए और उसकी उसके पास रसीद दे दी जाए । तहसीलदार साहब उसे यह बता दें कि 15 दिन के बाद फला दिन को आना और फिर फर्द ले जाना । इस दौरान में किसान. अपने खेत मं जाकर काम करे । तहसीलदार जो है पटवारियों को अपनी कोर्ट के अदर बुला. ले और वहा पर जितनी नकलों के जिए दरख्रास्तें आई हैं, वह सारी फर्दे पटवारी तैयार कर ले और जब वह मुकर्रर डेट को आए तो उसको फर्द पकड़ा दी जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह से मैं समझता हूंकि किसान की जो लूट होती है, उससे उसे बचाया जा सकता है । मैं यह समझता हूं कि जो मैंनेबताया है, वह सिस्टम लागू किया जाना चाहिए । इसके अलावाइरीगेशन के

मामले में मैं आपके सामने कुछेक बाते रखूंगा । मैंने कई सवाल भी पूछे थे । यह डिमान्ड नं 1 5 है । मैंने यह बात कई बार पूछी है कि यह मान लो कि एक टेल पर 100 किल्ले है । यह रूल के अन्दर लिखा हुआ है कि किसान वाटर चार्जिज तभी दे ने का अधिकारो होगा जब साल के अन्दर उसकी एक फसल को तीन पानी मिल जाएं । लेकिन आज हरियाणा के अन्दर हो क्या रहा है? एक मोरी के पर 100 किल्ले है और उस मोरी में सारा साल जितना पानी आया है, अगर उसकी माता को लें और तीन पानी देने के तहत कितने पानी आएं, उसकी बात को लें तो आपको यह सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि एक किसान आज जो 50 प्रतिशत वाटर टैक्स दे रहा है, वह वगैर पानी आए ही दे रहा है । कोई पानी उसको नहीं मिलता लेकिन फिर भी वहं वाटर टैक्स देने लग रहा है । तो मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा क्योंकि यह किसानों की सरकार है, देहातियों की सरकार है, कि यह जो पुराना डिफैक्ट है, यह जो पुरानी गलती है, इसको सरकार दूर करे । मैं यहं भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने पटवा–रियो की मारफत सेपूरी तरह से यहँ अन्दाजा लगाए कि साल के अन्दर कितना पानी आता है और यह तीन बार पानी देने में यह पानी कितना एरिया. इरी ओट कर सकता– था । मेरे विचार में उतने एरिया से ही वाटर चार्ज लिया जाना चाहिए । इसके अलावा आज वही पुराना धक्का किसान के साथ चल रहा है । आज भी आप किसी गांव के अन्दर चले जाइए । सबसे पहली जो शिकायत आपको मिलेगी वह मोघों के बारे में होगी । जो शिकायत मिलती

है वह यह मिलती है कि ओवरसीयर साहब जो हैं, यह किसान के मोवों को कभी तोसीमेंट लगाकर छोटा कर देते हैं तो कभी जब उसे 500, 800 या 1000 रुपए मिल जाते हैं तो सीमेंट हटा देते हैं । लेकिन दो तीन महीने के बाद फिर सीमेंट लगा देते हैं । अगर किसी किसान को, किसी गांव को यह 'बिल्कुल ही पता न हो कि हमारे मोवों की लम्बाई चौड़ाई महकमों की तरफ से कितनी मन्जूर है, तो आप ही सोचिए कि वह ओवरसीयर के रहमो–कर्म पर ही तो जीएगा । तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि गांव के अन्दर किसान को यह पता होना चाहिए कि मोघे जो महकमा की तरफ से हैं, इनकी लम्बाई चौड़ाई इतनी होगी क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं । वह पानी घट जाए तो ओवरसीयर से कहता है । ओवरसीयर यह कह देता है कि महकमे ने पर से ही घट कर दिया । इस तरह से इस समस्या का हल नहीं हो सकता कि जब तो उसकी जेब. गर्म हो जाए फिर तो मोघे चौड़े हो जाए' और न दे तो बन्द हो जाए । मैं आज सरकार को यह बताना चाहता हूं कि किसान के साथ जो लूट हो रही है, उसमें कोई भी फर्क नही आया है । मैं यह चाहता हूं कि उसे इस लूट से बचाने के लिए कुछ एलीमैंट्री चीजे, कुछ मोटी–मोटी चीजें बता दी जाएं तो बेहतर होगा । इसके अलावा मैं एजुकेशन के बारे कहना चाहूंगा । आज हरियाणा में एजुकेशन के पर खर्च कितना हो रहा है, मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर साहब से यह पूछू कि मुझे यह बताया जाए कि प्राइमरी एजुकेशन, जो देहात का बसे है, देहात की. रीढ़ की हड्डी है, उसके पर टोटल एजूकेशन पर जितना पैसा खर्च हो

रहा है, उसका कितना प्र तिशत है । मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि जित्तना एजुकेशन के पर बजट रखा हुआ है, उसका 50 प्रतिशत हिस्सा हमारे हरियाणा की दो यूनिवर्सिटीज खा जाती हैं जहां पर मुश्किल से 1 5–2 0 प्रतिशत लड़के हमारे देहातों के पढते है । मैं हैरान हो गया जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाकर देखता हूं कि वाईस चांसलर की साढ़े तीन लाख रुपए की कोठी है । रजिस्ट्रार, मैडिकल कालेज और विगतने वहां पर डाक्टर हैं, उनकी एक एक कोठी पर तीन तीन लाख रुपया खर्च हुआ है । 80 हजार रुपए कोठी की फर्निशिंग के पर खर्च हुए हैं । तो आप हमें बताएं कि स्कूल हमारे जो देहातों में टूटे पड़े हैं, सारे फ्लड की वजह से बरबाद होकर गिर पड़े हैं, उनकेलिए हमें पैसा इतना कम दिया जा रहा हैकि उससे हमारी स्कूलों की रिपेयर भी नहीं हो सकती । इसके अलावा, गांव वाले बिल्डिग खड़ी करके दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, जमीन हम दे रहे हैं, आप हैरान होंगे यह सुनकर कि पिनाना एक गांव है, वहां पर साढ़े चार लाख रुपया लगाकर एक बिल्डिग खड़ी करके दी और उसके साथ–साथ सात एकड़ जमीन है, अस्पताल बना रखा है, वैटरनरी अस्पताल बनाया है, डिस्पैसरी बनाई है और साढ़े चार लाख रुपया लगाया है लेकिन सब कुछ फेल हो चुका है । बिल्डिंग में रेह लगनी शुरू हो गई है, पानी लगना शुरू हो गया है । देहात के अन्दर न अस्पताल मिला है न डिस्पैसरी वहां पहुंची है और न वैटरनरी अस्पताल वहां खोला जा रहा है । वहां पर सात लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन ये लोग शहरों के अन्दर अस्पताल खोलते जाते हैं । मैं पूछना चाहता

हूं कि क्या देहात के अन्दर आज तक कोई मैटरनिटी हाउस खोला गया । क्या देहात और गांव के अन्दर बच्चे पैदा नही होते । (व्यवधान) । मैं आपके सामने यह कहना चाहूंगा कि पिछले तीस साल में देहात को बरबाद किया गया, देहात को निगलैक्ट किया गया, किसान को नुक्सान पहुंचाया गया । आज जो भी हैवी इंडस्ट्री लगाई जाती है वह शहर के अन्दर लगाई जाती है लेकिन जो किसान छ महीने तक बैठकर मक्खियां मारता है, कोई कमाई नहीं करता, कभी पानी आ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, वह सिर्फ चार महीने ही काम करता है उसके लिए आज तक किसी सरकार ने कोई धन्धा नहीं दिया । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एम्पलायमैंट के मैक्सिमम चांसिज रूरल एरियाज को होने चाहिएं । देहात को ज्यादा से ज्यादा चांसिज होने चाहिए आज कोई भी कम्पीटीशन हो उसके अन्दर देहात के लड़के ठहर नही पाते । देहात के लड़के आईएएस. और एच.सी.एस. नहीं बन पाते । इस सोशलिस्ट राज्य के अन्दर, डैमोक्रेसी के अन्दर एक तरफ पब्लिक स्कूल चलते हैं, जिनके अन्दर पांच सौ रुपया फीस देकर लड़के पढते हैं, छ बार डैरस चेंज करते है । मोटर के अन्दर जाते हैं और दूसरी तरफ गांवों के लड़के है । बैठने के लिए टाट नही हैं, मास्टर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नही है और जिस वक्त ये लड़के बीए. पास करके उन पब्लिक स्कूल्ज के लड़कों केमुकाबले में आईएएस. और एच.सी. एस. के कम्पीटीशन में बैठते हैं तो पीछे रह जाते हैं । मेरा कहना है कि उस कम्पीटीशन के अन्दर प्रैक्टीकल टैस्ट के लिए तीन–

सौ मार्क्स रखे जाने चाहिएं । हल चलाने का गेहूं काटने का, दूध निकालने का, टैरक्टर चलाने का इन सब चीजों का कम्पीटीशन होना चाहिए । फिर देखना चाहिए कि देहात के लड़के कहां आते हैं । इसलिए मैं यहां पर साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय होता रहा है, यह चीज मैं कोई मजाक के तौर पर नही कह रहा हूं । मुझे चौधरी छोटू राम के शब्द याद हैं । उन्होंने कहा था कि असली राज्य तो सैक्रेटेरिएट के पंखों के नीचे बैठता है लेकनि इस देहात के मुश्किल. से चार परसैन्ट लोग पंखों के नीचे बैठते है । पिछले तीस साल में बजट का सारा. पैसा शहरों पर खर्च किया जाता रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर देहात को पर उठाना हे तो 90 प्रतिशत पैसा देहात पर खर्च करना पड़ेगा । इसके अलावा मैं यह भी कहना चहता है कि जहां तक एनीमल हस्बैडरी का सवाल है देहात के अन्दर किसान का सबसे बड़ा धन जो है, वह पशु है, लेकिन आप सब यहां बैठे हैं, आज हालत यह है कि बारह–बारह गांवों के बीच में एक भी एनीमल हस्बैडरी का. अस्पताल नहीं है । अगर किसान की एक भैस भी मर जाए तो उसका चार पांच हजार का नुक्सान हो जाता है लेकिन उसका इंश्योरैसं नहीं है, उसक कोई कम्पनसेशन नहीं है । इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान की फसल का इंश्योरैस होना चाहिए । किसान के पशु का इंश्योरैस होना चाहिए । जब एक कारखाने का, एक फैक्ट्री का इश्योरैस किया जाता है ओर अगर कोई नुक्सान हो जाता है, आग लग जाती है तो पैसा लिया जाता है लेकिन– किसान की फसल को ओले से नुक्सान हो जाए,

बाढ़ से नुक्सान. हो जाए, लेकिन उसको कोई कम्पनसेशन नहीं मिलता । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान को किसी आइटम का तो मुआवजा मिलना चाहिए, उसका इशयोरस होना चाहिए ।

किसान के साथ एक और अन्याय हो रहा है । हम लोग बैकों से कर्जा लेते है, टयूबवैल. के लिए कर्जा लेते हैं, टैरक्टर के लिए कर्जा लेते हैं, सीमेंट के रिनए कर्जा लेते हैं खाद के लिए कर्जा लेते हैं, और हमारे से 17 रुपया सैकडं का ब्याज. लिया जाता है और दूसरी तरफ अगर किसान के गेहूं का भाव गिर जाए, गुड़ का भाव गिर जाए, उसका भाव पूरा नही किया जाता, लेकिन दूसरी तरफ बिरला, टाटा, डालमिया के जो कारखाने हैं और उनके अन्दर जो चीज पैदा होती है और अगर उस चीज के पैदा करने में 250 रुपया खर्च आता है लेकिन वर्ल्ड माकीट में उसका भाव सौ रुपया या एक सौ पचास रुपया है तो इस बीच के नुक्सान. को सरकार बर्दाश्त करती है, लेकिन किसान के अनाज. का भाव अगर गिर जाए, गुड़ के भाव गिर जाए, तो उसके नुक्सान को कोई बर्दाश्त नहीं करता । इसलिए मैं कहना चाहता हू कि सरमाएदार द्वारा पैदा की हुई चीज, अगर वर्ल्ड माकीट के कम्पीटीशन में उसकी कीमत कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम पड़ती है तो यह सरकार उसके नुक्सान को पूर। करती है । इसी तरह से मैं सरकर से कहना चाहता हूं कि किसान के गेहूं का भाव 125 रुपया क्विटल मुकरर होना चाहिए और अगर सरकार 125 रुपया

मुकर्रर नहीं करती तो 85 रुपया या सौ रुपया क्यिंटल मजदूर के लिए रख दे और यह जो बीच का नुकसान है अगर सरमाएदार के लिए सहन किया जा सकता है, तो किसान के लिए भी सहन किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा एक औरे चीज कहना चाहता हूं इस देश के अन्दर जो यह शराब का दौर चल रहा है यह किसान के लिए बहुत बुरा है क्योंकि किसान को केवल दो चीजें मार सकती हैं । देहात के किसान और मजदूर को दो चीजें बरबाद कर सकती हैं । एक तो बाढ़ का पानी और दूसरे शराब की बाढ़ । ये दो बाहे हैं जो किसान और मजदूर को बरबाद कर रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ये सरमाएदार और पूजीपति इस देश के लुटेरे हैं और हमारे देहात बरबाद करने के लिए इन्हेंने शराब का सिस्टम चलाया । सरमाएदार के कारखा ने में एक बोतल शराब 5. 50 रुपए में तैयार होती है और देहात में जाकर 17 रुपए में बिकती है । एक तरफ तो किसान का पैसा सरमाए.दार को दिया जा रहा है और दूसरी तरफ इन्होंने यह सोचा कि देहात के लड़कों को, मजदूरों के लडको को, किसान के लड़कों को अगर कोई चीज बरबाद कर सकती है तो वह शराब है । उन्होंने सोचा कि उनक दिमाग केवल शराब खराब कर सकती है । उनको यह डर था कि कहीं ये देहात के लड़के हमारे साथ कम्पटीशन में न आ जाए कहीं ये लड़के हमारे अधिकारों कोन छीन ले । हमको निरबुद्धि बनाने के लिए उन सरमाएदारों ने यह साजिश रची कि गांवों के

अन्दर शराब के ठेके खुलवा दिए । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देहात से ये शराब के ठेके बिल्कुल बन्द कर दें । देश के इस 90 प्रतिशत कमेरे को बचाने के लिए अगर करोड़ों का नुक्सान भी उठाना पड़े तो भी शराब को बिल्कुल दफना दिया जाए । मैं सरकार से यह आशा रखूंगा कि जो भी सुजैशन्ज मैंने दी हैं, उन पर सरकार जरूर गौर करे । हम सरकार को हर लिहाज से मदद दे रहे हैं और यह सोचकर दे रहे हैं कि इसे बने हुए अभी. एक्रू साल भी नहीं हुआ है । हम इस सरकार को काम करने का पूरा चांस देना चाहते हैं । डन शरदों के साथ मैं सरकार से यह प्रार्थन। करूंगा कि आप पन्द्रह फीसदी को बिस्कूल लात मारकर 85 फीसदी को अपने साथ लेकर चलें, तो आपको कोई मारने वाला नही होगा ।

16.00 बजे

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि हमारे साथियों ने कट मोशन भी दिया हुआ है, जिन्होंने कट मोशन दिया हुआ है, उनको पहले समय मिलना चाहिए ।

(इस समय कामरेड शंकर लाल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : शंकर लाल जी आप बोल चुके हैं पहले बजट पर... (शोर)...

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिंए टाईम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । सबसे पहली मेरी रिक्वैस्ट सरकार से यह है कि हमने जो वृक्षों को लगाने का कार्यक्रम बनाया है, उसमें अगर हम सफेदे के वृक्ष लगाने की बजाए सड़कोंकी दोनों तरफ या नहरों की दोनों तरफ फलदाररू वृक्ष लगाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा जिससे कि अन्न की व्यवस्था भी होगी और स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अच्छा रहेगा क्योंकि आज गरीब लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब होता जा रहा है, लोगों को आज दूध की बजाए, अच्छी खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल रहीं हैं अगर गांव में यह फलदार वृक्ष होंगे तो लोगों की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर खास ध्यान दिया जाए और सफेदे के वृक्षों की बजाए फलदार वृक्षों को लगाया जाए । इससे अगली बात डिप्टी स्पीयर साहब, मैं क्हना चाहता हूं, शराब बंदी के तरे में, जैसा एक अभी मेरे एक भाई गंगा राम ने बताया कि शराब बिस्कूल बन्द होनी चाहिए । अगर यह शराब वगैरह बन्द होगी. तो हमारे जो गरीब किसान मजदूर हें, वें अपनी थोड़ी सी कमाई में अच्छी प्रकार से रोटी खा सकेंगे । मेरा सरकार के सामने एक सुझाव है कि शराब की दुकानों पर रजिस्टर रखा जाए ताकि जो आदमी वहां पर शराब लेने के लिए जाए वह वहां रजिस्टर में अपना नाम व पता लिखे, जिससे शराब पीने वालों को जरा झिझक सी रहेगी और जो छोटे छोटे बच्चे वहां शराब लेने के लिए जाते हैं उनके पर भी रोक लग सकेगी

और वे भी वहां जाने से डरेंगे, इससे एक तो वही शराब की बिक्री कम होगी और दूसरे गरीब लोगों का इससे भला होगा । तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार को इस तरह का नियम भी बना देना चाहिए । अव्वल तो मेरा सुझाव है कि गांव–गांव में यह जो शराब की दुकानें हैं, यह भी कम होनी चाहिए । इससे अगली बात मैं डिप्टी स्पीकर साहब, सेव्य टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं जैसा कि दूसरे सूबों में सरकार ने इस सेल्ज टैक्स को कम करने की कोशिश की है, जो सेल्ज टैक्स फार्मज हैं, वे बिला वजह बिजनैसमैन को परेशान करने के लिए बनाए हुए हैं, फार्म नबर 1 4, 1 5, 16 वगैरह जो फार्म हैं, इन सब को जैसा कि दिल्ली के अन्दर सब के सब फार्म खत्म कर दिए गए हैं, यहां हरियाणा में भी इनको खत्म कर देना चाहिए और जैसे दिल्ली और पंजाब ने किया है कि छोटी दुकानों के लिए लाईसेंस देने पर उनका हिसाब किताब नहीं देखा जाता, उसी तरह से हरियाणा को भी ऐसे ही करना चाहिए कि छोटे दुकानदारों को तंग न किया जाए । जो बड़े–बड़े दुकानदार हैं, उनका हिसाब किताब जरूरत पड़ने पर रेखा जा सकता है, लोंकन छोटे दुकानदारों को इससे छूट मिलनी चाहिए, मेरी सरकार से यह बड़ी पुरजोर दरख्वास्त है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुरशीद अहमद पदासीन हुए ।)

तो चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था अपनी सरकार से कि केवल उन्हीं दुकानदारों को बुलाया जाए जिनके एकाउंट्स में

कुछ खराबी प्रतीत हो, दूसरे दुकानदारों को परेशान न किया जाए । अन्त में मैं हैल्थ के बारे में अपने ख्यालात रखना चाहता हूं कि इस समय देश के अन्दर हैल्थ के बारे में काफी खराबी पाई जा रही है । अभी–अभी. बहुत से साथियों ने बोलते हुए कहा कि शफाखाने और अधिक होने चाहिए । मैं भी इसक समर्थन करता हूं ताकि देश के बच्चों को, गरीब किसान को और दूसरे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नही हे, उनको दवाईयों की सुविधा प्राप्त हो सके । इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि यह जो दवाईयों के लिए पैसा रखा गया है, यह वहुत कम रखा गया है, इसको बढ़ा कर ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिए ।

अभी मेरे भाई ने बोलते हुहु कहा कि गांवों में 2 0–20 मील के फासले पर डिस्पैसरियां हें, जिनसे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है 'कि गांवों में जितनी. ज्यादा से ज्यादा डिस्पैंसरियां हो सकें, खोलनी चाहिएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो । दवाईयां खरीदने के लिए सरकर को और अधिक पैसा रखना चाहिए ताकि गरीब आदमियों को और उनके बच्चों को मुक्त दवाईयां मिल सकें । इन लफ्जों के साथ मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए. अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी) : आदरणीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बड़ा मश्कूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । चेयरमैन साहब, मैं तो सिर्फ एक ही डिमांड नम्बर 10 पर बोलूगा ।

आवाजें : चेयरमैन– साहब, हमें भी बोलने का समय मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : टाईम लिमिट थोड़ा कम रख दें, तो मेरे विचार में ठीक रहेगा.....

आवाजे : ठीक है जी ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : चेयरमैन साहब, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सारा भार आज मैडिकल प्रोफैशन पर डाला हुआ है, पर इसके लिए सारा समाज जिम्मेवार है । जब कोई किसी किस्म की खराबी होती' है, चाहे किसी पोलिटीशियन के साथ हो, चाहे स्पोर्टस– मैन के साथ हो, चाहे गरीब किसान के साथ हो, चाहे व्यापारी के साथ हो, चाहे किसी क्लर्क या बड़े आफिसर के साथ हो, तो इसकी सारी. जिम्मेवारी' मैडीकल प्रोफैशन पर डाली जाती है । मैंने अलवा कमीशन की रिपोर्ट पडी है उस पर मैं कुछ नहीं कहता । आज सन्तोख सिंह आनन्द जी का पेपर मैंने पढ़ा कि जब भी किसी के साथ हैल्थ के बारे में कोई बात हो जाती है तो मैडीकल प्रोफैशन को पकड लिया जाता है । जहां पर आप लोगों ने मैडीकल प्रोफैशन पर एक बड़ी

जिम्मेवारी डाली है, वहां पर इसका मखौल भी उड़ाया गया है । वह है फैमिंत्री प्लानिंग का । इसके बारे में एक बात कहता हू कि मैडिकल प्रोफैशन में कहीं पर यह नहीं कहा गया कि फैमिंत्री प्लानिंग कराओ । किसी ने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, यह तो सब पोलीटीशियनज ने ही लोगों को मजबूर किया और मखौल उड़ाया जाता है मैडिकल प्रोफैशन का, कितने दुख की. बात है । मैं इण्डियन मैडीकल एसोशिएशन का मैंबर होने के नाते आपके'य बताना चाहता हूं कि यह जो न्यू कम्युनिटी है, उनको सिर्फ तीन–महीने की ट्रेनिंग देकर गांवों में दवाईयां देकर भेज दिया जाता है जिनको उन दवाईयां के नाम तक नहीं पता है । कुनीन सल्फेट का नाम तक नही बता सकते हैं, मैं इस बात का चौलेंज करता हूं । उन लोगों को यह भी पता नहीं होता कि यह कुनीन सल्फेट किस वक्त देनी है और किस वक्त नही देनी और फिर लोग मैड़ीकल प्रोफैशन का मखौल उड़ाते हैं कितने शर्म की बात है ।

मैं कहता हूं कि ए0पी0सी0 की एक टेबलट भी किसी को नुक्सान दे सकती है जिसको पूस्प्रीन से एलर्जी हो, उसे नुक्सान कर सकती है । जहां तक हैल्थ का सवाल आता है तो उसके बारे में सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी आई0एम0ए0 के साथ मिलकर बात करती है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार सैट्रंल गवर्नमैंट ने आई0एम0ए0 के साथ कोई बातचीत नहीं की । इसलिए मैं उनका रोष इस हाउस में अपने द्वारा प्रकट

करना चाहता हूं कि यह जो न्यू कम्युनिटी हैल्थ वर्कर की स्कीम है,इस पर जो पैसा खर्चा जाएगा, यह सिर्फ नाम के डाक्टरों पर ही खर्चा जाएगा । क्या कोई तीन महीने में डाक्टर बन सकता है । परसों चौथे मैंने अखबार में पडा कि पंजाब में ऐसा हुआ है और जब गवर्नमेंट ने किसी से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह सर्विस छोड़ कर चला गया और जाकर डाक्टरी शुर कर दी । क्योंकि जिस वक्त वह किट लेकर गांव में जाएगा तो गांवों के जो हमारे भोले भाले आदमी हैं, वे उसी दिन उसके डाक्टर साहब कहेंगे । वह तो तीन महीने में डाक्टर बन गया और वैसे डाक्टर बीस साल में बनता है । 14 साल तो बी0एस0सी0 पर और पांच साल एम0बी0बी0एस0 पर और एक साल इटरनशिप पर और इस स्कीम के तहत उसे तीन महीने में डाक्टर बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और जब वह नौकरी से जाएगा फिर भी डाक्टर ही कहलवाएगा चाहे उसे कुछ आता है या नहीं । तोसरकार से मेरी यह गुजारिश हैकि यह जोपै सा हम न्यूकम्युनिटी हैल्थ स्कीम पर खर्च करने जा रहे हैं, इस पैसे के बारे में मैंने बहिन जी से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि यह पैसा सैन्ट्रल गवर्नमेंट देगी । ठीक है अगर सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी देती है, तोभी बिस्कूल ठीक है लेकिन सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस पैसे को बजाए इस स्कीम पर खर्च करने के प्राइमरी हैल्थ सैन्ट्रर्ज पर खर्च किया जाए । मेरे पास मिसाल है कि एक आदमी दुकान तो हलवाई की करता है और वह आप्रेशन पाइल्ज का करता है । एक तरफ तो हम क्वैक्स को बन्द करने की सोचते हैं और दूसरी तरफ इस

स्कीम के जरिए उसे बढ़ाने जा रहे हैं । इसलिए सरकार से मेरा अनु रोध है कि यह पैसा जो खर्चा जाएगा, इसकी बजाय हम यह पैसा नए प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोलने पर और दवाईयों की सुविधा पर लगाएं । इससे सारे समाज का, सारे देश का भला होगा और हम उन बेचारे गरीबों को जो देहातों में रहते हैं गुमराह नहीं कर सकेंगे । धन्यवाद ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : (उचाना कलां). चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि हमारी जगता सरकार ने जो यह बड़े दावे से कहा था कि जब जनता का राज होगा या जनता की सरकार बनेगी तो एक नई राह गरीब लोगों को और पिछड़े हुए लोगों को मिलेगी । इस ख्याल से यहां की जनता ने इतने भारी बहुमत से जनता पार्टी को इस राज की बागडोर सौंपी । चेयरमैन साहब, लोग कब तक बर्दाश्त करे? 8 महीने करें, 8 महीने करें या साल भर करे । अब बजट आने पर भी यह उम्मीद थी कि कोई नई स्कीम या नया तरीका इस राज ने अख्तियार किया होगा लेकिन अफसोस की बात है कि एग्रीकल्चर के अन्दर 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । उसके अन्दर सारे के सारे हैड्ज आ जाते हैं, जिनका एग्री– कद–पर से कोई सम्बन्ध नहीं है । तो जिन किसानों ने सरकार को जिताया उन किसानों के लिए यह सरकार क्या कररही है । सारे प्लान बजट का सिर्फ 10 प्रतिशत रखा गया है और शप देखेंगे कि इसमें भी अगर किसान की भलाई करनी मी तो उसकी फसल की इश्योरैसं की कोई

स्कीम आनी चाहिए थी, उसकी फसल के लिए कोई कीमत मुकर्रर होती लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि किसान के लिए कुछ नहीं किया गया है । ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे लोग यह कहते हैं कि कन्जयूमर के प्राइस इंडैक्स को भी देखना पड़ता है जब किसान के लिए भाव निर्धारित किए जाते हैं । मैं कहता हूं कि जब कन्जयूमर के प्राइस इंडैक्स को देखना पड़ता है तो किसान की कास्ट को भी देखना चाहिए । लेकिन बहुत दुख की' बात है कि किसान के लिए कोई प्राइस इंडैक्स फिक्स नहीं किया गया । आज– हालत यह है कि गन्ना 5 और 6 रुपए क्विटल तक बिक रहा है । मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान को जो भाव आज मिलना चाहिए था वह तीन महीने के बाद मिलेगा. । क्योकि इन तीन महीनों में सरकार के पूंजीपति साथी गुड़, खांड और चीनी का स्टोर कर लेंगे । वैसे तो किसान को हम अन्न दाता कहते हैं, लेकिन उसके बदले में हम उसको देते क्या हैं? आज 9 महीने हमारी सरकार को बने हुए हो गए हैं तथा एक साल हमारी केन्द्र की सरकार को बने हो गया, लेकिन किसान की जरूरत कीजो चीजे है, जैसे जूता है, कपड़ा है, शादी के लिए चीजें हैं या उसके खेतीबाड़ी के औजार हैं सब की कीमतें बढ़ गई हैं और दूसरी तरफ किसान जो पैदा करता है उसके भाव घटा दिए गए है । जैसे गन्ने का भाव घटा दिया गया है । दाल जो किसान पैदा करता है तो उससे 60 या 70 पैसे किलो ली जाती है लेक्नि वही दाल जब साफ सुथरे लिफाफों में जनती है, तो 4– 5 रुपए किलो के भाव से बिकती है । मैं यह नहीं कहूंगा कि

सरकार बिल्कुल आंखे मीचे हुए हैं, लेकिन सिर्फ नारेबाजी से किसानों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता, बल्कि कुछ करने के बाद होगा । सरकार ने 80 करोड़ रुपया कोआप्रेटिव सोसाइटियों के जरिए गांवों में बांटने के लिए कहा हे । उस 80 करोड़ रुपए को बांटने के लिए बड़ी भारी मशीनरी भी बनाई गई है और वह पैसा जो रिजर्व बैंक से 8– 9 प्रतिशत से चलता है वह किसानों को, गरीब मजदूरों को और गरीब हरिजनों को 16 और 18 परसैन्ट के वीच में मिलता है । जो सरकार यह कहती थी कि वह उस 80 प्रतिशत जनता को राहत देगी जिसको पिछले तीस साल में कोई राहत नहीं मिंत्री । मैं उन हाकिमों से यह पूछना चाहता हूं कि 16 और 18 प्रतिशत पर कर्जा तो आज से तीस सारन पहले गांव के महाजन और सेठ भी देते थे । सेठों से तो पैसा आराम से मिल जाता था, लेकिन आज किसान– कोकर्जे के लिए दफ्तरों की खाक छाननी पड़ती है और अगर वह उस कर्जे की कोई किश्त अदा न कर सके तो सरकारी मशीनरी उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है । लेकिन उस जन्माने में जब सूद खोरी का काम चलता था और ऐसी कोई बात हो जाती थी तो भाईचारे से फैसला हो जाता था । इसलिए मैं कहता हूं किं आज 4 0– 50 साल पहले जो एक रुपया नौ आना के हिसाब से ब्याज लिया जाता था वही. ब्याज आज यह सरकार किसानों से ले रही है जो कि बहुत ज्यादती है । मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर के अन्दर अगर इनको 22 करोड़ रुपए' का प्रावधान करना थो तो इनको चाहिए था जैसे एक मिल मालिक की फैक्ट्री से समान तैयार होकर

निकलता है तो उसके लिए उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन फिक्स की जाती है । मिल का मालिक जो टैक्स वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधि है, उस सामान पर एक्साईज टैक्स, सेलज टैक्स और दूसरी चीजे लगाता है, तब जाकर मार्केट में वह चीज आती है। जहां तक किसान की पैदावार का ताल्लुक है, उसको हर दुकानदार, हर शहरी, हर पटवारी लूटता है और इन हालात में सरकार का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि सरकार किसान को चिट्ठियों द्वारा सूचित करे कि तुम्हारा गन्ना, चना, सरसों, दालें वगैरा इस भाव पर बिकेंगे और अगर इससे कम बिकता है तो जो 22 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर हैड में रखा है उससे किसानों को कम्पन्सेट करेगी । किसान को चिट्ठियो द्वारा सूचित करना चाहिए ताकि उसकी पैदावार का सही मूल्य मिल सके । लेकिन सरकार किसान के लिए छोटे–छोटे सैन्टर खोलकर उसके आंसू पोंछना चाहती है और उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है । इस तरह से उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता, इसके लिए ठीक कदम उठाने चाहिएं चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह दावा किया था कि गेस रूट पर डैमोक्रेसी कायम करेंगे । लेकिन इन्होंने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कायम किए और उन के अन्दर अपने आदमी लगाने शुरु कर दिए । जो क्राइ– टेरिया रखा है, उसकेबारे में आज हरियाणा का हर एक व्यक्ति यह कहता है। कि इस हरियाणा के अन्दर दो आदमियों का राज. है । देहातों में चौधरी देवी लाल का और शहरों में डा. मंगल सैन का यह

बात पहली बार सुनने में आई है । इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा हे कि कितने आदमी आर0एस0एस0 के है और किन–किन का होल्ड है । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहरों के अन्दर हरिजन नही बसते, बैकवर्ड क्लासिज के भाई नहीं बसते, इनको क्यों शामिल नही किया गया । एक भी हरिजन भाई को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया, सब जगह आर0एस0एस0 छाया हुआ है । इसी तरह से हमारे फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, सब कुछ फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर के काबू में हैं और वे बड़े दावे के साथ कहते है कि किसी चीज की कीमत नही बढ़ रही । वे कहती. है कि वे कैम्पों में बैठ कर आती है जहां लोग छोटी–छोटी निक्कर पहने फिरते हैं । इन गांवों से इनको रिपोर्ट मिलती है कि गांवों में व्यवस्था बिल्कुल ठीक हे, लेकिन व्यवस्था का यह हाल है कि गांवों में इनके बिचोलिए काम करते हैं जो किसान का शोषण करते है, उन निक्कर पहने गरीबों का शोषण करते हैं और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत रिपोर्ट दे ते हैं । इस तरह से वे लोग इस 80 प्रतिशत जनता का भला नहीं सोच सकते । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 प्रतिशत लोगों के पास तो साधन हैं, लेकिन 80 प्रतिशत जनता के पास साधन नही हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है । इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों में नोमिनेशन हुई है, उन पर समाज का वही अंग बैठ गया जो समाज का शोषण करता आया है, समाज पर अत्याचार करता रहा है । लेकिन 80 प्रतिशत लोगों का उसमें कोई जिक्र नही है..... ।

श्री सभापति : आपका टाईम हो गया है, दो मिनट बोलना था, लेकिन चार मिनट हो गए है ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, इस सरकार के बहुत बड़े–बड़े दावे थे कि सर– कारी मशीनरी पैसा इकट्ठा नही करेगी, समाज में भ्रष्टाचार नहीं होगा । मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरकारी मशीनरी पैसा इकट्ठा कर रही है । में नाम नहीं लेना चाहता, यहां मेरे एक आनरेबल मैंबर बैठे हैं, उन्होंने मुझे टिकटों का एक थब्बा दिखाया और कहा कि यह टिकट तहसीलदार और एस0डी0एम0 ने काटे हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए । चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा प्रमाणं और कोई नहीं हो सकता । सरकारी मशीनरी को भ्रष्ट करने की यह एक मिसाल है । जहां तक फूड एंड सप्लाई महकमे का सवाल है, यह महकमा तो जनसंघ का है । यहां पर काम करने वाले जनसंघी भाई मौज उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं (व्यवधान)– एक समय में चीनी के दो परमिट काटे गए, एक असल था और दूसरा नकली था । एक काले बाजार में चला गया और दूसरा बंटने के लिए क्या गया । यह फूड एंड सप्लाई में भ्रष्टाचार का नमूना है । चेयरमैन साहब, जनता पार्टी जिसको जनता पार्टी की सरकार कहते हैं, इसमें वही लोग हैं जो समाज का हमेशा शोषण करते आए हैं, किसान पर अत्याचार करते आए हैं । हमारे मुख्य मन्त्री जी आ गए हैं, इन्हें इस बात का इल्म होगा कि किस तरीके से समाज के अन्दर भ्रष्टाचार पनपता रहा और जो लोगों की आशाए

थी, उम्मीदे थीं, वे धूमिल हो गई । जो लोग यह सोचते थे कि शासन के अन्दर तबदीली आएगी, नया निखार आएगा, वे भूल कर रहे हैं । यही कारण है कि आज की जनता यह दावा करती है कि आज की शासन प्रणाली में वही लोग आ गए हैं जो पहले राज में जनता का, किसानों का शोषण करते थे ।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिए, काफी टाईम हो गया है ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री दीप चन्द भाटिया : मुझे टाईम दें, मैं कई बार खड़ा हुआ हूं । ..... मुझे टाईम नहीं दे रहे –(व्यवधान)

श्री सभापति : ये रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए जाएं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, जिन लोगों ने कट मोशन्ज दे रखी हैं, उनको टाईम दे दिया जाए । वे दस–दस बार बोलने के लिए खड़े हो चुके हैं ।

श्री सभापति : जो टाईम है, उसके मुताबिक सबको मौका दिया जाएगा ।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला) : चेयरमैन साहब, मुझे जो आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे एक बात का

गिला है कि जो नए सदस्य आए हैं, उनका खासतौर पर ध्यान रखा जाए । एक तो मैं नया हूं और दूसरे कोने में बैठा हूं, आप हमारा ख्याल रखा करें । आपका मैं शुक्र गुजार हूं, जोमुझे बोलने का समय दिया है । मैं अपनी स्पीच में किसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता । चेयरमैन साहब, अनुदानों की मांगों पर डिस्कशन हो रही है । अनुदानों के बारे में मैं एक बात बड़े फस' के साथ कह सकता हूं कि इन मांगों में जो बातें हैं, इनका जो उद्देश्य है, जो भलाई है, इसके लिए हम पिछले 30 सालों से भटक रहे हैं । हमारे बजट में जो योजनाए हैं, उनका रूझान गांवों की तरफ है, इस बात के लिए मैं जनता सरकार को बधाई देता हूं । लेकिन मैं यह बात कहे बगैर नही रह सकता कि पिछली कांग्रेस सरकार नें गांधी जी के नाम को सरे बाजार नीलाम किया है, गाधी जी के सिद्धान्तों को मिट्टी में मिला दिया, उन पर चलने का बिल्कुल प्रयास नही किया । लेकिन जनता सरकार ने इस ओर ठोस कदम उठाए हैं और गांवों की तरफ ध्यान देकर अच्छी योजनाएं बनाई है । जहां सरकार गांवों की तरफ ध्यान दे रही है, वहां इस बात के लिए भी जागरूक रहे कि गांवों में जो बड़े–बड़े जमीदार हैं, उनकी तरफ ही ज्यादा ध्यान न रहे, छोटे जमीदार भी इस देश में रहते हैं, खेती मजदूर रहते हैं, इनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए । गांवों को शहरों के बराबर लाने की जो हमारी कल्पना है कही हम उससे भटक न जाएं । जनता सरकार को मैं बधाई देता हूं जिसने अपना रुख गांवों की तरफ मोंड़ा है । इसके साथ ही साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों से

कांग्रेस राज में एक बहुत बुरी बात होती चली आ रही है । हमने यह नहीं सुना था कि शासन जनता को जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहन करती हैं । इस लाटरी को खत्म किया जाना चाहिए । पिछली सरकार ने इस देश में जुआ खेलने का एक रिवाज चलाया है जो देश को सर्वनाश की तरफ ले जा रहा है । मेरी सरकार से प्रार्थना है है कि वह हिम्मत करके इस जुए वाली लानत को खत्म करे ।

सभापति महोदय, शराब के बारे में बहुत से साथी बोल चुके हैं । मैं उन बातों को दोहराना नही चाहता मगर एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जब तक कोई भी सरकार नेक नीयती से काम न करना चाहे, तब तक शराब बन्द होने वाली नही है । ज्वांयट पंजाब का, जिसमें आज का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल शामिल है, इस मद से राजस्व लगभग 88 करोड़ रुपया बनता है । इस रेवैन्यू के लालच में आज तक कोई भी सरकार शराब को बन्द करने के लिए ठोस कदम नही उठा रही है । लेकिन हमे गांधी जी के शब्द याद रखने चाहिएं । गांधी जी ने कहा था कि शराब का पैसा लेकर विकास करने की बजाय मैं हिन्दुस्तान को अनपढ़ और अविकसित रखना चाहूंगा । इसलिए इस पैसे से विकास करना तो वह बात होगी जैसे एक घड़े में आप पर से पानी डालते जाए और नीचे के छिद्र से वह निकलता जाए । जब तक सरकार रेवैन्यू का बहाना लगाकर इस अनैतिक चीज को प्रोत्साहन देती रहेगी, तब तक शराब बन्द नहीं हो सकती ।

श्री बलदेव तायल : चेयरमैन साहब, आन ए प्वांयट आफ आर्डर । मैं यह बात जानना चाहता हूं कि ये मैंबर साहब किस डिमांड पर बोल रहे है? बोलने से पहले यह बात बतानी तो जरूरी थी ।

श्री सभापति : आप अपनी स्पीच वाईड अप करें और यह भी बता दें कि कौन–सी डिमांड पर आप बोल रहे हैं ।

श्री जय नारायण वर्मा : चेयरमैन साहब, मैं राजस्व वाली डिमांड पर बोल रहा हू ।

तो चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था सरकार को इस तरह से राजस्व को छोड़ने की कभी न कभी क्रांतिकारी हिम्मत करनी. ही पड़ेगी । शराब पर टैक्स भी लगना चाहिए । जब तक शराब की आमदनी को शराब केखिलाफ प्रयोग करने की हिम्मत नही होगी, तब तक हम इसको बन्द नही कर सकेंगे । आज सत्ता की बागडोर ऐसे हरियाणवियो के हाथों में है जिन पर हमें गर्व है । अगर आज. भी शराब बन्द न हुई तो यह बड़ी अदभुत् सी बात होगी । यदि हम कल्पना करे बिय यह शराब फिर कभी बन्द हो सकती है तो ऐसा नहीं हो सकता ।

इसके बाद, चेयरमैन साहब, मैं रोजगार वाली' डिमांड के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा । इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि बजट के अन्दर रोजगार के बहुत से अच्छे साधन जुटाए जाने का जिक्र किया गया है । नौजवानों

को नौकरी' दिला ने का प्रयास भी किया जा रहा है । लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात मैं अवश्य कहंना चाहूंगा । आज हम देखते हैं कि जब चीनी की कमी होत्ती है तो राशनिंग होती है जब कोयले की कमी होती है तो कोयले की राशनिंग होती है । तो क्या हम ऐसा नही सोच सकते हैं कि राशनिंग आफ एम्पलायमैन्ट भी हो । आज देखा कह जाता है कि किसी घर में तो पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, बहिन भी नौकरी करती है और भाई भी नौकरी करता है, लेकिन कई घर ऐं से हैं जिनका कोई दूर का रिश्तेदार भी नौकरी में नही हे । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करुगा कि वह राशनिंग आफ एम्पलायमैंट केबारे मे भी सोचे ताकि सबको रोजगार के बराबर अवसर मिल सकें ।

आखिरी बात, चेयरमैन साहब, मैं यहकहना चाहता हूं कि समाज के जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं, समाज के जो पिछडे वर्ग है, उनके लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वे नाकाफी हैं । इस प्रोविजन को बढ़ाया जौना चाहिए, ताकि जो भाई बहिन समाज में पीछे रह गए हैं, वे आगे बढ़ सके ।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद) : चेयरमैन साहब, मैं आपका अपनी आ त्मा से धन्यवाद करता हूं क्योंकिं मुझे चार दिन के बाद बजट के पर बोलने का पांच मिनट का मौका मिला है ।

श्री सभापति : आप किस डिमांड के पर बोल रहे हैं?

श्री दीप चन्द भाटिया : मैं अपनी आत्मा की बात तो एक मिनट कर स । चेयरमैन साहब, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जनता सरकार ने चीफ मिनिस्टर **चौधरी** देवी लाल जी ने, जो 10 परसैन्ट आबियाना बढ़ाया था, जो गरीब किसानो के पर, गरीब भाईयों के पर बड़ा बोझ था, उसे विद्ड्रा कर लिया । दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारा व्यापारी वर्ग जो जनता सरकार से नाराज हो गया था उसे इस सरकार ने खुश कर लिया है 13 परसैन्ट बडे हुए सरचार्ज को विद्ड्रा करके । तीसरी चीज मैं अपनी आत्मा की आवाज की तरफ से कहना चाहता हूं । – (हंसी)

श्री सभापति : आप सारी डिमांडज पर इकट्ठा बोल लें ।

श्री दीप चन्द भाटिया : चेयरमैन साहब, मेरे गरीब भाई और मजदूर भाई बसों पर चलते हैं. इसलिए यह जो 10 परसैन्ट पैसेंजर टैक्स में बुद्धि की गई है यह भी विदड्रा होनी चाहिए । अगर कह हो जाए तो यह भी खुशी की बात होगी और तभी यह जनता का सही बजट होगा । (प्रशंसा) लेकिन अतः सवाल है कि पैसा कहां से आएगा, जनता सरकार कैसे चलेगी? इसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में करोड़पति और अरबोगित बैठे हुए हैं जिनकी फैक्ट्रियां वहां–चलती है लेकिन दफ्तर दिल्ली के अन्दर हैं 1 मैं यह बात पहले भी कई दफा कहू चुका है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है । अपने फाईनेंस मिनिस्टर साहब को भी मैं यह बात कई दफा बोल चुका हूं लेकिन पता नही क्यों यह बात ठन्डी हो जाती है । मैं आज फिर इस

हाउस में कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद के अन्दर जो फैक्ट्रियां हैं, अगर उनके दफतर दिल्ली से फरीदाबाद में आ जाएं तो कोई टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

इसके अलावा मैं एक और भी अर्ज करना चाहता हूं । शराब के बारे में सभी भाई बोल चुके हैं लेकिन मैं एक जरुरी बात कहना चाहता हूं । यह शराब बहुत गन्दी चीज है । इसलिए इसके पर इतना टैक्स लगाया जाए कि अगर कोई पीए तो उसको कुछ पता तो लग जाए । आज जो टैक्स लगा हुआ है उससे दुगुना इसको कर दो । हमारे फाईनैसं मिनिस्टर साहब, यह जो 10 परसैन्ट पैसेंजर टैक्स बढ़ा देते है या तीन परसैन्ट सेल्ज–टैक्स फालतू कर दे ते हैं इससे बात नही बनेगी । (विघन) चेयरमैन साहब, मैं अपने आनरेबल मैंबर को यह बता देना चाहता हूं कि यह एम 0एल0ए 0 तो चुन लिए गए है लेकिन इनको अभी यह नहीं पता कि दीप चन्द भाटिया प्याज भी नहीं खाता, शराब पीने और म्उर्गा खाने की तो बात ही क्या है । (हंसी) यह खुद कांगेस में रहे हैं, इसलिए इनकी वहीं. पुरानी भावना अभी तक चल रही है । (विध्न)

इसके बाद चेयरमैन साहब, मैं हाउसको यह बताना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो हमारे गरी ब मजदूरों के पर जुल्म किया है, वह अब दूर किया जाना चाहिए । इस हाउस में मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि हजारों झुग्गी–झोंपडियां जो हमारे गरीब वर्कर्ज ने बनाई थी, उन्हें

एमरजेंसी के दिनों में तोड गया, जैसे दिल्ली में तुर्कमान गेट में तोड़ी गई थीं । क्योंकि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है इसलिए तुर्कमान गेट वाली झुग्गी–झोंपड़ियों के बनाए जाने के बारे में तो आर्डर्ज हो गए हैं, लेकिन मेरे फरीदाबाद, जहां से करोड़ों रुपए की आमदनी इस प्रान्त को है, के बारे में अभी गौर ही किया जा रहा है । फरीदाबाद की लेबर आज. फिर उसी तरह की झुग्गी–झोपडियों में रह रही है । वे एक इन्सान की जिन्दगी बसर नहीं कर रहे हैं । मैं चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जात् । चेयरमैन साहब, मैं भी लाखों आदमियों का नुमाइंदा हूं और मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो बच्चा अच्छा काम करता है, आमदनी अच्छी देता है, उसको मां और बाप, दोनो दूध भी अच्छा पिलाते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं । इसलिए आपको भी यह चाहिए कि चूंकि फरीदाबाद आमदनी देने वाला है, इसलिए उस रकम का कुछ हिस्सा वहां लगाया जाए ताकि उन गरीब लौंगों के मकान बन सकें । (विध्न)

चेयरमैन साहब, वहां एक बी0के0 हास्पिटल है । मेरे दिल्ली के आसपास के और पलवल आदि के सारे देहाती भाई वहां आते है, लेकिन वहां पर उनको कोई खास सहूलियतें नहीं मिलतीं । चेयरमैन साहब, वह अस्पताल उस व्यक्ति के नाम पर है, जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है और जो फ्रंटियर का महात्मा गांधी था । जिस वक्त मुस्लिम लीग की हकूमत पाकिस्तान

में बनी थी उस वक्त यानि 1947 से पहले वहां कांग्रेस का राज था । तो मैं अपनी सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि हमें बादशाह खान के नाम को चमकाना चाहिए । (विध्न) चेयरमैन साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करना चाहता है कि देहात के जो गरीब भाई वहां आते हैं, उनको वहा पर रोटी मूफ्त मिलनी चाहिए ।(घंटी) ।

चेयरमैन साहब, मुझे तो अभी तक बोलने केलिए समय मिला ही नहीं है । आप तो मेरे इलाके के हैं, इसलिए भी थोड़ा सा ख्याल करके मुझे टाईम दे दे।

चेयरमैन साहब आप को भली भांति पता है कि फरीदाबाद के अन्दर ज्यादातर लेबर रह रहे हैं । वे बेचारे गरीब वर्कर हैं । उनके मीनीमम वेजिज 170 रुपए है । उन गरीबों के पास कोई रास्ता नहीं है. खाने कमाने का कोई दूसरा साधन नहीं है । अगर एक परिवार में दो बच्चे और मियां बीबी हों तो चार आदमियों का 170 रुपए में गुजारा नही हो सकता । किसप्रकार से 170 रुपए मे रोटी खा सकते है? हमारे जो मिनिस्टर बने हैं, वे यहां हाउस में पास करा दें कि उनकी तनख्वाह ज्यादा हो ताकि उन दो बच्चों और मियां बीबी का रोटी का काम चल सके ।

चेयरमैन साहब हमारा यह करोड रुपए का बजट है । यह बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा केलोगों की भलाई पर खर्च होगा । हमारे हरियाणा में जब फलड नहीं आया

था, उस वक्त भी मैंने सी0 एम0 साहब से रिक्वैस्ट की थी और उनका यह नारा भी था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे । मैं आपके जरिए यहां रिक्वैस्ट करुंगा कि कांग्रेस के राज में एम0 एल0ए0 भी खाते थे, मिनिस्टर भी खाते थे । वहां पर जो ब्लैक से सीमेंट बिकता था, उसमें वे लोग अफसरान से मिले हुए थे । वहां पर ओवर सीयर की बिल्डिग बन जाती है, एस0डी0ओ0 की बन जाती है, क्लर्क की बन जाती है, कई लोगों ने वहां पर लाखों और करोडो बनाए हैं । इस बारे में सरकार को इनक्वायरी करनी चाहिए । इस टाउन के अन्दर हरियाणा का गरीब आदमी टैक्स दे रहा हे, इसटैक्स को वह क्यों दे, फैक्ट्रियों के आदमियों को देना चाहिए । पिछले राज में गरीबों की मेहनत का पैसा योंही जाया होता रहा है । इसलिए पिछले राज में जो सीमेंट बिकता था वह सीमेंट किस का है? वह हरियाणा का है । हरियाणा में जो पूरा सीमेंट नही लग रहा है,वह गरीब लोगों का नुक्सान हो रहा है । सीवरेज पर सीमेंट नही लगेगा। तो वह टूट जाएगा, पुल पर पूरा नहीं लगेगा तो वह भी टूट जाएगा । कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज बनाएं, अगर उस पर सीमेंट पूरा नहीं लगेगा तो टूट जाएगा । इस लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी बॉडी बना दें, जो इन बातों को चौक करे । .... इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक बॉडी बनाई जाए ।

Mr. Chairman : These remarks be expunged.

श्री दीप चन्द भाटिया : चेयरमैन साहब, मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं । तीस साल बाद तो जनता पार्टी के मिनिस्टर आए हैं । मेरी उनके बारे में भावना गलत नहीं है, लेकिन वे नए मिनिस्टर आए हैं, थोड़ी बहुत कमी होसकती है । इसलिए जो सीमेंट का भ्रष्टाचार है या कोई सड़क पर तारकोल पूरा नहीं डालता है, उसके बारे में इनक्वायरी कराएं । चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि छापे मार कर इस चीज को चौक किया जाए, ताकि यह भ्रष्टाचार खत्म हो सके ।

श्री सभापति : आप अपनी स्पीच खत्म करे ।

श्री दीप चन्द भाटिया : मैं खत्म ही करने जा रहा हूं । हं आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर इतना काम नहीं हुआ है, वहां पर होना चाहिए । वहां पर बसोंकी दिक्कत है, वहां पर बसें चलाई जाएं । इन लफजो के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाईम दिया ।

स्वामी आदित्यवेश (हथीन) : चेयरमैन साहब, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की भलाई का और हरियाणा के लोगों की समृद्धि केलिए यह बजट प्रस्तुत किया है । आज हाउस के अन्दर एक मांग से ले कर 25 मांगों पर 6 अरब 38 करोड़ के करीब खर्च होना है । मैंने पहले यह सोचना आरम्भ किया कि हरियाणा का कितना बड़ा बजट है, कितने करोड़ों रुपए का बजट है । जब मैंने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक

इस पर विचार करके देखा कि हर व्यक्ति को सरकार ने क्या दिया है? हमारे हरियाणा प्रान्त की आबादी करीब एक करोड़ बीस लाख है । आज के दिन हरियाणा पर 371 करोड़ का कर्जा है । इसको काट कर प्रतिव्यक्ति पर बराबर बराबर बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति 201 रुपए साल के हिसाब से आता है । साढ़े सोलह रुपए महीने के हिसाब से और 55 पैसे प्रति दिन के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया है । जब बजट को यथार्थ में देखते है तो इसमें कुछ और भी बातें दिखाई देती हैं । उदाहरण के तौर पर मांग नम्बर एक में 31, 8 2, 150 रुपए मांगे गए हैं । 'मुझे तो इसे देख कर हैरानी होती है कि एक तरफ तो 55 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से प्रावधान किया गया है और दूसरी ओर राज्य के एक शासक के लिए दस लाख रुपए का प्रावधान किया गया है । हमारे जितने विधायक हैं उन पर 42 हजार रुपया साल में वेतन के रूप में खर्च होगा लेकिन हमारे जो राज्य के एक प्रशासक हैं, उन पर 66 हजार रुपया खर्च किया जौ रहा है । इसी प्रकार से मकानों को सजाने के लिए तीन लाख 14 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है । क्या यह सही रूप से पैसे का वितरण किया गया है?

एक दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हरियाणा में बाढ़ आई । 517 स्कूलों की बिल्डिगे गिर गईं । इन तमाम स्कूलों की मुरम्मत के लिए केवल बीस लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन राई के अन्दर एक स्पोर्ट स्कूल. है,

उसकी एक बिल्डिग के लिए 35 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जवकि 517 स्कूलों के लिए केवल 20 लाख रुपया रखा गया है । तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से किसान और गरीब मजदूर जो कि समाज के आखिरी आदमी हैं पनप पाएंगे? दूसरे जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, पाठशाला हैं, गुरुकुल हैं उनके लिए केवल डेढ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि पिंजौर गार्डन के लिए साढ़े दस लाख रुपए की व्यवस्था की जा रही है । अगर आप गरीब किसान और मजदूर को उठाना चाहते हैंतो पैसे का किस प्रकार से विभाजन कर रहे हैं? ठीक है कि किसान और मजदूर को उठाने की भावना है लोकिन बजट के अन्दर यह भगवन। व्यक्त नहीं की गई है । बजट के अन्दर तो मैं कुछ और ही पढ़ रहा हूँ । इसमें किसान और मजदूर को कुछ नही मिल रहा है । सभापति महोदय, पर्यटन विभाग पर हमारी सरकार ने 59 लाख रुपया खर्च करने की योजना बनाई है । यह पैसा अय्याशी पर खर्च किया जाएगा लेकिन हमारे जो प्राइवेट कालेज– है उन पर बहुत थोड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है । 133 प्राइवेट कालेजों की संख्या हरियाणा में है, उन पर केवल साढ़े चार लाख रुपया ग्रान्ट के रूप में देने का प्रबन्ध सरकार ने किया है । इसमें कोई दो राय नहीं कि यह बजट पास होगा, लेकिन हम लोगों को अपनी छाती पर हाथ रख कर विचार करना चाहिए किं आखिर इस बजट में गरीब आदमी को सरकार ने क्या दिया है? किसान जो इस समाज का आखिरी आदमी है, उसको क्या 'दिया है? बोलते हुए मुझे दुख होता है, किसानों के लिए इस

सरकार ने क्या दिया है? दु:ख के साथ कहना पड़ता कि सारे बजट का पचास प्रतिशत रुपया महंगाई, भत्ते, किराए पर खर्च हो रहा है ।

चेयरमैन साहब हमारे हरियाणा ने एक हवाई जहाज भी खरीदा है, जबकि हरियाणा बाढ़ से तबाह हो रहा है । मैं समझता हूंकि इस हवाई जहाज के खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी । उस हवाई जहाज की मेंटीनैस के लिए आठ लाख 82 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है । इस प्रकार से उजडे हुए प्रान्त के लिए बिलकुल अच्छी बात नहीं लग रही है ।

17.00 बजे

हमारे प्रान्त मे इस समय लगभग डेढ लाख के करीब लोग बेरोजगार हैं । अभी हमारे पडोसी प्रान्त ने अपने शिक्षित बेरोजगारों केलिए 40 रुपए महीना का भत्ता दिया है, जो पांच सालों से रोजगार रजिस्टर में अपने नाम दर्ज कराए हुछ हैं । हमारी सरकार ने 8 करोड़ रुपया रेगिस्तान को हराभरा बनाने के लिए व्यवस्था की है । मैं यह चाहूंगा कि कम से कम यहां पर भी एक करोड रुपया शिक्षित बेरोजगार लोगो को निश्चित रुप से बेरोजगारी भत्ता देने त्हे लिए सुरक्षित रख लिया जाए तो उससे एक तो सरकार की यह जिम्मेवारी आ जाती है कि जब तक सरकार उनको रोजगार नहीं देती उन्हे बेरोजगार भत्ता देती रहे, दूसरे इससे हमारे प्रान्त में से बेरोजगारी. की समस्या हल हो

सकेगी अन्यथा हमारे यहां से बेरोज– गारो की समस्या हल नही हो सकती । अब मैं शरावबन्दी की बाबत कुछ कहना चाहूंगा । सरकार ने यह कहा है कि हम शराबबन्दी लागू करेंगे, लेकिन यह मुझे देखकर हैरानी हुई है, कि इस बजट में एक कौड़ी भी शराबबन्दी को लागू करने के लिए, किस प्रकार से उसका प्रचार करेंगे और किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहन देंगे, इस बजट में प्रबन्ध नहीं किया गया है । इस बजट में इस शराबबन्दी को लागू करने के लिए एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं रखी गई है । इसके अलावा, पिछले दिनों हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने यह कहा कि– हम जो शराबबन्दी लागू कर रहे हैं इससे हमें 4 करोड़ रुपाए का घाटा हो रहा है । यह बात ठीक हो सकती है । लेकिन जब से हरियाणा बना है यानी 1 966 से लेकर 197 7–7 8 तक की जो एक्साईज से इन्कम थी वह ही आप देख लीजिए । 1966 में इससे इन्कम 1करोड़ 49 लाख रुपए की थी, जो कि बढते बढ़ते 28 करोड़ तक पहुंच गई जबकि 1977–78 में साढ़े 24 करोड़ की इन्कम एक्साईज से थी । इस बार भी यह बढ़ कर 26 करोड़ के लगभग हो गई है । फिर मेरी यह बात समझ में नही आती कि इन्हे घाटा कहां से हो गया? हमारी केन्द्रीय सरक्रूार ने यह एलान भी किया है कि जो राज्य सरकारें शराबबन्दी लागू करेंगी उनका घाटा आधा वह पूरा करेगी । जबकि यहं क्रूहावत बिल्कुल मशहूर है कि ' देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना'' । आज जबकि इस शराब से हरियाणा मे इन्कम बढ़ती जा रही हो, तो इनको ऐसा कहना शोभा नही देता । मैं यह कहता हूं कि अगर

आप जो 292 के लगभग शराब की दुकानें देहातों के अन्दर हैं, उन्हें बन्द कर देते तो कितना ही अच्छा होता । आज 1022 शराब के ठेके हैं । जैसे कि प्रधान मन्त्री जी ने कह आश्वासन दिया है कि चार साल के अन्दर पूर्ण नशाबन्दी लागू कर देंगे, मैं यह चाहता हूं कि एक चौथाई दुकानें यानी 1022 का चौथा हिस्सा यानी 254 दुकानें बन्दकर दी जाती, ताकि हम जनता के अन्दर जाकर यह बात खुलकर कह सकते कि देखो जिस बात के पिछली सरकार ने दरिया बहाए हुए थे हम उसे धीरे–धीरे सही, चार सालों के अन्दर पूर्ण रूप से बन्द कर देंगे । मेरा विचार है कि जनता पार्टी की सरकार को लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह उनकी समस्याओं को हल कर रही है । उसके लिए सबसे पहला कदम उसे शराबबन्दी के बारे में शराब के ठेकों और दुकानों को बन्द करने का उठाना. चाहिए । अन्त में मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं कि जो किसान, गरीब मजदूर के पर, हरियाणा के युवक के पर आप 55 पैसे खर्च करने जा रहे हैं, यह कोई ज्यादा नही है, मैं यह चाहूंगा कि उन्हें इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए ताकि उनको यह अहसास हो कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं और हमारी सरकार हमारी भलाई के बार में सोच रही है ।

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए ।)

श्री सभापति : चौधरी उदय सिंह दलाल मैं हाउस के मैंबरों से एक यह दरख्वास्त करूंगा कि टाईम बहुत थोड़ा है लेकिन बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं । इसलिए अगर हरेक आनरेबल मैंबर 3 मिनट से काम चला ले तो उससे बहुत ज्यादा मैंबरों को समय मिल सकेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, जिन आनरेबल मैंबर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट पर भी मौका मिल चुका है, उन्हें दुबारा बोलने का मौका नही दिया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : आपको भी टाईम मिलेगा । देखिए, जिन्होंने कट मोशन दिए हैं पहले उनको मौका दिया जाएगा । फिर उसके बाद जितना समय बचेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैंबरों को अकोमोडेट करूंगा । (इस समय बहुत से सदस्य एक साथ बोलने लग गए ।) देखिए इस तरह से आप बोलेंगे तो एक स्पीकर का टाईम तो निकल जाएगा । (कामरेड शंकर लाल जी की ओर से विध्न) देखिए, शंकर लाल जी आप बैठ जाइए । अब सरकारी डिमान्डज हैं, वह आपका प्रोग्राम हो चुका है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : (बादली). चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह कहना चाहता हूंकि जिस भावना से सरकार ने लोगों से वायदा किया था और जिस भावना से बजट पेश किया गया है और जिस भावना से मांगें रखी गई हैं,

मैं इसकी सराहना करता हूं । अब जबकि मुख्य मन्त्री महोदय ने आबियाना और सेल्ज टैक्स पर जो सरचार्ज था, वह वापिस ले लिया, वह तो ठीक किया, लेकिन चूकि टाईम थोड़ा है, पाबन्दी लगी हुई है, इसलिए मैं दो तीन बातें ही सरकार को सुझाव के रूप में कहूंगा । एक तो यह है कि किसानों और फैक्ट्रियों के व्याज में जो डिफैन्स है, वह रेट यकसां कर दिया जाए । जो भी सरकार फैक्ट्रियों वालों से ब्याज का रेट लेती है, उसी रेट से किसान को कर्जा दिया जाए, चाहे वह ट्यूबवैल लगाने के लिए हो, या कुएं लगाने के लिए हो, या रहट लगाने के लिए या किसी और किस्म का भी कर्जा हो । जिस तरह से फैक्ट्रियों वालों से कम रेट लेते हैं, उसी तरह से किसान से भी 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाना चाहिए । जो रियायत फैक्ट्री वाले से होती है, वह रियायत उससे भी होनी चाहिए । आप जानते हैं वह खाता पीता तबका है और यह बेचारा कुचला हुआ तबका है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह जो ब्याज का फर्क है, इसे बराबर किया जाना चाहिए । मेरे काफी भाईयों ने अलग अलग तबकों की मांगें रखी । हर आदमी को दर्द होता है जब किसी आदमी के साथ बे–इन्साफ होता है तो कुछ.. आदमी उसके हक में बोलते हैं, तो कुछ उसके खिलाफ बोलते हैं । आपको पता है कांग्रेस वालों ने पिछले 30 सालों में एक ऐसा सिस्टम डाल दिया कि इस सरकार के लिए उस सिस्टम को ठीक करना मुश्किल हो रहा है । मैं सभापति महोदयसे यह तजवीज करूंगा कि आपको जैसे कि पता ही है 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है 80 नहीं तो 75 प्रतिशत तो गांव

के आदमी नौकरियों में लगाए जाने चाहिए। चाहे वे गरीब हरिजन हैं, या गरीब मजदूर हैं या किसान हैं, मेरा विचार यह है कि आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए और उस हिसाब से 75 प्रतिशत तो जो आदमी लिए जाते हैं वे देहात के लिए जाएं और 25 प्रतिशत शहरों से लिए जाने चाहिएं । चेयरमैन साहब, आप गवर्नमैंट की फिर्ग्ज को ही ले लें । आप देखिए 8 क्य 90 प्रतिशत. आदमी आज सर्विसिज में शहरों के लगे हुए हैं । जितनी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, उन पर अफसरों के बेटे लगे ूए है और हमारे देहात के आदमी या तो पुलिस में हैं या फिर खम्भे गाडने पर हैं या फिर

किसी दफ्तर में चपडासी हैं । चेयरमैन साहब, जनता पार्टी की सरकार को पिछली सरकार ने जो गलतियां की हुई हैं, उन्हें नहीं दोहराना चाहिए । जो पिछली सरकार गलत रिवायात डाल गई है, जनता यह उम्मीद लगाए बैठी है कि जनता पार्टी की हमारी. सरकार, तमाम देहात के लोगों को उनका उचित हक उन्हें दिलाएगी । इस बारे में जो हमेशा दिक्कत आई है, वह यह है कि कुछ अफसर ऐसे हैं, जो कि कांटा लगा देते हैं और ऐसी कोई बात सिरे नहीं चढ़ने देते । मैं सरकार को एक तजवीज– पेश करूंगा उससे चेयरमैन साहब, मैं कोई करोड़ों की तो बात नहीं करता, लेकिन लाखों रुपए जरूर बच जाएगे । बिजली' बोर्ड का दफ्तर है, कार्पोरेशन्ज हैं और दूसरे बोर्ड है उनकी यहा पर रखने की क्या जरूरत है? इनको हिसार, भिवानी, रोहतक वगैरह में

भेज– दिया जाए । यहां होने के कारण लोग बड़े परेशान होते हैं और अ फसर लोग जिनका दिल्ली का कोई काम होता है वे कोई कागज तैयार कर लेते हैं और सोनीपत का टूर निकाल लेते है, रोहतक का टूर तैयार कर लेते है और करो में घूमते फिरते हैं और इस तरह से दिल्ली चले जाते है । सरकर को ये आर्डर कर देने चाहिए' कि अगर कोई सरकारी काम होगा, तो वह अफसर बस में जाएगा । कोई बहुत बड़ी. एमरजेंसी. हो, तभी कर का इस्तेमाल किया जाए । एक बात मैं रैस्ट हाउसिज की बाबत कहना चाहता हूं । सरकार को यह आर्डर कर देने चाहिए कि जो आदमी रैस्ट ही उस में ठहरेगा, उसको कम से कम दस रुपए देने पड़ेगे । इससे कह फायदा होगा कि जो लोग खामखाह के लिए दो दिन या तीन दिन रैस्ट हाउसिज में ठहरते हैं वह नही ठहरेंगे और दस रुपए देने से रैस्ट हाउसिज का खर्चा है वह निकलेगा । रैस्ट हाउसिज को भी कुछ आमदनी हो जाएगी ।

चेयरमैन साहब, हर सब–डिवीजन– पर किसान रैस्ट हाउसिज बनाए जाए । इसके लिए सरकार को कुछ खर्च नहीं करन। पड़ेगा । मार्कीट कमेटी का जो पैसा है, पंचायत का जो पैसा है, ब्लाक समिति का जो पैसा है उस पैसे से ये किसान घर बनाए जा सकते है । इनके बनाने से यह फायदा होगा कि कोई टैरक्टर वाला गाड़ी' वाला सब डिवीजन पर किसी कम से आएगा, तो वह रात को यहां रुक सकेगा । इस वक्त तो. हालत यह है कि किसान को, गाड़ी वाले को ठहरने की अगर जरूरत पड़ जाए तो

कोई जगह ठहरने की नहीं होती । इस वक्त तो हालत यह है कि अव्वल तो मार्कीट कमेटी के कोई रैस्ट हाउसिज हैं नही और अगर कही हैं, तो उनको आफिसर इस्तेमाल कर रहे है । या तो वहां पर दफ्तर बना रखा है या रिहायश के लिए इस्तेमाल किया जाता है । चेयरमैन साहब., बिजली का प्वांयट बहुत जरुरी प्वांयट है । पहले मैं अस्पतालों के बारे में कह दूं । अस्पतालों के बारे में मैं सरकार से प्रार्थना कंरुगा कि गांवों में डंगरो और आदमियों के अस्पताल जरूर बनाए जाने चाहिए । शहरोंमें तो प्राइवेट डाक्टर भी होते हैं, उनसे इलाज कराया जा सकता है । गांवों की हालत तो कह है कि वहां पर तो सरकारी डाक्टर भी जाने से गुरेज करते हैं । अगर सारी फिगर गांवों की मंगाई जाए तो कोई भी अस्पताल ऐसा नही मिलेगा, जि समें पिछले तीस साल में पूरा स्टाफ पहुंचा हो हो सकता है कागजों पर सारा स्टाफ हो, लेकिन असलियत में पूरा स्टाफ किसी भी अस्पताल में नहीं पहुंचा । आखिर में मैं कहूंगा बिय गांव का आदमी जो गरीब है, वह हमारा भाई है चाहे वह किसी भी मजहब का है, किसी भी सोसाइटी का है । अगर हमारी कोई जात है तो

वह गांव का गरीब आदमी है और वही हमारा धर्म है । हैमने उसकी राय ली है । इसलिए सरकर से मेरी प्रार्थना हैकि सबसे पहरने गांव के गरीब आदमी को पर उठाने की कृपा करें । इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर–अनुचित जाति) : चेयरमैन साहब, आपने जो बोलने का टाईम दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूं । चेयरमैन साहब, ये जो ग्रान्टस हाउस के सामने रखी हैं, जितना भी यह खर्चा है, उसका फायदा गरीब. आदमी, किसान और जो पिछडे लोग हैं, उनको पहुंचेगा, ऐसी मुझे आशा है । बजट में भी और यहां हाउस में भी कहा गया है कि एग्रीकल्चर पर ज्यादा से ज्य! दा खर्चा होगा । बजट का 70 फीसदी पैसा एग्रीकल्चर पर खर्च किया जाएगा । चेयरमैन साहब., मेरी' एक सबमीशन है कि इस पैसे को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जांए कि उसका फायदा बड़े–बड़े जमींदारों को न मिले बल्कि ऐसे आदमियों को मिले जो असल में काश्त करते है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते है । अब तक जो भी फायदा होता रहा है, वह बड़े जमींदारो को होता रहा है । जो लोग पांच सात रुपए रोजाना की मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं उनको आज तक कोई फायदा नही पहुंचा है । छोटे किसान के लिए अभी तक कुछ नही किया गया सिर्फ बड़े जमीदारों को ही' सरकार फायदा पहुंचाती रही है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह बजर इस प्रकार खर्चा जाए कि उसक फा यदा वीकर सैक्शन को हो । उसको इस पैसेका फायदा हो, जो मेहंनत करता है, जो अपने खून पसीने की कमाई करता है उसको इस पैसे का फायदा होना चाहिए ।

इसके साथ–साथ हर डिपार्टमैंट के अन्दर आफिसर्ज ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया हुआ है, उसकी तरफ सरकार ने

कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है । मैं अपने मुख्य मन्त्री महोदय. से कहना चाहता हूं कि यहीं पर जितने भी आर्डर बड़े आफिसर्ज द्वारा या मन्त्री द्वारा किए जाते हैं, फील्ड में उनकी इम्पलीमैंटेशन नही होती, और इस ढंग से उनको टाल दिया जाता है कि यह कोई हरियाणा का चहने वाला नही है और इन लोगों को हरियाणा से कोई ताल्लुक नहीं है । इस प्रकार से हरियाणा के गरीब आदमी को न्याय नही मिलता और उसे न्याय दिलाने केलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा 'कि हर डिपार्टमैंट मेंएक अलग से सैल बनाया जाना चाहिए, जोइस बात पर गौर रखे कि अगर कोई भी आफिसर उन आर्डर्ज को इम्पलीमैंट न करे, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उसको फौरन गिफ्तार किया जाए, और उसको नौकरी से हटा देना चाहिए । ऐसे आफिशियल की हरियाणा मे कोई जरूरत नहीं है ।

चेयरमैन साहब, क्वैश्चन आवर में भी मैंने कहा था कि जिस चीज की तरफ सरकार कोई ध्यान नही दे रही है, वह है कि कायदे के हिसाब से अगर चार वकैन्सीज हैं, तोएक हरिजनको मिलती है, लेकिन आफिसर्ज की मनौपली है कि तीन वकैन्सीज निकालते हैं, चौथी वकैन्सी निका लते ही नहीं, और चौथी वकैन्सी के लिए चाहे एडहाक पर या स्टाईपैन्ड पर लगाएं, लेकिन चौथी वकैन्सी नही निकाली जाती । चार की जगह तीन वकैन्सीज निकालते हैं और तीनों जनरल पूल से लिए जाते है और इसका नतीजा यह होता है षिय जो हरिजन कैन्डीडेट होते हैं, या तोवे

आगे प्रमोट नहीं होते या लिए नहीं जाते और अगर लिए जाते हैं, तोवे प्रमोट नहीं होते । इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रही है उसको हटाया जाए और जहां पर तीन पोस्टें निकलती हैं, वहां पर चार वकैन्सीज निकाली जानी चाहिए और हरिजनों को जरुर नौकरी मिलनी चाहिए । यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी बात है । हमारे जो हरिजन तथा बैकवर्ड क्लासिज के भाई हैं, उनको नौकरी अवश्य दे'। जानी चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा 'कि इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए –– (व्यवधान) – चेयरमैन साहब, बजट सैशन में अपोजीशन से लेकर टेरजरी बैचिज' तक तीन आदमियों को टाईम मिला है । हरिजनों के 'तिरा ज्यादा से ज्यादा टाईम देना चाहिए । हम लोग तो रिजर्वेशन के आधार पर चुनकर आए हैं (व्यवधान)। इसके साथ–साथ चेयरमैन साहब, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस निगम का जो पिछला पैसा था, वह हरिजनों पर खर्च होना चाहिए था । चेयरमैन साहब, उस निगम का पांच लाख रुपया गैर हरिजनों में हिसार में बांटा गया और उसकी आज तक कोई इनक्वायरी नही की गई । यह गवर्नमैंट की जिम्मेदारी है कि जो हरिजनों का पैसा है, हरिजन कल्याण निगम का पैसा है, वह सिर्फ हरिजनों के पर खर्च किया जाना चाहिए । वह पांच लाख रुपया श्री गुलाब सिंह जैन जैसे आदमी जो हिसार के हैं, मैं अर्ज करूंगा कि वह तमाम पैसा उनसे वसूल किया जाए

। चाहे उनकी वुड़की की जाए, और वह पैसा उनसे वसूल करके हरिजनों में बांटा जाना चाहिए । जहां जमींदार के लिए, किसान के लिए सरकार सब कुछ कर रही है, उसका आबियाना भी माफ कर दिया, हर प्रकार की फैसेलिटीज देने के लिए सरकार ने मान लिया है तो हरिजन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसा यह सरकार खर्च करे । जितना ज्यादा पैसा उन पर खर्च किया जाएगा, उतना ही वे लोग पर उठसकेंगे । चौधरी बंसी लाल ने हरिजनों को बेदखल कर दिया था और 1973 में चौधरी चांद राम के नेतृत्व में हमारी एक संधर्ष समिति बनी. थी और आज के मुख्य मन्त्री उस समय हमारे साथ थे और हरिजनों के 28 हजार मर्द और औरते जेलों में गए थे । 13 औरतों ने बच्चे जनमे और 1 4 आदमी मृत्यु के शिकार हुए थे ।

तो चेयरमैन साहब, यह डिमांड हमने उस समय सरकार के सामने रखी थी तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह डिमांड इम्पलीमैंट करवाई जाए । और इस तरह से जो हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है वह दूर करवाया जाए और हरिजनों को हर पहलू में पूरी रिजर्वेशन दिलवाई जाए । चेयरमैन साहब, है इस सदन का ध्यान सैन्टर के ट्रांसपोर्ट और शिपिंग विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पहले वहां पर हरिजनों के लिए रिजर्वेशन पूरी नहीं थी और जब से पूज्यनीय **चौधरी** चांद राम जी वहां गए हैं, हरिजनो के लिए पूरी रिजर्वेशन करवाई गई है और उन्होंने आर्डर भी भेजे हैं जो कि इस बात का संकेत है–– (विध्न) –

श्री सभापति : चौधरी साहब, आप यहां सैन्टर की स्कीमों को डिस्कस न कीजिए, वजट पर ही बोलें ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : तो चेयरमैन साहब, जब तक सर्विसिज में हमारी रिजर्वेशन पूरी नहीं होती तब तक हरिजनों –च लिए 40 परसैन्ट का भर्ती का कोटा मुकर्रर किया जाए और फिर जब यह हाउस चाहे, कोटा पूरा होने के बाद बेशक सरकार 20 परसैन्ट पर आ जाएं । इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, मैं किसानो के लिए, जमीदारों के लिए व्यव धान)

श्री सभापति : आप एक ही सबजैक्ट को रिपीट न करे ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : चेयरमैन साहब, किसानों और गरीब मजदूरों के लिए जो पैसा सरकार ने रखा है, उसकी मुझे बहुत खुशी है कि सरकार गरीब किसान भाईयों की तरफ ध्यान दे रही हुऐ । जो किसान अपनी मेहनत करके, सारे देश का पेट पालता है, बड़े दुख की बात है कि उसके तन पर कपड़ा भी नहीं है, लेकिन आज जो कदम सरकार ने उस किसान की खुशहाली के लिए उठाए हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं और अपील करता हूं अपनी जनता सरकार से कि जो पैसा किसानों की भलाई के लिए इस बजट में रखा गया है वह पैसा किसानों के लाभ के लिए ही खर्च किया जाए । चौयरमैन साहब., पिछली सरकार के वक्त में क्या होता था, भेदभाव की नीति बरती जाता थी उस खरवार ने

चोर को कहा ''लाग, शाह को कहा जाग'' । एक तरफ तो हरिजनों को यह कह दिया कि आपको जमीन मिलेगी और दूसरी तरफ जमींदारों को यह कह दिया कि तुम्हारी से जमीन खुसने वाली है । इस तरह से पिछली सर– कार ने जो भी काम किया वह आपस में फूट डालने का ही किया । गरीब हरिजनों और जमींदारों को आपस में लडाती रही । इसलिए आज. जनता पार्टी सरकार को चाहिए कि वह किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ न बरते । पहले हरिजन भाई 10–20 हजार रुपया कर्जा लेकर अपना काम संवार लेते थे पर पिछली कांग्रेस सरकार ऐसे कानून बना गई कि अब कोई इन पर एतबार नहीं करता । आपको पता है कि चेयरमैन साहब इस वक्त 83 परसैन्ट लोग गांवों में रहते है, इसलिए आप कोई ऐसा कदम उठाए, कि जिससे इनको आपस में मिलने का अखिकार प्राप्त हो, और इनके साथ कोई भेदभाव की नीति न अपनाई जाए, ताकि गरीब लोगों को हर प्रकाररू की सुविधा प्राप्त हो और वे सुख का सांस ले सकें । इसके साथ–साथ मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा कि अगर हमारी हरियाणा सरकार तरक्की करना चाहती है, अगर प्रगति के पथ पर आगे जाने को तत्पर है, तो इन लोगों के हितों का पूरा पूरा ध्यान करे–– (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी स्पीच करते हुए समय का भी श्यान रखें ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : अन्त में चेयरमैन साहब, यह कहूंगा कि हरियाणा में नशाबन्दी कानून शीघ्र ही लागू किया जाए, क्योंकि लोग शराब पीकर लड़ाई करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी बरबादी हो रही है, इसलिए शराब पर जो डयूटी 10 परसैन्ट है, उसको बढ़ाकर 50 परसैन्ट कर दी जाए ताकि जिस किसी को भी शराब लेनी हो, वह जरा सोच समझ कर चले । इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (तोशाम) : सभापति जी, पिछले आम चुनाव में लोकसभा में और हरियाणा विधान सभा के चनाबों में, जिस उम्मीद के साथ उगम जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने जनता पार्टी के हाथ में राजसत्ता सौप दी है, उसको देखते हुए आज इस बजट से यह महसूस होता है कि आज चौधरी देवी लाल, जो कि अरस्टवाईल पंजाब में भी यह दावा करते थे कि वे किसानों के, गरीब मजदूरों के नेता हैं चाहे सरदार प्रताप सिंह कैरों का रजि है, चाहे कामरेड रामकृष्ण का राज है, वे हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं आम आदमी के लिए लड़ता हूं लेकिन आज जब उनके हाथ में ताकत आई तो उन्होंने सारी कलम किसान पूर तोड़ दी । अभी मेरे भाई श्री गंगाराम ने भी बोलते हुए कहा कि जो वायदे इस जनता सरकार ने अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में किसान और मजदूरों की भलाई के लिए किए थे, वे वायदे आज कहां गए? (मुख्य संसदीय सचिव, श्री जगन्नाथ की

ओर से विध्न) । चेयरमैन साहब, मैं श्री जगन्नाथ जीसे प्रार्थना करूंगा कि वह आराम से सुनें । सभापति महोदय, हमारे कई भाईयों ने यहां पर पिछली कांग्रेस सरकार की चर्चा की और साथ में यह भी कहा गया कि पिछले तीस सालों में कांग्रेस ने हिन्दुस्तान का भट्टा बिठा दिया है, मैं चौधरी देवी लाल और दूसरे साथियों से पूछना चाहता हूं कि वे जनता पार्टी में कब से आए और कब से काग्रेंस में थे । मेरे भाई यह भूल गए कि वे कांग्रेस का प्लेट फार्म ही लगाते रहे हैं और वही से भाषण देते रहे हें और आज वह कांग्रेस पार्टी उनकी नजरों में बुरी हो गई।

एक आवाज : चेयरमैन साहब, चौधरी सुरेन्द्र सिंह किस पर बोल रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं 0 2 पर बोल रहा हूं जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की है । पिछले साल एमरजेंसी के वक्त तो यहां तक कहा जाता रहा है कि दिल्ली में तो श्री संजय गांधी एडमिनिस्टेरशन चलाता है और हरियाणा में सुरेन्द्र सिंह का नाम लिया जाता था । पर मैं चौधरी देवी लाल को और अपने भाईयों को यह बता देता हूं कि चौधरी बंसी लाल और चौधरी देवीलाल में लड़ाई इसी बात पर थी कि वे किसी की भी नहीं मानते थे, चाहे वह चौधरी देवी लाल है चाहे सुरेन्द्र सिंह है । लेकिन आज जनतापार्टी का राज है और **चौधरी** देवी लाल मुख्य मन्त्री हैं ..... (विध्न एवं शोर)..... (शोर एवं व्यवधान)..

श्री सभापति : अब आप अपनी स्पीच वाईड अप करें.. (शोर)..

चौधरी संत कंवर : चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि **चौधरी** सुरेन्द्र सिंह कहते थे कि मैं डिमांड नं0 2 पर बोल रहा हूं जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है । आप इनको कहें कि यह जनता पार्टी पर अटैक न करे, क्योंकि यह पोलिटीकल पार्टी है, पोलिटीकल पार्टीज का यहां पर जिकर नहीं आना चाहिए । यह अपनी डिमांड पर ही बोलें (शोर)

Shri Surrender Singh : I will not touch any political party. Take it for granted. मैं किसी राजनीतिक पार्टी की चर्चा नही करूंगा – (विघ्न)– क्या मेरे लायक दोस्त उस बात को भूल गए कि

श्री लछमन सिंह : चौयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है.

Mr. Chairman : There is another point of order. Please take your seat. आप बैठिए, उनका प्वांयट आफ आर्डर है ।

श्री लछमन सिंह : चेयरमैन साहब, इन्हेंने कहा कि ....He is neither a member of the HOUse nor a Minister nor he is present in the House.इसलिए ये लफज जो हैं ये हाउस की

प्रोसिडिंग्ज से एक्सपंज होने चाहिएं, क्योंकि जो आदमी हाउस में हाजिर नहीं है उसके खिलाफ –छ नही कहा जा सकता ।

Mr. Chairman : Please do not refer to the people who are not present in the House.

Shri Surerrnder Singh : It will not be repeated.

Mr. Chairman : Correct.

श्री सुरेन्द्र सिंह : लेकिन आज मेरे लायक दोस्त को बड़ा याद आया कि किसी पार्टी की चर्चा न करो । क्या यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नही है कि एक पार्टी जो चन्दा इकट्ठा करती थी उस पर तो केस रजिस्टर कर दो बगैर किसी आदमी की या पार्टी की शिकायत के और इस बारे में एक पुलिस कप्तान की तरफ से शिकायत आए ।.....

Mr. Chairman : Please do not make it a personal debate. **I** will request the Hon. member to remain within the scope of the Debate.

Shri Surrender Singh : I will not

Mr. Chairman : Please take your seat. There is a point of Order by the Chief Minister.

मुख्य मंत्री (चौ धरी देवी लाल) : चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है...

Mr. Chairman : Please take your seat. There is a point of Order by the Chief Minister.

चौधरी देवी लाल : चेयरमैन साहब, यहां इल्जाम लगाया गया है आठ लाख रुपया इकट्ठा करने का । यह पहले भी लगाया गया था जिसके लिए मैंने लैटर लिखा था कि जो आठ लाख रुपए हैं, उसकी लिस्ट दी जाए ताकि मैं उसका जवाब दे सकू । **चौधरी** चरण सिंह जी को सिर्फ 73 हजार रुपए दिए गए थे । चेयरमैन साहब, दो दो लाख रुपए जेब में डालकर मैं कभी नहीं गया और न कभी मेरे लड़के गए हैं, और वह दो लाख तो ये मानते हैं और हालांकि यूथ कांग्रेस के हिसाब में वह जमा नहीं है ।

(इस समय **चौधरी** सुरेन्द्र सिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Chairman : Before you start, I will make an observation. Please take your seat.

(इस समय श्री दीप चन्द भाटिया बोलने के लिए खड़े हुए) मि0 भाटिया आप बैठिए, पहले उनका जवाब आने दीजिए । पहले सी0एम0 साहब के प्वांयट आफ आर्डर का जवाब आने दीजिए । आप बैठिए? देखिए– (शोर) – (इस समय चौधरी सुरेन्द्र सिंह बोलने के लिए खड़े हुए ।) Please take you seat. I have not given my ruling on the Point of Order raised by the Chief Minister. —(Interruptions)—देखिए, समय का ख्याल रखिए, साढ़े पांच बजे मिनिस्टर साहब ने बोलना है । Wild allegations, without any foundations, should not be levelled

against any body personally, and I wish you do not do anything 'of that sort. Those allegations should be expunged.

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मैं चौधरी देवी लाल जी के व्यक्तित्व केबारे में कोई निजी बात नहीं कहूंगा । लेकिन जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है मैं एक एफ0आई0आर0 का नम्बर बताता हूं वह चौधरी देवी लाल के बारे में नहीं है – (विघ्न)– गवर्नमैंट का पैसा टेरयरी से निकलवा कर खाया गया और वह पैसा विद्ड्रा कर लिया गया । चीफ मिनिस्टर साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वह अपनी स्पीच में, जवाब में एफ 0आई 0आर 0 नं. 251...

Mr. Chairman : F.I.R. is a subjudice matter. If it is pending in the court, please do not refer to it. — (interruptions)—

Shri Surrender Singh : It is not a sub-judice matter. It is not .pending in the court.

Mr. Chairman : Is it not pending in the court ?

Shri Surrender Singh : Not at all. The case has been withdrawn. Mr. Chairman : Then it is alright.

Mr. Chairman : Then it is alright.

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, एफ0आई0आर0 251 डेटिड 1–6–7 6 अंडर सैक्शन 42 0, 45 6, 1 20– बी कंसरनिंग पुलिस स्टेशन भिवानी । टेरयरी में पैसा जमा था और जिसकी जमीन एक्वायर हुई, उस आदमी को नही मिला । एक वकील ने

तथा उसके दूसरे साथी ने कांस– पीरेसी सेबोगस दस्तखत करके टेरयरी से पैसा निकलवा लिया और उस आदमी के खिलाफ केस विद्ड्रा कर लिया What is the politics in it ?

श्री सभापति : आप वाइंड अप करने की पालिटिक्स में आएं ।

श्री सुरेन्ह सिंह : चेयरमैन साहब, मैं इस सदन में वह बात नहीं कहूंगा । वे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हें.....

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : प्रताप सिंह चौधरी देवी लाल जी के लड़के हैं, उन्होंने चुटाला में एक लैण्ड स्कैण्डल बताया । उन्होंने वहां के पब्लिक हैल्थ डिपाटन्मैंट के बारे में बताया । क्या जवाब है? चीफ मिनिस्टर के बारे में उनके लड़के से ज्यादा कौन जानता है और क्या स्टेट– भैंट थी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन था– (शोर) – चेयरमैन साहब, एडवाइजर लगाए गए हैं । एडवाइजर किस लिए? चीफ मिनिस्टर साहब को सलाह देने के लिए । क्या चीफ मिनिस्टर के पास दूसरे अपने वजीर अवेलेबल नहीं हैं, क्या चीफ सैक्रेटरी, दूसरें कमीशनर या सैक्रेटरी या हैड आफ दी डिपार्टमैंट अवेलेबल नहीं है और पुलिस डिपार्टमैंट का जनक राज जो लगाया है, चेयरमैन साहब, हाई कोर्ट में केस....

Mr. Chairman : Please do not refer to the people who are not present in the House. Please wind up now.

Shri Surrender Singh : They are very much part and parcel of the administration.

श्री सभापति : अब आप वाईंड अप करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं वाईड अप कर रहा हूं । चेयरमैन साहब, मैं इरीगेशन के बारे में दो बातें कहूंगा । पिछले दिनों

श्री सभापति : आप एक मिनट में खत्म करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, न मुझे बजट पर बोलने का टाईम मिला और न ही गवर्नर एड्रैस पर टाईम मिला ।

श्री सभापति : अब आपको टाईम मिला है तो you are wasting it.

श्री सुरेन्द्र सिंह : (शोर) आप अगर कहें तो मैं सारी बातें बता दूं लेकिन (शोर) लेकिन चेयरमैन साहब, पिछले दिनों रोहतक से हमारे चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी का ब्यान ट्रिब्यून में आया कि लिपट इरीगेशन स्कीम बिल्कुल बेकार बना दी गई है लेकिन अच्छी बात है वजीर सहिब ने (शोर एवं विध्न) आप यह भी कहते हैं, आप इस बात से नाटते है (शोर) लेकिन चेयरमैन साहब, मुझे खेद इस बात का है कि जो भिवानी जिले के लिए पैसा मंजूर किया गया है.....

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है

Mr. Chairman : Mr. Surrinder Singh, if you touch those controversies, there will be points of Order.

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, सुरेन्द्र सिंह जी को तीन मिनट अलाट हुए थे और ये सात मिनट ले चुके हैं इसलिए अब आप इनको बैठने के लिए कहें ।

श्री सभापति : मिस्टर सुरेन्द्र सिंह, आप फौरन वाईंड अप करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमन साहब, हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने पिछले दिनों सदन. में एक ब्यान दिया थाकि जो यह.....

श्री सभापति : आप जल्दी खत्म कीजिए, जो भी आपने कहना है, जल्दी कहें ।

Shri Shamsher Singh : He himself had taken more than 15 minutes.

Mr. Chairman : At that time there was no time limit.

श्री सुरेन्द्र सिंह : चौयरमैन साहब, हाउस के लीडर बैठे हैं, मिनिस्टर्ज बैठे हैं । They will extend the time.

Mr. Chairman : Guillotine is to be applied. The time cannot be extended.

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मै दरख्वास्त करूंगा कि चौधरी देवी लाल जी को याद होगा, कि ज्वांयट पंजाब के वक्त एक फ्लड कमेटी बनी थी और उसने यह फैसला लिया था कि जो रावी व्यास का टोटल पानी 7. 2 मिलियन एकड़ फीट आएगा, उसमें से हरियाणा को 4. 58 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए । उसके बाद जो एक हरियाणा डिवैल्पमैंट कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन पंडित श्री राम शर्मा थे जो कि आज विजीलेंस कमेटी के चेयरमैन हैं । उस कमेटी ने यह रिपोर्ट इसके. .....

Mr. Chairman : Again you are making a reference to a person who is not present here. You are making remarks

Shri Surrender Singh : Not allegations. The Chief Minister knows this fact.

Mr. Chairman : Please finish your speech within a minute.

श्री सुरेन्द्र सिंह : ठीक है जी । उसके बाद जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए (विघन)– उसके पहले तो यूनाइटिड पंजाब की असेंबली का सैशन था उसमें उस वक्त के गवर्नर के एड्रैस में और चीफ मिनिस्टर ने इस बात को मैन्शन किया था कि इस फैसले को हमकंसीडर करेंगे और यह ज्यादा पानी हरियाणा को मिलेगा । लेकिन वह फैसला जो उस वक्त की हमारी प्रधान मन्त्री ने दिया उसके पर आज पंजाब में कई तरह की स्टेटमैंट्स आती हैं । वे कहते हैं कि हम हरियाणा से ज्यादा पानी

लेंगे । जो 3. 5 मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा को मिला है वह इतना पानी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए । चेयरमैन साहब, मैं आज. इस सदन में एक बात कहूंगा कि परसों जब चौधरी देवी लाल जी बोल रहे थे तो ये बड़े मेज थपथपा कर कह रहे थेकि उस वक्त जो इन्दिरा जी के नजदीक होने का दावा करते थे वे उस वक्त इतना पैसा किसान के लिए और पानी के लिए खर्च न कर सके जितना मैं करने जा रहा हूं । अगर ये इस डायरी में से फिगर उठा कर देख लें तो हरियाणा बनने के बाद जितना पैसा किसानों पर, नहरों पर उस वक्त खर्च हुआ अगर उससे आधा पैसा ये अपनी स्कीम के दौरान खर्च कर लेंगे, तो हम मान जाएंगे । – (विध्न)–– चेयरमैन साहब, एक बात मैं भिवानी जिले के बारे में कहना चाहता हूं

श्री सभापति : अब आपका टाईम हो चुका है, आप अपनी सीट लीजिए । भिवानी के बारे में तो बहुत कुछ आ चुका है ।

(At this stage Shri Surrender Singh resumed his seat)

Mr. Chairman : The Finance Minister.

(At this stage, several hon. Members rose to speak)

Mr. Chairman : I have now called upon the Finance Minister to reply to the debate.

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, आज हमारे साथियों ने डिमाण्ड्ज पर काफी कुछ बोला है और वे आमतौर पर वही बातें हैं जो बजट स्पीच पर कहीं थीं । मैंने काफी बातों का जवाब उस वक्त दे दिया था । लेकिन आज डिमाण्ड्ज पर बोलते हुहु सबसे पहले राव दलीप सिंह जी ने ओलों का जिक्र किया । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि ओलों से जिन फसलों का नुक्सान हुआ है सरकार उससे बहुत चिन्तित हे, बहुत दुखी है, लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नही चलता । जो कुछ भी सरकार कर सकती थी उसके बारे में हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने इस हाउस में ऐलान किया और वह पालिसी जो मुख्य मन्त्री जी ने हाउस के समक्ष रखी कि प्रति एकड़ 100 रुपया लोन, फर्टीलाईजर पर सबसिडी और ट्रैक्टरों के लिए राहत देने का सरकार ने फैसला किया है । इसके अलावा राव साहब ने दूसरी बात यह कही कि तम्बाकू के पर से सैन्ट्रल एक्साईज डयूटी खत्म कर दी जाए । चेयरमैन साहब, यह मामला सैन्ट्रल गवर्नमैंट का है, राज्य सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती । इन्होंने गवर्नमैंट एम्पलाईज को एडीशनल डी0ए 0 देने के बारे में कहा । एक किश्त तो बजट में अनाउंस कर दी, जिसको देने का सरकार ने फैसला किया है । इसके अलावा इन्होंने दो बैंकों को मर्ज करने की बात कही । मैं कहना चाहूंगा किइस मर्जर से ज्यादा फायदा होने वाली बात नही है । दोनों बैक अच्छी तरह से किसान की सेवा करते हैं, गांव के लोग ज्यादा लोन वसूल कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो

रहा है । इन्होंने एक खास बात कही कि अहीर शिक्षा संस्था ओं को ग्रान्ट्स नही दी जा रही हैं । यह गलत एलीगेशन है । सरकार की नजरों में सब एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन्ज बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । इन–कोइस बात का गिला नही करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मन्त्री कर्नल साहब अहीर हैं, वे सब का ख्याल रखते हैं । हां, यह बात जरुर है कि ठेके– दार बनने का जो काम था, वह खत्म कर दिया गया है । सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ठेकेदार है, जो मैनेजमैंट में हेराफेरी करते थे, उनसे शिक्षा संस्थाओं को दूर रखा जाए । बी 0एड0 के दाखले में हजारों रुपया लिया जाता था । बहुत सारी संस्थाएं लुट जाया करती थीं और सरकार ने निर्णय लिया है कि यह लूट अब नहीं चलने दी जाएगी.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । चेयरमैन साहब, ये पर्सनल अटैक न करें । इन्होंने लूट का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया है (हंसी) –

श्री सभापति : आप बैठ जाइए ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : चेयरमैन साहब, इसके बाद इन्होंने फलैट रेट सिस्टम की बात कही । मुख्य मन्त्री जी इस सदन में अनाउंस कर चुके हैं कि जनता पार्टी की सरकार जल्दी ही फलैट सिस्टम जारी करेगी । इसके साथ ही साथ इन्होंने लेबर की बात कही कि हिसार टैक्सटाईल मिल और सोनीपत में लेबर

ट्रबल है । इस सम्बन्ध में मैंने बजट स्पीच में सदन के अन्दर कहा था कि इससे पहले मिलों में वातावरण घुटा घुटा था, लेबर की जबान पर पट्टियां बंधी हुई थीं और जब जनता पार्टी का राज आया तो देश को प्रजातन्त्र के अन्दर अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिला और मुंह पर बन्धी पट्टियां खुलीं । उनके अधिकतर मसले हल हो गए । चेयरमैन साहब, मजदूर की जो दबी हुई आवाज थी, वह जनता पार्टी के राज में बाहर आई और इन्होंने मैनेजमैंट से अपने हक मांगने शुरू कर दिए । जहां तक दादरी का ताल्लुक है, यहां पुरानी सरकार का खराब किया हुआ मामला है । डालमिया पुरानी सरकार के चेले चांटे थे, इसने मजदूरों को लूट लिया । सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मिल को दोबारा चलाया जाए, मिल को राहत दी जाए, जिससे मजदूरों को अपने हक मिलें । इस सिलसिले में जिस वक्त पार्लियामैंट में क्वैश्चन आया था तो हमने स्पष्ट कहा था कि मजदूर को बोनस देना पड़ेगा, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है, बोनस दिलवाया जाएगा । जहां तक टैक्सटाईल का मामला है, वहां 4 यूनियनें हैं और एक यूनियन के 35 आदमी हैं, उन का लाल झंडा है । 35 आदमियों में एक नौजवान है जो वहां हड़ताल किए बैठे हैं । म्युनि– सिपल कमेटियों के इलैक्शन आ रहे हैं और वह चाहता है कि म्युनिसिपल कमेटी का इलैक्शन लडू कारखाने के अन्दर पांच छरू हजार लेबर काम कर रही है और वह भूख हड़ताल करके, अपने स्वार्थ केलिए बैठे हुए हैं । जहां तक ला एंड आर्डर का ताल्लुक है, सोनीपत में ला एंड आर्डर पूरी तरह से ठीक है, एक

भी फैक्ट्री क्लोज नहीं है, कोई स्ट्राइक नही है । मैं अपने साथी' को एकही बात कहना चाहूंगा कि कानून को जो व्यक्ति अपने हुइ में लेगा, चाहिए वह मुख्य मन्त्री हो, चाहे मन्त्री हो, चाहे लेबर हो, चाहे बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं । गोली का जहां तक ताल्लुक है, कानून के मुताबिक केस रजिस्टर करवाए हैं, छानबीन हो रही है, सच और झूठ का अदालत में पता लगेगा । यह मामला सब– जुडिस है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सच और झूठ का पता अदालत में लग जाएगा । श्री देवेन्द्र शर्मा ने एक बात कही कि शराब बन्दी होनी चाहिए । नशाबन्दी की बाबत तकरीबन सब साथियों ने कहा है । जहां तक नशाबन्दी का ताल्लुक है, हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसने नार्दन इण्डिया के तमाम एक्साईज मिनिस्टर्ज को बुलाकर कहा कि हम प्रोहिबिशन की तरफ कदम उठा रहे हैं । हरियाणा ने सबसे पहले पहल की है । इस पालिसी के तहत हरियाणा राज्य सब राज्यों से आगे है । हम 2 अक्तूबर को ताडू और चुटाला का 8– 8 मील का एरिया पहले ही सूखा घोषित कर चुके हैं । इसके अलावा सदन के अन्दर आश्वासन दिया गया था कि गांव की जो पंचायतें रैजोल्यूशन पास करके भेजेगी, हम उन के गांवों में शराब के ठेके नहीं खोलेंगे । चेयरमैन साहब, इस भावना से प्रेरित होकर 145 रैजोल्यूशन आए, जिन में से 120 का हमने फैसला कर दिया है । 120 गांवों में जहां पहले ठेके खुले हुए थे, वहां ठेके नहीं खोले जाएंगे । जहां पहले खुले हुए नही थे, वहां भी नहीं खोलेंगे । इसके साथ ही साथ हमने शराब की

डियूटी इनक्रीज करदी है, 10 परसैन्ट से 20 परसैन्ट कर दी है । देसी शराब जो इनके जमाने में 8 रुपए की बोतल बिकती थी, वह 1 4 रु पए में बिका करेगी, हमने इसको 8 रुपए से 1 4 रुपए कर दिया है । इसके अलावा जो ठेका 5 हजार में नीलाम करते थे, उसकी लिमिट 20 हजार बढ़ा तक दी है । इससे साफ जाहिर है कि जनता पार्टी की सरकार प्रोहिबिशन की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का आदेश है, उसको चार साल के अन्दर पूरा करने की कोशिश करेंगे और हरियाणा को सबसे पहली प्रोहिबिशन वाली स्टेट घोषित किया जा सकेगा । चेयरमैन साहब, पहले जो ठेके की बोली हुआ करती थी, हरियाणा सरकार ने लाईसेंस सिस्टम से ठेके बेचने का फैसला किया है । पहले कोयले के ठेकेदार हुआ करते थे, कोयले की वैगन कोई लेता था और बेचता कोई दूसरा था । इसी तरह से शराब के ठेकों में हुआ करता था । शराब का ठेका कोई लेता था और शराब कोई बेचता था । सिर्फ दो चार पांच आदमी ही हरियाणा में ठेका लेते थे, और सब स्टेशन बनाकर, शराब बेचकर लाखों रुपया कमाया करते थे । जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने की नीयत से फैसला किया. है कि देसी शराब और अंग्रेजी शराब के लाईसेसं दिए जाए और इससे सरकार की आमदनी भी ज्यादा बढ़ेगी । कांग्रेस के जमाने में जो ठेकेदार शराब में इलिसिट डिस्टिलेशन करके लोगों का खन चूसा करते थे, उनको खत्म किया जाए और यह निर्णय लिया है और लाईसेंस सिस्टम से ठेके बेचने का फैसला किया है ।

चेयरमैन साहब, देवेन्द्र शर्मा जी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बाबत काफी कुछ कहा । यूनिवसिटी एक आटोनोमस बाडी होती है और सरकार का उसमें कोई दखल नहीं होता । इसके अलावा जो बातें उन्होंने कहीं हैंय उनका जवाब मैं दे देता हूं । उन्होंने कहा कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के पर ज्यादा खर्च –करती है और बहुत सी फजूलखुची हो रही है । चेयरमैन साहब, हमारे नोटिस में तो कोई ऐसी बात नही है कि कोई विलासिता से रह रहा है । अगर इनके नोटिस में कोई बात हो, तो ये हमारे नोटिस में लाए उस पर हम जरूर ध्यान देंगे । हमारी सरकार तो सादगी के अन्दर विश्वास रखती है । मुख्य मन्त्री जी खुद सादे हैं । वे चाहते हैं कि हमारी सरकार का जितना भी अमला है, अधिकारी हैं, वे भी सादगी से रहें । इसके बाद उन्होंने ट्रांसफर पालिसी का जिक्र किया । चेयरमैन साहब, अभी तक तो हमारी कोई ट्रांसफर पालिसी बनी ही नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी ने जब सत्ता सम्भाली तो फ्लड आ गया । सारी सरकार, मुख्य मन्त्री से लेकर मन्त्रीगण और अधिकारीगण तक उस काम में लग गए । उससे जब निपटारा हुआ तो ट्रांसफर्ज का सीजन नहीं रहा । ट्रांसफर की नीति तो अब बनेगी । अभी तक अगर कुछ ट्रांसफर्ज हुई हैं, तो वे कम्पलेंट बेसिज पर या एडमिनिस्टेर– टब बेसिज पर हुई हैं । फिर उन्होंने कहा कि प्रमोशन्ज गलत ढंग से होती हैं । इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को यही कह सकता हूं कि अगर कोई कानून के खिलाफ प्रमोशन हुई है, तो वे उसे सरकार के नोटिस में लाएं । प्रमोशन के बारे में तो चेयरमैन साहब मुख्य

माली जी या कोई दूसरा आदमी दखल नहीं दे सकता । उसके लिए सैट लाज हैं । उस आदमी के दस साल पिछले सी0आरज ठीक होने चाहिएं, उसका सीनियोरिटी में नम्बर होना चाहिए, उस का काम ठीक होना चाहिए । प्रोमोशन से पहले ये सब बातें देखी जाती हैं । कोई भी आदमी इनसे दूर नहीं जा सकता । शायद किसी ने इनसे गलत बात कही हो । चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट री–आर्गेनाइजेशन की बात भी उन्होंने कही । मैं हाउस को आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं और पहले भी यह बात कई बार यहां कही जा चुकी है कि यह मामला कमेटी के विचाराधीन है । अभी तक कोई फाईनल फैसला नही हुआ है । जो कुछ भी किया जाएगा, वह हरियाणा के हित में किया जाएगा । पुरानी सरकार की तरह हम नही करेंगे कि गांव तो हिसार के अन्दर लेकिन मिला दिया भिवानी से, और गांव तो भिवानी के अन्दर लोइक्रून जोड़ दिया हिसार के साथ । चेयरमैन साहब, जो भी सरकार करेगी, लोगो की सलाह से करेगी । मुख्य मन्त्री जी ने सरेआम कहा है कि जो भी कार्य होगा लोगों के हित के अंदर किया जाएगा । स्पोर्टस की बाबत भी चेयरमैन साहब उन्होंने एक बात कही । इस सम्बन्ध में मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टेट लेवल पर एक स्पोर्टस काउंसिल कायम की जाएगी । ऐसा लगता है कि उन्होंने बजट को देखने या पढ्ने की कोशिश नहीं की । स्पोर्टस के लिए तो इस साल के बजट में पिछले साल से ज्यादा पैसा रखा गया है ।

चेयरमैन साहब, चौधरी गंगा राम जी ने फामर्ज के लिए कहा कि सरकार को इनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए । मैं अपने माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हुं कि अगर वे बजट को श्वान से पढ़े' तो उन्हें मालूम होगा कि बजट का लगभग 75 प्रतिशत भाग किसानों के लिए खर्च होगा, चाहे वह खर्च पानी के पर है, चाहे बिजली के पर है, चाहे खाद की सब– सिडी के पर है या किसी और चीज के पर है । इससे चेयरमैन साहब साफ जाहिर होता है कि यह सरकार किसान और मजदूर की सरकार है । यह उनके हितों की रक्षक है । जिस दिन पानी का इन्तजाम पूरा हो जाएगा, फ्लड से छुटकारा हो जाएगा, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लग जाएंगीं तथा अन्य स्कीमें, जिनको जनता पार्टी की बहू सरकार कार्यान्वित करनें जा रही है, जब पूरी हो जाएंगीं, उस दिन ये देखेंगे कि हरियाणा का देहात किस कदर खुशहाल होगा ।

चेयरमैन साहब, मंगला साहब ने वनों के बाबत कुछ जिक्र किया । उन्होंने जो सुझाव दिया कि फलदार वृक्ष लगाए जाएं, उसको हम ध्यान में रखेंगे । सफेदे के वृक्ष के बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमें तो ऐसा बताया जाता है कि यह वृक्ष इंडस्ट्री के अन्दर काम आता है, यह बहुत जल्दी तैयार होता है, फसलों को नुक्सान नहीं पहुंचाता, कोई शौर बुराई वाली बात इसमें नही है, जिससे कोई बीमार लगती हो, बल्कि इसके फायदे ही है ।

डाक्टर बृजमोहन गुप्ता जी ने हैल्थ सैन्टर्ज केबारे में अपने विचार रखे । उन्होंने ग्रामीण स्वास्थय स्कीम के बारे मेंकहा कि स्चास्थ्य कार्यकर्त्ता को मैडिकल की टैक्नीक लेटीज का और दवाईयों आदि का पता नही होता, लेकिन मैं डाक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि यह ठीक है कि उन्हें कुनीन और ए0 पी0 सी0 आदि की जो मिसालें उन्होंनें दी हैं उनका पूरा पता नहीं होगा, लेकिन गांव के अन्दर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनरल बातें बताने के लिए यह एक अच्छी सेवा रहेगी । हम चाहते हैं कि यह स्कीम सक्सैसफुल हो । लेकिने जिस दिन हमारी सरकार कोयह पत। लग जाएगा कि यह स्कीम ठीक नहीं, इस पर ख्वामख्वाह का खर्चा हो रहा है तो मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी किसी बात पर अडते नहीं, हेम इसको री–कसीडर कर सकते हें । चेयरमैन साहब, उन्होंने सेल्ज टैक्स के फार्मज की भी बात कही । –इसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं यिरू इसके लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो इस बात की जांच कर रही है कि टैक्स स्ट्रक्चर को किस तरह सिम्पलीफाई किया जाए, जिससे व्यापारियों को ज्यादा तकलीफ न हो ।.. (विघ्न).. शराब की बाबत पहले काफी बात हो चुकी है, उसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा ।

चेयरमैन साहब, कांग्रेस के साथियों में से चौधरी शमशेर सिह जी की तरह चौधरी बीरेन्द्र सिह – ने भी कुछ बातें कहीं । जैसे चौधरी शमशेर सिंह जी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए

थे और किसान का नाम लेकर वे यहां बड़े तडपे थे उसी तरह आज बीरेन्द्र सिंह जी का नम्बर आया और वे भी किसान के नाम से बड़े तडपे ।.. (विध्न).. –मैं सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह और बीरेन्द्र सिंह का इकट्ठा जवाब दे रहा हूं । चेयरमैन साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तो वे किसान के लिए तड़पने लगे हैं लेकिन क्या वे वह समय भूल गए, जब किसान जाकर के ईख के अन्दर सोया करता था ? उसकी रजाई कहीं होती थीऔर वह कही होता था और तुम उसके पीछे पीछे रहा करते थे । क्या वह किसान नहीं था? क्या वे किसान के बेटे नही थे जब तुम किसी भाई और बहिन की लिहाज न. करके उन्हें जबरदस्ती नसबन्दी के अहाते में खड़ा कुरते थें? आपके राज के अन्दर बहन को अपने भाई को खाबिन्द कहना पड़ा । (शेम, शेम की आवाजें) –– क्या वे किसान नहीं थे? आज आप किसानों के ठेकेदार बन कर कहते हो कि जनता पार्टी ने किसानों से जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए । (विधनू) मारूति फैक्ट्री के लिए कितने पर बरबाद किए थे, क्या आप इस बात की बताएंगे? क्या आप रिवासा की कहानी भूल गए, पीपली काण्ड भूल गए, नगीना काण्ड भूख गए? उस समय आप कहां गए थे, जब तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए थे? आज. किसान के ठेकेदार बनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती ।.. (विध्न)..

चेयरमैन साहब, बजट से साफ जाहिर है कि जनता पार्टी ने किसान से जो वायदे किए थे, उससे ज्यादा यह किसान के लिए करने जा रही है ।

आज मैं हाउस के अन्दर अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि पिछले सालकी 1 48 करोड रुपए की प्लान थी, परन्तु जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर ज्यादा रुपया खर्च करने के लिए इतनी बड़ी प्लान बनाई जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई थी । जितनी भी हमारी स्कीमज हैं, वे सभी किसानों केलिए है । ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजली और पानी केप्रबन्ध परखर्च करने जा रहे हैं । यह जनता पार्टी की स्कीमज हैं । सभी स्कीमें किसान को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से हैं । हमारी पहली सरकार है जिसने 148 करोड से बढ़ाकर 2.। 0 करोड़ रुपए का प्लान बनाया । आप चाहे सिंचाई को लें, चाहे हैल्थ–विभाग को लें, हर विभाग पर हमने पिछली सरकार से अधिक पैसा खर्चा करने का बजट में प्रोंविजन किया है ।

मेरे साथी इस बात को भूल गए जिस वक्त कांग्रेस का राज था और काफी साथियों को तो पता भी है कि शुगर मिलों के अन्दर गन्ने का क्या भाव हुआ करता था । एक मिल में कुछ होता था तो यमुनानगर के शूगर मिल में अलग ही भाव हुआ करता था । यमुनानगर के मिल मालिक ने एक बार सरकार पर दाब दी तो भाव गिरा दिए जाते थे लेकिन हाउस को यह जानकर खुशी होगी कि जिस तरह से पहले होता था कि दीदे दिखा दिए तो भाव नीचें गिरा दिए जाते थे, लेकिन अब वह बात नही है । पहले तो अपने मन चाहे भाव करवा लेते–थे, लेकिन जब से हमारे मुख्य मन्त्री जी आए हैं, उन्होंने मिल मालिक को कह दिया है कि

आपको किसानों के खून को नही चूसने दिया जाएगा –– (तालियां) वहां के मिल मालिक श्री पुरी की हिम्मत नहीं हुई, वे आज 13 रुपए 50 पैसे का भाव किसानों को दे रहे हैं । यहीं हाउस में हमारे साथी बातें करते हैं कि किसानों के हित की सरकार नहीं है । यह गलत बातें करते हैं ।

चेयरमैन साहब, हरियाणा के लोगों पर आपत्ति आई, फ्लड आया, आप को यह जान कर हैरानी होगी कि हमारे मुख्य मन्त्री साहब जिनकी आयु 65 साल के करीब है, इतनी उम्र के होते भी वे बरसात के अन्दर पानी में गए । देहातों के अन्दर गए । मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को चिट्ठी लिखी गई कि हरियाणा के देहात डूब रहे हैए, आप लोग गांव में जाएं, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । ये लोग अपने हवादार कमरों के अन्दर आराम से बैठे रहे और आज यह लोग बजट के खिलाफ बोल रहे हैं और किसानों के हितैषी बन रहे हैं ।

चेयरमैन साहब, यह जनता पार्टी की सरकार थी जिसने बाढ़ पीड़ितों के लिए इतनी राहत दी । यह हरियाणा के इतिहास में मिसाल रहेगी । हमारे यहां देहातों में लोग यह कहा करते थे

''तूने मेरा कौन सा खेत बहा दिया, हल चला दिया'' । इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तो किसानों के खेतों में हल चलवा दिया, यानी ट्रैक्टर से उनके खेतों को बहवा दिया । यह जनता पार्टी की सरकार है जिसने किसानों के खेतों को

बहाया, बीज दिए, रिजाई दी, खाने के लिए दिया यानी सब चीजों का प्रबन्ध किया।

श्री सभापति : मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि टाईम थोड़ा रह गया है, इसलिए आप अपनी स्पीच खत्म करे ।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : स्वामी आदित्यवेश जी ने शराब के बारे में कहा । वैसे तो इस के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । सरकार की जो भी नीति है, वह पहले ही हाउस में बताई जा चुकी है । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि राजसी ठाठ पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है । अगर आपने बंसी लाल जी का जमाना देखा होता तो उसके राज– सी ठाठ का पता चलता । बंसी लाल जी की कोठी पर एक लाईट घूमा करती थी, अगर उस कोठी पर से कोई पंछी भी गुजर जाए, तो उसको भी कहता था कि मीसा में रोक दूंगा । आज वह घर नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब की कोठी किसानों की धर्मशाला है । यह फर्क है आज के राजसी ठाठ में और उस टाईम के राज–सी ठाठ में । जब से हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी है किसी भी मन्त्री के लिए कोई सोफा या पर्दा नहीं खरीदा गया । जो भी पुराने सोफे या परदे थे, पुरानी सरकार के टाईम पर थे, वे ही वहां पर फिट हैं । हमारे मुख्य मन्त्री जी की सरकार हो, मेरा जैसा फाईनैंस मिनिस्टर हो, खजाने का मालिक हो, तो राजसी ठाठ कहां हो सकेंगे । आज एक–एक पैसा बचाकर हरियाणा की

खुशहाली पर हम खर्च करना चाहते हैं । हम किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं । हमारा किसान मजदूर खुशहाल हो । हम हरियाणा को देश के पहले नम्बर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और हाउस से रिक्वैस्ट करता हूं कि ये डिमाण्ड्ज पास की जाएं ।

18.00 बजे

Mr. Chairman : Now I apply guillotine and put the various Demands and the cut motions to the vote of the House.

(Voices : All the demands be put together)

Mr. Chairman : There are cut motions to various Demands which will have to be put first. Therefore, these demands cannot be put together.

Question is—

That a sum not exceeding Rs. 31,82,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

The motion was carried.

स्वामी आदित्यवेश : चेयरमैन साहब, मैं अपनी सारी कट ध्ध्मोशन्ज वापिस लेता हूं ।

Mr. Chairman : First **I** will put the cut motions by Swami Aditya Vesh to Demand No. 2 to the vote of the House.

Voices : He has already withdrawn all his cut motions to various Demands.

Swami Aditya Vesh : I have already withdrawn all my cut motions.

Mr. Chairman : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his cut motions ?

(Voices : Yes.)

The cut motions were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Now, **I** will put the cut motions by Sarvshri -- Surrinder Singh and Shamsher Singh Surjewala, which are identical, to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-

The cut motion was lost.

Mr. Chairman Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,50,52,260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 2-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion by Swami Aditya Vesh **to** Demand No. 3. Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 14,56,57,480 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 3-Home.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion by Swami Aditya Vesh **to** Demand No. 4. Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,64,74,080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There are cut motions by Swami Aditya Vesh to Demand No. 5. Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the cut motions ?

(Voices : Yes)

The cut motions were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,35,64,580 be granted to the Governor to &fir y the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 5—Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There are cut motions by Swami Aditya Vesh to Demand No. 6. He, has already withdrawn his cut motions. Has he the premission of the House to do so ?

(Voices : Yes.)

The cut motions were by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,87,36,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 6—Finance.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There are cut motions by Swami Aditya Vesh to Demand No. 7.

Has he the leave of the House to withdraw the cut motions ?

(Voices : Yes.)

The cut motions were, by leave of the House, withdrawn. Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,13,75,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There are cut motions by Swami Aditya Vesh **to** Demand No. 8. Has he the leave of the House to withdraw the cut motions ?

(Voices : Yes.)

The cut motions were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum nct exceeding Rs. 28,91,65,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come i n the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion by Swami Aditya Vesh to Demand No. 9.Has he the leave of the House to

withdraw his cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Now **I** will put the cut motion by Shri Surrinder Singh to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The cut motion was lost.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 46,36,76,355 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 IP respect of the charges under Demand No. 9—Education,

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion by Swami Aditya Vesh **to** Demand No. 10. Has he the leave of the House to withdraw the cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is —

That a sum net exceeding Rs. 26,58,87,015 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No, 10—Medical And Public Health,

The motion was carried,

Mr. Chairman : I will put the cut motion by Chaudhri Birinder Singh to Demand No. 11 to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The cut motion was lost.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 79,31,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 11—Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There are no cut motions to Demand Nos. 12 to 15. I will, therefore, put these together.

Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,62,77,235 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 12—Latour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 3,57,07,059 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 94,82,78,000 be granted to the Goverror to defray the charges. that will come in the course of payment for the year 1978-79 in

respect of the charges under Dcmand No. 14—Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 1,24,84,21,230 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 15—Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion to Demand No. 16 by Swami Aditya Vesh . Has he the leave of the Houes to withdraw the cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the House withdrawn.

Mr. Chairman : There is also a 'cut motion to this Demand by Shri Mange Ram Gupta. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The cut motion was lost,

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4.07,95,390 be granted to the Govrnor to defray the charges that will come in the course of payment for the year in respect of the charges under Demand No. 10-Industries.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion to Demand No. 17. by Shri Aditya Vesh. Has he the leave of the House to withdraw the cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 25,13,66,460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course if payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 17—Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There are no cut motions to Demand Nos. 18 to 21. **1** wi!l, therefore, put these together.

Que tion is—

That a su n not exceeding Rs. 5,74,93,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year1978-79 in respect of the charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 55,38,920 be granted to the overnor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 3,19,13,2I0 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year I978-79 in respect of the charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 4,93,28,7I5 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 2I-Community Development.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion by Chaudhri Birinder Singh to Demand No. 22. **I** will put it to the vote of the House.

Quest ion is—

That the demand be reduced by Re. I/-.

The cut motion was lost.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 9,43,42,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 22—Cooperation.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is no cut motion to Demand No. 23. Question is—

That a sum not exceeding Rs. 41,75,72,426 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of Demand No. 23—Transport.

The motion was carried.

Mr. Chairman : There is a cut motion to Demand No. 24 by Swami Aditya Vesh. Has he the leave of the House to withdraw the cut motion ?

(Voices : Yes.)

The cut motion was, by leave of the of House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 13,30,310 be granted tc the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year I978-79 in respect of the charges under Demand No. 24—Tourism.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5I,72,17,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1978-79 in respect of the charges under Demand No. 25—Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Chairman : The House stands *adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 14th March, 1978.

18.07 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 14th March. 1978).